R.N.I. NO.HIN/2002/8718 www.akshnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष 19, अंक-20
16 से 31 जुलाई 2021
पृष्ठ-48
मूल्य 25 रूपये

- प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण की गर्माहट
- केंद्र की राजनीति में बढ़ा मप्र का कद

राजनीति के असली सिकंदर क्षेत्रीय दल

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipment

BC-6800

Auto Hematology Analyzer

Small Cube, Big Difference

mindray

healthcare within reach

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M.: 9329556524, 9329556530 **Email : ascbhopal@gmail.com**

इस अंक में

राजतंत्र

9 | विकास को लगेंगे पंख

मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही मप्र ने भी अपने विकास की डिमांड नए मंत्रियों के सामने रख दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी...

पहल

12 | फिर भी मप्र खुशहाल

मई में जब प्रियजनों के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जद्दोजहद करते लोगों और श्मशानों में लंबी कतारों के मनहूस दृश्य खबरों में छाए थे, कोविड 2.0 चुपचाप कहीं और भी कहर बरपा रहा था...

मप्र भाजपा

15 | माननीयों के बेतुके बोल

अभी हाल ही में भोपाल में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को नसीहत दी गई थी कि वे पार्टी की गरिमा अनुसार कार्य करें और अनाप-शनाप बोलने से बचें।

मप्र कांग्रेस

18 | जमावट में जुटे नाथ

मप्र में भले ही विधानसभा के आम चुनाव होने में अभी दो साल का समय है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से चुनावी किला फतह करने के लिए गुपचुप रूप से तैयारी शुरू कर दी है। यानि जिस तरह की तैयारी भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है लगभग उसी पैटर्न पर कमलनाथ भी संगठन...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

2022 में उप्र सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर से क्षेत्रीय क्षत्रपों और उनकी पार्टी की ताकत का आंकलन करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि भाजपा को इस समय कांग्रेस से नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती से डर लग रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने भाजपा को धूल चटाई है, उससे एक बात तो यह साफ हो गई है कि भारतीय राजनीति में असली सिकंदर क्षेत्रीय पार्टियां हैं।

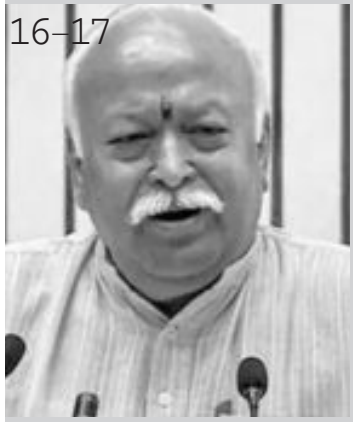

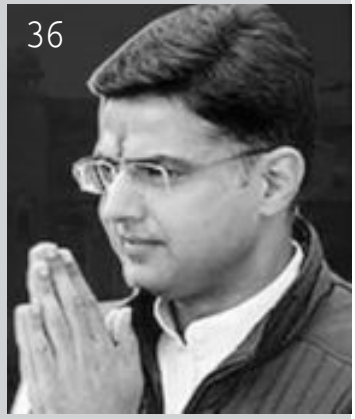

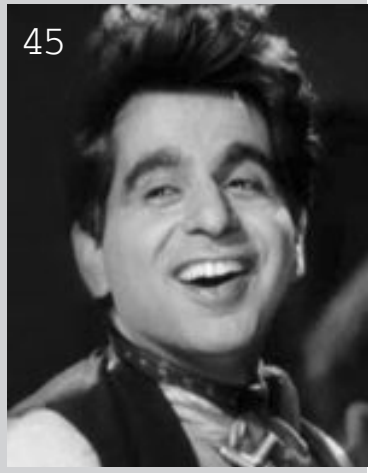

राजनीति

30-31 | राफेल मुद्दा भरेगा उड़ान?

राफेल डील की आग बुझी तो नहीं थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी के मुद्दा बनाने के बावजूद कांग्रेस की हार के साथ ही उसकी लपटें धीमी जरूर पड़ गई थीं। अब एक बार फिर धुआं उठने जरूर लगा है और ये फ्रांस में दिखाई पड़ा है, लेकिन देश की राजनीति में भी कोई असर...

महाराष्ट्र

35 | गठबंधन में कांग्रेस का पेंच

शरद पवार विपक्षी खेमे में मोदी सरकार के खिलाफ चल रही मोर्चेबंदी की धुरी बने हुए हैं। शरद पवार या प्रशांत किशोर के विपक्षी एकजुटता की कवायद से कांग्रेस को अलग रखने की वजह सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं लगते। महाराष्ट्र में उनके करीबी, भरोसेमंद और उनकी नजर...

बिहार

38 | विरासत पर घमासान

चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच छिड़ी विरासत की जंग से बिहार का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग और पशुपति ने अपने-अपने तरीके से इस विरासत पर पकड़ बनाने की कोशिश की।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

स्मार्टसिटी का सिर्फ नाम, हकीकत में नाकाम!

कवि अनवर सुहेल की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं...

ये जगह जो अभी योजनाओं और नीतियों में ले रही आकार
जिस पर झूम रही सरकार, घात लगाए है विश्वव्यापी व्यापार

कुछ ऐसी ही स्थिति मप्र की राजधानी भोपाल सहित उन शहरों की है, जहां स्मार्टसिटी जैसी योजनाएं चल रही हैं। भोपाल हो या इंदौर या फिर कोई अन्य शहर, यहां विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, अधर में लटकी हुई हैं। इस कारण शहर बदहाल नजर आ रहा है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह शहर पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन बाजारवाद के कारण सरकार पर इस शहर को स्मार्टसिटी बनाने का ऐसा भूत सवार हुआ कि शहर स्मार्टसिटी तो नहीं बन पाया लेकिन यहां की सबसे स्मार्ट बस्ती आज खंडहर बनकर रह गई है। वहीं शहरवासियों को मेट्रो ट्रेन का सपना दिखाया गया। मेट्रो का सपना कब साकार होगा इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस परियोजना के कारण शहर की सड़कें बदहाल हो गई हैं। अगर यह कहा जाए कि भारत का सबसे हरित शहर भोपाल आज स्मार्ट सिटी और मेट्रो परियोजना के कारण गड्ढ़ों में तब्दील हो गया है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। स्मार्टसिटी के नाम पर शहर में जितनी भी योजनाएं-परियोजनाएं शुरू की गईं सब की सब बदहाल स्थिति में हैं। न स्मार्ट पार्किंग काम कर रही है, न स्मार्ट रोड और न ही अन्य योजनाएं। अभी तक स्मार्ट सिटी की जितनी योजनाएं बनी हैं उनमें गुणवत्ता का अभाव है। इस कारण वे निर्माण के साथ ही बदहाल हो गई है। राजधानी को स्मार्टसिटी बनाने के लिए भले ही बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हों लेकिन हकीकत यह है कि कागजों में स्मार्ट बन चुके शहर में सड़कों की हालत बेहद खराब है। हर साल नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। पूरे शहर में हर जगह गड्ढ़ा युक्त तस्वीरों को आसानी से देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत दिनों जिला योजना समिति की बैठक में विधायकों ने भी शहर के विकास में हो रही लापरवाही का मुद्दा उठाया। माननीयों ने कहा कि नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं है। अन्य सरकारी विभाग भी सुस्त पड़े हुए हैं। इस कारण राजधानी का हाल बदहाल हो गया है। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है, जहां समस्याओं का अंबार न लगा हुआ हो। भानपुर खंती, आदमपुर छावनी को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। शहर की सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना संकट के बावजूद लोगों ने नगर निगम को भरपूर टैक्स दिया है, लेकिन इसके बाद भी शहर में विकास की गति रुकी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान में भले ही अफसर कागजी खानापूर्ति कर वाहवाही पा रहे हैं, लेकिन सड़कों से लेकर पार्कों तक में कचरा और गंदगी फैली हुई है। बरसात ने नगर निगम के सफाई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो गया है। थोड़ी सी बारिश में नालों का पानी सड़क पर आ जाता है। ऐसे में स्मार्टसिटी का सपना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 20, पृष्ठ-48, 16 से 31 जुलाई, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलंटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

सरकार उठाए कदम

कोरोना वायरस के इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों में फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं लेकिन सरकार इसके प्रति भी कोरोना की तरह ही उदासीन बनी हुई है। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए सरकार को तुरंत कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **विजय सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

न्याय की लड़ाई

भोपाल गैस त्रासदी को 37 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में त्रासदी के कारण दिवंगत लोगों की विधवाओं की पेंशन को रोकना कतई सही नहीं है। वो भी तब जब कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। ऐसे में महिलाएं दो जून की रोटी के लिए भी मजबूर हैं।

● **रवि नागर,** भोपाल (म.प्र.)

पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन लाएं

मप्र सहित देशभर में पेड़ों की कटाई आम बात हो गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी तो लोगों को पेड़ों का महत्व समझ में आया। अब गांवों से लेकर शहरों तक लोग पौधारोपण कर रहे हैं।

● **सुरेश जाधव,** इंदौर (म.प्र.)

अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे सरकार

देश में कोरोना संक्रमण की मार ने एक तरफ जहां महंगाई को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ गई है। लोगों को कर्ज लेकर अपनी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धांत कहता है कि जब लोगों के हाथ में पैसा अधिक और उत्पादन कम होता है तब महंगाई बढ़ती है। आसान भाषा में समझा जाए तो यह कि जब एक अनार के सौ बीमार हों यानी एक सामान को खरीदने के लिए 100 लोगों के हाथ में ठीक-ठाक पैसा होता है तो दुकानदार कीमत बढ़ा देता है। यदि हमें देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **मनीषा वर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

किसान के साथ दुर्व्यवहार

लोगों का पेट भरने के लिए देश का किसान दिन-रात मेहनत करता है, अनाज उगाता है, तब कहीं जाकर वह अन्न के रूप में लोगों तक पहुंचता है। लेकिन कुछ लोग किसान की परेशानी बन गए हैं, जो नकली खाद-बीज का व्यापार कर रहे हैं। शासन-प्रशासन की सक्रियता के बाद भी नकली खाद-बीज बेचने वालों पर अंकुश नहीं लग रहा है। यह देश के किसान के साथ सही व्यवहार नहीं है। सरकार को नकली खाद-बीज बेचने वालों पर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि किसान परेशान न हो।

● **राहुल शिवहरे,** जबलपुर (म.प्र.)

ममता को मिले मौका

हाल ही में ममता बनर्जी ने चुनाव जीतकर भाजपा को बहुत अच्छी तरह पटखनी दी है। लेकिन वे सभी को स्वीकार्य नहीं हैं। दरअसल अब भी कोई दल कांग्रेस से ऊपर आकर विपक्ष की बागडोर अपने हाथ में नहीं ले रहा है और यही इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। सभी दलों को चाहिए कि वे अभी से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करें और ममता बनर्जी को अपना नेता मान लें।

● **पुरुषोत्तम सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

पूर्व मंत्रियों को काम की तलाश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से जिन मंत्रियों की विदाई हुई है उनका क्या होगा? सरकार से हटाए गए नेताओं को लेकर तीन तरह की बातें हो रही हैं। पहला अंदाजा यह है कि कुछ नेताओं को पार्टी संगठन में लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ नेताओं को राज्यों में भेजा जा सकता है और तीसरी बात यह है कि कुछ नेता राजभवनों में जा सकते हैं। हालांकि जिनको राजभवन जाना था उनको हटाने से पहले ही कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। इसलिए इस चर्चा में दम नहीं लग रहा है कि रविशंकर प्रसाद तमिलनाडु के राज्यपाल बनेंगे या कोई और नेता राजभवन भेजा जाएगा। संभव है कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉ. हर्षवर्धन को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी मिले। मोदी सरकार से एक दर्जन मंत्री हटाए गए और जेपी नड्डा के संगठन से तीन लोगों को सरकार में भेजा गया। पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव, उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और पार्टी सचिव विश्वेश्वर टुडू को मंत्री बनाया गया है। तभी कहा जा रहा है कि नए महासचिव नियुक्त होने हैं और उपाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। ये तीनों नेता इस लायक हैं कि इनको उपाध्यक्ष या महासचिव बनाया जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले राज्यों के चुनाव में इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है।

ममता की नजर दिल्ली पर

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भाजपा को हालिया संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त देने के साथ ही अब राष्ट्रीय राजनीति में धमाका करने को आतुर नजर आने लगी हैं। 2024 के आम चुनावों के लिए तृणमूल ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि ममता ने अपने प्रवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों पर पार्टी की राय रखने को कहा है जो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महत्व के हों। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल से सटे राज्यों में तो दीदी ने बाकायदा 'खेला' शुरू भी कर डाला है। पार्टी सूत्रों की मानें तो ममता का फोकस बंगाल भाजपा में बड़ी टूट के साथ-साथ त्रिपुरा में भी भाजपा संगठन में बड़े स्तर की सेंधमारी का है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस मुहिम की जिम्मेदारी दीदी ने मुकुल रॉय को सौंपी है। रॉय की पहचान एक मजबूत संगठनकर्ता की रही है। खबर पक्की है कि तृणमूल उन्हें जल्द ही राज्यसभा भेजने वाली है ताकि 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन में न केवल तृणमूल सक्रिय भूमिका निभा सके, बल्कि मोदी के बरक्स ममता को विपक्षी दलों का सर्वमान्य चेहरा बनाने पर भी सहमति बनाई जा सके।

मिला-जुला खेल

राजनीति में खेल का यह मॉडल बहुत लोकप्रिय है। हाल के दिनों में मुलायम सिंह यादव ने इसे लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बेटे अखिलेश से दूरी बनाई और खुद को भाई शिवपाल के करीब रखा। चौतरफा यह मैसेज बना कि अखिलेश जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बाद में पूरी पार्टी उनके नियंत्रण में चली गई। बिहार में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह यह मिला-जुला खेल कर रहे हैं। मीडिया में यह मैसेज बनाया जा रहा है कि आरसीपी ने अपने लिए खुद बात कर ली और केंद्र में मंत्री बन गए, जबकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे। मीडिया में इस बात की खूब चर्चा हुई कि नीतीश कुमार ने मंत्री बनने पर आरसीपी सिंह को बधाई तक नहीं दी। सोचें, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि नीतीश की मर्जी के बगैर आरसीपी सिंह भाजपा और प्रधानमंत्री से बात कर लें और मंत्री बन जाएं? हकीकत यह है कि जनता दल(यू) में नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर वे नहीं चाहते तो केंद्र में मंत्री बनना तो छोड़िए, भाजपा नेतृत्व से बातचीत भी आरसीपी सिंह नहीं कर सकते थे। फिर भी कुछ भोले लोग इस भ्रम में हैं कि नीतीश को धोखा देकर आरसीपी सिंह मंत्री बन गए हैं।

बढ़ रहा अविश्वास

सत्ता की गलियारों में खबर गर्म है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक खेला होने जा रहा है। जानकारों का दावा है कि शिवसेना प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी के मध्य इन दिनों कई बार बातचीत होना सामान्य घटना नहीं वरन् किसी बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा है। दरअसल, शिवसेना ने जबसे भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस और एनसीपी का साथ लेकर सरकार बनाई है उसके वरिष्ठ नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। खासकर सेना के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी का समन आने के बाद से ही सेना के नेताओं की चिंता खासी बढ़ चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अपने सहयोगियों का दबाव भाजपा संग दोबारा गठबंधन को लेकर बढ़ता जा रहा है। सेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने तो इस मुद्दे पर ठाकरे को पत्र लिखकर कह डाला है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचना जरूरी है इसलिए पार्टी को भाजपा संग तालमेल कर लेना चाहिए।

पीके का अलग ही खेल

पिछले कुछ महीनों में प्रशांत किशोर अपनी मुलाकातों के कारण चर्चा में रहे हैं। गत दिनों प्रशांत किशोर यानी पीके ने राहुल गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। बताया गया था कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान इन दोनों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। इसके साथ ही वर्चुअल तौर पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल हुई थीं। मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी से प्रशांत किशोर मिलने पहुंचे थे। लेकिन अब एक और नई बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा।

ठेके पर दे दिया पूरा विभाग

मप्र के कमाऊ विभागों में से एक विभाग इन दिनों ठेके पर चल रहा है। आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन आलम ही कुछ ऐसा है। दरअसल, प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे कमाऊ विभाग के मंत्रीजी ने पूरे विभाग की कमान कांग्रेसी पृष्ठभूमि के एक नेता को सौंप दी है। इस पर भी आपको आश्चर्य होगा कि जिस विभाग में 2-2 आईपीएस अधिकारी बैठे हैं, उसे एक कांग्रेसी कैसे चला रहा है। लेकिन यह हकीकत है। दरअसल, मंत्रीजी के कृपापात्र उक्त नेता ने पूरे विभाग पर कुंडली मार ली है। वे ही पूरे विभाग को चला रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मंत्रीजी की शह पर पूरे विभाग को ठेके पर दे दिया है। यानी विभाग के आय के स्रोत माने जाने वाले बैरियर की हिस्सेदारी कर दी है। यानी उन्होंने बैरियर पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों से कह दिया है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यह कोई देखने नहीं आएगा। इसके एवज में तुम्हें अमूक राशि मुझे हर महीने पहुंचानी होगी। इस राशि के ऊपर जो भी कमाई होती है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं। सूत्र बताते हैं कि उक्त नेता की ऐसी हरकत से पूरा विभाग आश्चर्यचकित है। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण सरकार के राजस्व के स्रोत बंद पड़े हुए हैं, ऐसे में जहां से राजस्व आना है, उस पर भी कांग्रेसी नेता ने कुंडली मार रखी है। हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में न तो मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं और न ही सरकार के अन्य लोग।

उपेक्षा से नाराज पूर्व नौकरशाह

कुछ माह पूर्व तक सरकार की आंख, कान बने पूर्व नौकरशाह इस समय उपेक्षा से परेशान हैं। इन अफसरों का कहना है कि हमने भी सरकार की खूब सेवा की है, फिर भी हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे इन पूर्व नौकरशाहों ने विगत दिनों एक बैठक की और अपनी उपेक्षा पर चिंता जाहिर की। दरअसल, जिन पूर्व नौकरशाहों ने बैठक की थी उनके रिटायर होने के बाद सरकार ने कुछ विभागों का प्रमुख बनाया था। ये अफसर सरकार की गुड लिस्ट में थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें समय से पूर्व चलता कर दिया गया। यही नहीं पूर्ववर्ती सरकार में मुख्य सचिव रहे एक साहब तो अभी भी सेवा में हैं और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकार में इन्हें प्रशासनिक मुखिया बनाया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही इन्हें उनके पद से हटाकर हाशिए पर खड़ा कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ जांच तेज कर दी गई। ऐसे में वे कैट में चले गए जहां से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे में अब वरिष्ठ अफसर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार पूर्व अफसरों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया जा रहा है।

मुफ्त का चंदन...घिस मेरे नंदन

यह कहावत इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में खरी उतर रही है। दरअसल, कई मंत्रियों के यहां तैनात अधिकारी-कर्मचारी मंत्रीजी के नाम पर अपनी रोटी सेंक रहे हैं। जहां आटे में नमक के बराबर लेनदेन चल रहा है, वहां तो मामला दबा हुआ है। वहीं कई जगह मंत्रीजी के प्रिय बेतहाशा कमाई में जुटे हुए हैं और वे यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि भाई मौका है चौका तो लगा लेने दो। मुफ्त का चंदन मिल रहा है, तो उसे घिस लेने दो। ऐसी मंशा रखने वाले एक निज सचिव काफी चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल मंत्रीजी के ही यहां तैनात उक्त निज सचिव तो मंत्रीजी के नाम पर पैसा लेकर पचा लेते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला उजागर होने के बाद निज सचिव की पोल खुल गई। उन्होंने मंत्रीजी के नाम पर छोटी रकम नहीं बल्कि 20 पेटी लेकर दबा लिया था। लेकिन मामला उजागर होने के बाद उन्हें उक्त राशि मंत्रीजी को देनी पड़ी। सूत्रों का कहना है कि गरीबों को रोटी मुहैया कराने वाले विभाग के मंत्रीजी के ये निज सचिव काली कमाई के लिए जाने जाते हैं। ये कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते हैं, जिससे कमाई की जा सके। स्थिति यह है कि वे ठेकेदारों, अफसरों आदि से मंत्रीजी के नाम पर पैसा मांगते हैं और खुद हजम करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इस बार मंत्रीजी के पीए की दाल नहीं गल पाई है। मंत्रीजी के सामने उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है।

ये कैसी परंपरा?

प्रदेश में इस समय नई-नई व्यवस्था और परंपरा देखने को मिल रही है। ऐसा ही नजारा गत दिनों सरकार की ब्रांडिंग करने वाले विभाग में नजर आया। दो आईएएस और एक आईपीएस की पदस्थापना वाले इस विभाग में पहली बार नया चलन देखने को मिला। दरअसल, गत दिनों विभाग की गतिविधियों से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह देखने को मिला कि सत्तारूढ़ पार्टी के दो पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। दोनों पार्टी के मीडिया विभाग से संबंधित हैं। दोनों को बैठक में देखकर अफसर भी आश्चर्यचकित हुए। सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ पार्टी के पिछड़ने के कारण प्रदेश पदाधिकारियों को गत दिनों फटकार लग चुकी है। इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी के ये दोनों पदाधिकारी इस बैठक में इसलिए शामिल हुए होंगे ताकि सरकार की बेहतर ब्रांडिंग हो सके। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी से काफी आगे है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मीडिया में सत्ता और संगठन के खिलाफ पनपे रोष को शांत करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा हुई।

अजब-गजब पुलिस

मप्र पुलिस के कई किस्से इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक मामला पुलिस विभाग के एक महकमे का है जहां तैनात बड़े साहब की यारी एक कनिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी से हो गई है। उक्त महिला अधिकारी अपनी रूप लावण्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आलम यह है कि साहब ने उक्त महिला अधिकारी पर अपना सारा अधिकार न्यौछावर कर दिया है। यानी विभाग में अब केवल उक्त महिला की ही चल रही है। इसके पीछे रहस्य क्या है, यह तो साहब ही जानें। वहीं प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में पदस्थ एक बड़े साहब इसलिए परेशान हैं कि उक्त जिले का प्रभारी गृहमंत्री को ही बना दिया गया है। यानी विभाग में जो भी तबादले या फेरबदल होंगे, वे प्रभारी मंत्री के ही माध्यम से होंगे। ऐसे में साहब को इस बात की चिंता है कि उनका हाथ तो खाली ही रह जाएगा। वैसे साहब ईमानदार अफसर माने जाते हैं लेकिन दे दाता के नाम पर उन्हें जो भी मिल जाता है वे उससे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसलिए साहब चिंतित हैं।

कोरोना की दूसरी लहर को उप्र ने जिस तरह संभाला है, वह अभूतपूर्व है। उप्र की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और यहां की जनता बधाई के पात्र हैं। आज उप्र मेक-इन इंडिया के लिए पसंदीदा जगह बन रहा है। कुछ साल पहले यहां कारोबार करना मुश्किल था।

● **नरेंद्र मोदी**

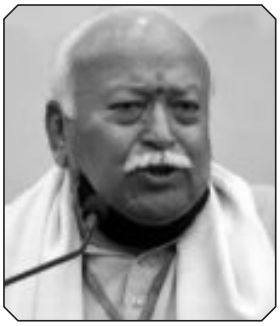

हम भारतीयों का डीएनए एक है। लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। हम एक लोकतंत्र में हैं। यहां हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है और सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत जितना हिंदू का है, उतना ही मुसलमान का भी है।

● **मोहन भागवत**

मेरे पास सब तरह के मेडल हैं, लेकिन जो मैं चाहती हूं वह गोल्ड मेडल मेरे पास अभी तक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल भी जीत लूंगी। इसके लिए मेरी तैयारी जोरों पर है। देश की उम्मीद पर खरा उतरने की हर बार कोशिश की है और इस बार दोगुने उत्साह के साथ हम ओलंपिक में उतरेंगे।

● **मैरीकॉम**

भारत अंतरिक्ष में अपनी पैठ जमा रहा है, इसके लिए उसे बधाई। विश्व के अन्य देश भी अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं, इससे लोगों को अंतरिक्ष और पृथ्वी के बारे में गहराई से जानने का मौका मिलेगा। अंतरिक्ष पर्यटन का केंद्र भी बन रहा है। यह अच्छे संकेत हैं।

● **एलन मस्क**

मैंने बॉलीवुड में अभी तक हर फ्लेवर की फिल्में की हैं। इससे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है। लेकिन अब मुझे एक ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला है, जो न केवल बड़े बजट की फिल्म है, बल्कि उससे काफी उम्मीद भी है। करन जौहर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मैं करने जा रही हूं। इस फिल्म में काम करने का अलग ही उत्साह है। कोरोना संक्रमण के बाद मैं फिर से लाइट, कैमरा, एक्शन का सामना करूंगी। यह फिल्म मेरे लिए मेरी डेब्यू फिल्म की तरह ही होगी, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद किसी फिल्म में काम करने जा रही हूं।

● **आलिया भट्ट**

वाक्युद्ध

रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक को राहुल गांधी जिस तरह छोड़कर चले गए, वह उचित नहीं है। वे अपनी मनमर्जी के सवालों को उठाकर चर्चा को प्रभावित कर रहे थे। वे एक जिम्मेदार पद पर हैं इसलिए उन्हें यह शोभा नहीं देता है कि किसी महत्वपूर्ण बैठक में से इस तरह बाहर निकल जाएं।

● **रविशंकर प्रसाद**

भाजपा और केंद्र सरकार हर चीज में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में सरकार राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं थी। वहां अपने मनमानी विषय पर चर्चा की जा रही थी, ऐसे में कांग्रेस वहां बैठकर केवल प्रवचन तो नहीं सुन सकती थी। इसलिए वॉकआउट किया गया।

● **अधीर रंजन चौधरी**

मप्र का खजाना खाली है। इस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार-बार कह रहे हैं। ऐसे में विकास कार्यों के लिए फंड की जुगाड़ में मुख्यमंत्री ने गत दिनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मंत्रियों ने मप्र में विकास की गति बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द फंड मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

विकास को लगेंगे पंख

मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही मप्र ने भी अपने विकास की डिमांड नए मंत्रियों के सामने रख दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। प्रदेश से 8 नई फ्लाइट 16 जुलाई से शुरू हो रही हैं। दोनों के बीच मुलाकात में प्रदेश की देश और विदेश से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई। शिवराज सिंह ने प्रदेश के लिए 8 फ्लाइट शुरू करने पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि अब राज्य की देश के साथ एयर कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने गत दिनों उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा 16 जुलाई से 8 फ्लाइट राज्य से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सिंधिया से कुछ और फ्लाइट शुरू करने, एयरपोर्ट के विस्तार और कार्गो हब की सुविधा बढ़ाने की मांग भी उठाई है। उड़ान योजना में अंतर्राज्य फ्लाइट की मांग रखी है।

शिवराज सिंह ने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मप्र की एयर कनेक्टिविटी देश और विदेश से बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। एयर कनेक्टिविटी पर्यटन, निर्यात और निवेश के लिए जरूरी है। कृषि, कपड़ा उत्पादन में राज्य आगे है। उन्होंने बताया केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से वृद्धा, दिव्यांग पेंशन पर चर्चा की गई। 2011 के बाद राज्य में इनकी आबादी बढ़ी है। मगर राज्य के 22 लाख लोगों को 2011 के आंकड़ों के मुताबिक पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार खुद बाकी लोगों को पेंशन दे रही है। केंद्र सरकार से मांग की है कि बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप बजट भी बढ़ाए।

मुख्यमंत्री शिवराज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मूंग दाल की खरीद पर बातचीत की है। राज्य की एक लाख 34 हजार मीट्रिक टन दाल खरीद की इजाजत केंद्र सरकार ने दे रखी है। मप्र में इस साल मूंग दाल का 7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार से मूंग दाल की खरीद 5 लाख मीट्रिक टन करने की मांग उन्होंने की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। उन्होंने जबलपुर और इटारसी में ऑर्डिनेंस क्लस्टर शुरू करने की मांग उठाई है। यहां पर 6 फैक्ट्रियों में बाहर की एमएसएमई छोटे-छोटे कलपुर्जे सप्लाई करती है। अगर यह सप्लाई राज्य की अपनी एमएसएमई शुरू कर दे तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और निवेश भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास सरकार की जमीन भी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित तीन पेंशन योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को रिवाइज करने का अनुरोध किया। मंत्रालय सूत्रों ने बताया, केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत तीन पेंशन योजनाएं इंदिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्त पेंशन योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर मप्र के 22 लाख हितग्राहियों की संख्या का स्टेट कैप निर्धारित किया गया है। सूत्रों ने बताया, इन योजनाओं को संचालित करने में मप्र सरकार पर (अतिरिक्त 11 लाख 38 हजार पात्र हितग्राही) 66.78 करोड़ प्रतिमाह राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मप्र में लागू हो सरप्लस शेयरिंग मॉडल

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर गत वर्षों के अनुभवों को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कंपनियों के चयन के लिए 3 बार निविदा जारी की गई किंतु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग मॉडल को मप्र में लागू किया गया है। मॉडल के अनुसार बीमा कंपनी की क्लेम देनदारियां कुल प्रीमियम के 80 से 110 प्रतिशत रहेगी। कुल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक स्तर का क्लेम राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा तथा 80 प्रतिशत से कम दावा बनने पर बीमा कंपनी द्वारा 80 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त की राशि राज्य शासन को वापस की जाएगी।

बीमारू राज्य से उबारने के बाद से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरा फोकस मप्र को विकसित राज्य बनाने पर है। मुख्यमंत्री की इस मंशा को अब उड़ान मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार में मप्र का प्रभाव बढ़ा है। अब केंद्र सरकार में मप्र के 6 मंत्री हो गए है। इससे प्रदेश में 6 गुना तेजी से विकास होने की संभावना है।

केंद्र में बढ़ा मप्र का कद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होने के बाद मप्र का सियासी प्रभाव और बढ़ गया है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में अब तक मप्र से 5 केंद्रीय मंत्री रहे, अब संख्या 6 हो गई है। प्रदेश के विकास के लिए आतुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए यह बड़ी सौगात है। क्योंकि प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद के विस्तार में कुछ पुराने मंत्रियों की पदोन्नति यह बताती है कि उन्हें उनके बेहतर काम का पुरस्कार मिला। यह मिलना भी चाहिए था क्योंकि इससे सभी को यह संदेश जाता है कि बेहतर प्रदर्शन मायने रखता है न कि मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर मौजूदगी। इस पहले बड़े विस्तार और साथ ही फेरबदल से यही स्पष्ट हुआ कि नए मंत्रियों के चयन में योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता देने के साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा गया।

नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि मंत्रालय है। मप्र की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है। आज मप्र कृषि के क्षेत्र में अव्वल राज्य बना है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तोमर का भी अमूल्य योगदान है। तोमर का सर्वाधिक योगदान देश के कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के रूप में रहा है। भ्रष्टाचार का कलंक झेल रही मनरेगा को आज देश के ग्रामीण अंचल में रोजगार की रीढ़ बनाने में तोमर का खास योगदान है। गांवों के विकास में पारदर्शिता, प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब को छत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के स्वप्न को पूर्ण करने का कार्य तोमर ने विगत 7 वर्षों में किया है। तोमर की योग्यता, प्रतिभा और अनुभव का सही उपयोग देश के कृषि मंत्री के रूप में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुप्रतिक्षित कृषि सुधार कानूनों को अमली जामा पहनाकर उन्होंने मील के वे पत्थर स्थापित किए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम किसानों के जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित कर देंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से किसानों की आय का सशक्तिकरण हो या स्वामिनाथन आयोग की अनुशंसा पर किसानों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना एमएसपी प्रदान करना हो, तोमर ने कृषि मंत्री के रूप में किसानों के हित में ऐसी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी।

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी तोमर सदैव मप्र के विकास के प्रति सक्रिय एवं चिंतित रहते हैं। मुरैना जिले के कैलारस-सुमावली क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की 1500 करोड़ की रक्षा परियोजना हो या निजी क्षेत्र की देश की पहली हथियार निर्माण इकाई की स्थापना मालनपुर में कराना हो, तोमर के प्रयासों ने इस अंचल के विकास को नई दिशा दी है। ऐसे में अब तोमर से प्रदेश को और अपेक्षाएं हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको सफलीभूत करने में शिवराज और तोमर की जोड़ी सफल होगी।

मप्र से राज्यसभा सदस्य धर्मेंद्र प्रधान के पास इस बार शिक्षा, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। प्रधान के पास इससे पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय का जिम्मा था। प्रधानमंत्री ने अब धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का मुखिया बनाया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय का कुनबा भी बढ़ गया है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में तीन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जबकि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता

सिंधिया से काफी उम्मीदें

मप्र से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में शामिल होना पहले से तय माना जा रहा था। क्योंकि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने सरकार भी बनवाई थी। इसलिए उन्हें यह पद उपहार स्वरूप भी माना जा रहा है। हालांकि उनका परफार्मेंस मनमोहन सरकार में भी अच्छा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, जिसका सालाना बजट 3224.67 करोड़ रुपए है। इससे प्रदेश को उनसे काफी उम्मीदे हैं। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बड़ा मुद्दा है। अभी देश के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद प्रदेश करता है। इसके अलावा एयर कार्गो की लंबे समय से डिमांड हो रही है। साथ ही प्रदेश में नए एयरपोर्ट व इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश का एयर-कनेक्शन यदि सीधे विदेश से जुड़े तो इसे भी बड़ी पहल माना जाएगा। एयर इंड्रस्टी में प्रदेश हब बन सकता है, क्योंकि यह देश के सेंटर में है। इससे देशभर में कही भी जाने के लिए सेंट्रल पाइंट के रूप में विकसित हो सकता है। सिंधिया का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेहतर तालमेल है। मप्र की राजनीति में पिछले सवा साल में दोनों नेता एक नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मप्र के विकास में सिंधिया-शिवराज की जोड़ी नया गुल खिलाएगी।

मंत्रालय में एक राज्य मंत्री का पद सृजित किया गया है। नए बदलाव के तहत डॉ. सुभाष सिरकार, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह और अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं, राजीव चंद्रशेखर को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। यानी प्रधान के पास एक मजबूत टीम है। इससे संभावना जताई जा रही है कि मप्र सहित देशभर में शिक्षा का स्तर सुधारने में प्रधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के पास उच्च शिक्षा विभाग है। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इससे प्रदेश में कई नवाचार हो सकते हैं। प्रदेश को नए एनआईटी, आईआईएम या ऐसे बड़े संस्थान की उम्मीद है। इसके अलावा नॉलेज कारपोरेशन और इंटरनेशनल एजुकेशन कनेक्टिविटी भी प्रदेश के लिए हो सकती है। नई नीति में निजीकरण को बढ़ाया दिया गया है। इस कारण देश-दुनिया के बड़े ग्रुप को इंदौर या अन्य शहरों में लाने की उम्मीद की जा सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी नया स्कोप है। इसके अलावा बजट के मामले में उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी प्रधान की अच्छी ट्यूनिंग है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि प्रधान मप्र में शिक्षा की क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मोदी की नई कैबिनेट में प्रहलाद सिंह पटेल के पास भी दो मंत्रालय हैं। इस बार उनके पास जल शक्ति मंत्रालय आ गया है। जलशक्ति मंत्रालय की योजना को साकार करने में मप्र अन्य राज्यों से आगे रहा है। घर-घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर मप्र में तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि प्रहलाद पटेल हर घर नल से जल की योजना को जल्द से जल्द साकार करेंगे। गौरतलब है कि दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल काफी अनुभवी नेता हैं।

मोदी की पूर्ववर्ती कैबिनेट में पर्यटन का स्वतंत्र प्रभार पटेल के पास था। मप्र सहित देशभर में पर्यटन के विकास के लिए इन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। पर्यटन को उद्योग बनाने के लिए पटेल ने कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन व संस्कृति क्षेत्र के दमोह सहित महाकौशल जबलपुर में कई नए कार्य शुरू कराए। राष्ट्रपति को दमोह लेकर आए, रानी दुर्गावती किला का जीर्णोद्धार कराया। देश में पांचवा सीसीआरटी सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र का कार्यालय भी खुलवाया था। गुजरात से पदयात्रा भी की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। प्रहलाद पटेल द्वारा किए गए कार्यों के अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोधी बाहुल्य वोट बैंक को आगामी उप में भी साधने के लिए कद घटाते हुए मंत्रिमंडल में ही रखा गया है। प्रहलाद पटेल को जलशक्ति व खाद्य प्रसंस्करण का राज्यमंत्री बनाया गया है, जो दो मंत्रियों के नीचे कार्य करेंगे। जलशक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बनाए गए हैं। वहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार बनाए गए हैं। प्रहलाद पटेल ने दमोह जिले में पर्यटन उद्योग के जो नए द्वार खोले जाने के प्रयास किए थे अब वह पूर्व की तरह बंद रहने के आसार बन गए हैं। जिससे पर्यटन के क्षेत्र में होने वाले विकास को बड़ा झटका लगा है।

राज्यमंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते के पास दो मंत्रालय हैं। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नई बयार बहने की उम्मीद है। मंडला लोकसभा सीट से छठी मर्तबा जीते फग्गन सिंह कुलस्ते पार्टी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। प्रदेश के एक नेता थावरचंद गहलोत मंत्रिमंडल से हटाए गए, बदले में प्रदेश से दो नेताओं को जगह मिल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं वीरेंद्र खटीक को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल कर अच्छे विभाग दे दिए गए। सिंधिया को उड्डयन मंत्री बनाया गया और खटीक को सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्री। इसका मतलब यह कतई नहीं कि मप्र के साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ। सिंधिया-खटीक ताकतवर मंत्री बने तो प्रहलाद पटेल एवं फग्गन सिंह कुलस्ते का कद घटा दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर से दो महत्वपूर्ण विभाग पंचायत, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण वापस ले लिए गए। हालांकि वे केंद्र में ताकतवर बने हुए हैं। प्रहलाद पिछड़े वर्ग में लोधी समाज के बड़े नेता है और फग्गन को भाजपा में आदिवासी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। आमतौर पर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। यहां उलटा हो गया। प्रहलाद-फग्गन का प्रमोशन की बजाय डिमोशन कर दिया गया। पहले वे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री थे, अब सिर्फ राज्यमंत्री रह गए। ये दोनों पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का कद छोटा करने की वजह उनकी परफार्मेंस को बताया जा रहा है। वे नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में भी राज्य मंत्री थे लेकिन परफार्मेंस ठीक न होने के कारण उन्हें हटा दिया गया था।

● **कुमार राजेन्द्र**

बुंदेलखंड में आएगी बहार

सूखा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहे बुंदेलखंड में अब विकास की बहार आएगी। इसकी आस मप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले 7 जिलों के लोगों को है। इसकी वजह यह है कि मोदी की नई कैबिनेट में टीकमगढ़ के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार मंत्री बनाए गए हैं। डॉ. वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसका सालाना बजट 1,1689.39 करोड़ रुपए है। लोगों को उम्मीद है कि डॉ. वीरेंद्र कुमार क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर यहां विकास की गंगा बहाएंगे। बुंदेलखंड के बड़े नेता वीरेंद्र खटीक सागर, टीकमगढ़ से 7 बार के सांसद हैं। थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। लिहाजा, उनकी जगह इसी वर्ग से खटीक को मौका दिया गया है। सांसद खटीक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सितंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए थे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनने पर खटीक को 17 जून 2019 को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। उन्होंने मोदी सहित सभी सांसदों को शपथ दिलाई थी।

कोरोना संक्रमण ने देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। इसका असर मप्र पर भी पड़ा है। इसके बावजूद मप्र के लोग खुशहाल हैं। इसकी वजह यह है कि कृषि ने मप्र की अर्थव्यवस्था संभाल ली है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब प्रदेश को टूरिज्म और इंडस्ट्रियल हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

फिर भी मप्र खुशहाल

मई में जब प्रियजनों के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जद्दोजहद करते लोगों और श्मशानों में लंबी कतारों के मनहूस दृश्य खबरों में छाए थे, कोविड 2.0 चुपचाप कहीं और भी कहर बरपा रहा था और वह थी अर्थव्यवस्था। दूसरी लहर ने जिस अप्रत्याशित प्रचंडता से हमला बोला, उसने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश में हुई थोड़ी-बहुत आर्थिक बहाली को भी पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन से बचा गया, लेकिन राज्य लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हुए। लिहाजा, निवेश फर्म बार्कलेज के मुताबिक, देश को मई के हर हफ्ते करीब 8 अरब डॉलर या 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी स्थिति में मप्र की अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाल लिया।

कृषि को अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत बनाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब मप्र को टूरिज्म और इंडस्ट्रियल का हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 7 जुलाई को शासकीय जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर की। शिक्षा, रोजगार और उद्योग से जुड़ी नीतियों पर युवा संवाद के जरिए छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि कृषि का भरपूर दोहन कर चुके हैं। अब तेज औद्योगिकीकरण की जरूरत है। प्रदेश में तीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चंबल अंचल से अटल एक्सप्रेस वे निकालने, जबलपुर-रीवा-सतना से सिंगरौली होते हुए एक कॉरिडोर और तीसरा नर्मदा एक्सप्रेस अमरकंटक से जबलपुर होते हुए गुजरात की सीमा तक जाएगा। इस मार्ग के दोनों तरफ छोटे-बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। प्रदेश को टूरिज्म और इंडस्ट्रियल हब बनाकर इसकी तस्वीर बदलनी है। इसमें तीनों कॉरिडोर बड़ी भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि रोजगार जरूरी है। कृषि का पूरा दोहन कर हम पंजाब को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अब औद्योगिकीकरण की रफ्तार बढ़ानी है। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में अपना बिजनेस शुरू करें। कोशिश है बाहर से उद्योगपति आएं, लेकिन मप्र के युवा भी उद्योग लगाने की सोचें। इसलिए तीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना की गई है। युवा के लिए धन की बाधा होती है। उनके लिए इनोवेटिव युवा उद्यमी योजना बनाई है। शिक्षा के तीन उद्देश्य है। ज्ञान देना, अच्छा नागरिक बनाना और कौशल देना। देश में स्किल्डमैन पॉवर की कमी है। इस अंतर को भरना है। पहले टपरे वाली आईटीआई चलती थी। अब संभागीय स्तर पर मॉडल आईटीआई बन रही है। हम भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, जहां 6 हजार बच्चों को पढ़ाकर देश-विदेश में नौकरी लायक बनाएंगे।

मप्र में पर्यटन क्षेत्र को भी रोजगार मूलक बनाया जा रहा है। खुद शिवराज कहते हैं कि पर्यटन मप्र की ताकत है। पर्यटन के क्षेत्र में मप्र ने एक साथ 11 पुरस्कार जीतने का काम किया है। टूरिज्म की बेहतर नीति बनाई गई है। बारिश में बफर में सफर योजना चालू की है। हाट बैलून जैसी नए इनोवेटिव आईडिया लेकर आए हैं। दरअसल, प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने की नीति पर वर्षों से काम हो रहा है। इसलिए यहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इस दौरान लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उद्योग-धंधे अभी भी पटरी पर नहीं आ पाए हैं। इस बीच कोरोनाकाल के पिछले 14 महीनों में जहां बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधों को नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं इस दौरान मप्र में इस मोर्चे पर सुखद खबर आई। 1 मार्च 2020 से 15 मई 2021 तक 6095 नई कंपनियां रजिस्टर्ड की गईं। 1 मार्च 2020 से लेकर 15 मई 2021 के बीच रजिस्टर्ड हुई इन कंपनियों में 4844 प्राइवेट लिमिटेड हैं तो 1141 कंपनियां एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली हैं।

● **प्रवीण कुमार**

पढ़ाई खत्म होते ही मिलेगा रोजगार

मप्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में शिक्षा समाप्त होते ही युवाओं को रोजगार मिलने की अनूठी पहल शुरू की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शिक्षा समाप्त होने के बाद पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार सभी 52 जिलों में प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त करेगी। साथ ही प्रदेशभर में 6-6 माह का डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जाएगा। यह तकनीकी शिक्षा युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायक रहेगी। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद शैक्षणिक संस्थानों में ही प्लेसमेंट लगाया जाएगा और शिक्षा के तकनीकी आधार पर तत्काल रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोनाकाल के बाद कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। दो साल से उच्च शिक्षा से दूर प्रदेश के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

सप्लीमेंट्री बजट लाएगी सरकार

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 9 से 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान सरकार पहला सप्लीमेंट्री बजट लेकर आएगी। इसमें कोरोना की व्यवस्थाओं में हुए खर्च के लिए प्रावधान किए जाएंगे। वित्त विभाग की तैयारी के मुताबिक, सप्लीमेंट्री बजट में करीब 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और अवैध कॉलोनी को वैध करने वाले संशोधित विधेयक को सरकार विधानसभा में पारित कराएगी। मप्र का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से बजट सत्र तय अवधि से 10 दिन पहले समाप्त हो गया था। इसके पहले 2020 में मानसून और शीतकालीन सत्र भी नहीं हो पाए थे। 6 माह में सदन की बैठक करने की अनिवार्यता के चलते सितंबर 2020 में बैठक हुई थी।

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 9 से 12 अगस्त तक होने वाले सत्र में वित्त विभाग मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान भी प्रस्तुत करेगा। इसमें कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न विभागों को अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी कर चुके हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आने वाले समय में बड़ी राशि खर्च की जाएगी।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के विधेयक को पेश करेगी। शिवराज कैबिनेट ने पिछले सप्ताह ही इस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन इस विधेयक का नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है। चूंकि इससे पहले विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है, ऐसे में विधेयक सदन से पारित कराना होगा।

मप्र में नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए शिवराज सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में एक बार फिर नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक लाएगी। बजट सत्र में भी इसे प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी।

कोरोनाकाल की दूसरी लहर के बाद होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। मानसून सत्र में बरसने के लिए विपक्ष पहले से तैयारी में जुटा हुआ है। इस सत्र में कोरोना की दूसरी लहर से बने हालातों, मारे गए लोगों का आंकड़ा और स्वास्थ सेवाओं की कमी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और खाद बीज की किल्लत समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सत्तापक्ष भी तैयारी में है। पूर्णकाल के दौरान सरकार के उठाए गए कदमों और सरकार की योजनाओं के सहारे सत्तापक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देगा। 12 जुलाई को विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा में उठने वाले मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष तैयारियों में जुट गए हैं।

कोरोनाकाल के दौरान इससे पहले हुआ विधानसभा का बजट सत्र अपने तय समय से पहले खत्म हो गया था। विधानसभा का बजट सत्र तय अवधि से 10 दिन पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। इस बार भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उसके तय समय से पहले विधानसभा का सत्र छोटा रखा गया है ताकि छोटे सत्र में बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकें।

विधानसभा का मानसून सत्र चार दिन का होने को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि इस सत्र को कम से कम एक सप्ताह का किया जाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के साथ ही नेमावर में हुई घटना और महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस इस सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार को घेरने की तैयारियों पर कांग्रेस को झटका लगा है इसलिए कांग्रेस ने चार दिन के विधानसभा सत्र को लेकर आपत्ति की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं और पत्र भी लिख सकते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही में पहले दिन गृह विभाग और कृषि विभाग के प्रश्नों को लिया जा रहा है। जबकि आखिरी दिन चिकित्सा शिक्षा, राजस्व विभागों के प्रश्न आएंगे।

वर्मा का कहना है कि विधानसभा के तीन सदस्यों का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। इसलिए पहले दिन इन सभी के प्रति सदन संवेदना प्रकट करेगा और सदन उस दिन स्थगित हो जाएगा। ऐसे में गृह और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के प्रश्न चर्चा में आ ही नहीं पाएंगे। जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। नेमावर सहित कई जिलों में जघन्य अपराध हुए हैं, उन पर चर्चा के लिए समय ही नहीं मिलेगा। वहीं आखिरी दिन चिकित्सा शिक्षा और राजस्व जैसे विभाग रखे हैं। आखिरी दिन आमतौर पर हंगामा होता है, ऐसे में कोरोना में हुई मौतों पर भी ज्यादा चर्चा नहीं हो सकेगी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ मांग करेंगे कि सत्र कम से कम एक सप्ताह का होना चाहिए।

● **विकास दुबे**

कमलनाथ सरकार ने बदला था महापौर चुनाव का तरीका

कमलनाथ सरकार ने नगर पालिक विधि में संशोधन करते हुए महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की जगह पार्षदों के बीच से करने का प्रविधान किया था। शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत भाजपा ने विरोध दर्ज कराते हुए राज्यपाल से इन प्रविधानों को लागू करने की अनुमति नहीं देने की मांग रखी थी। हालांकि, राज्यपाल ने इसे कुछ दिन बाद अनुमति दे दी थी। इसके बाद विधेयक लाया गया था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए और सत्ता परिवर्तन हो गया।

कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान

मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब पार्टी कार्यकर्ताओं को पद देकर सम्मान देने के लिए फॉर्मूला 52 बनाया है। इस फॉर्मूले के तहत करीब 10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। यह काम स्थानीय भाजपा संगठन की सहमति में जिलों में प्रभारी मंत्रियों को करना है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर यह जमावट की जा रही है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को खुश करना चाह रही है। इसके लिए पार्टी सरकारी समितियों में तकरीबन 10 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए स्थानीय संगठन और जिला प्रभारी मंत्रियों को फ्री हैंड कर दिया गया है।

दरअसल भाजपा कैडर बेस पार्टी हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि होता है। हाल ही में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को आस जगी है कि उन्हें जिले की शासकीय समितियों को जगह मिलेगी। कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वह जल्द ही इन समितियों का गठन करने की तैयारी में है। यदि इन समिति को गठन होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 10 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है।

माना जा रहा है कि जिला स्तरीय दो दर्जन से ज्यादा समितियों में भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकती है। इन समितियों में प्रभारी मंत्री अशासकीय सदस्यों को लिए जाने की अनुशंसा कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जगह योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समितियों में मिल सकती है। इस विभाग की जिला योजना समिति में दो अशासकीय सदस्यों को लिया जा सकता है। वहीं अंत्योदय समिति में 21 अशासकीय सदस्यों को रखा जा सकता है। इसी तरह नगर स्तरीय समिति नगर निगम में 21 और नगर परिषद में 7 इसके अलावा विकासखंड स्तरीय समिति में 21 और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में 7 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है।

पीएचई की जिला जल एवं स्वच्छता समिति में तीन सदस्य, जिला शहरी विकास अभिकरण की शासी निकाय समिति में भी तीन सदस्य, रोगी कल्याण समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला उपभोक्ता फोरम, विकासखंड स्तरीय सतर्कता समिति में दो-दो अशासकीय सदस्य प्रभारी मंत्री अपनी अनुशंसा पर बन सकेंगे। इसके अलावा एकीकृत बागवानी विकास मिशन समिति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक-एक सदस्य बन सकेंगे। जेल विभाग की अशासकीय संदर्शक समिति में 6 सदस्य बन सकेंगे। जिला कौशल समिति में 3, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिला प्रबंध कारिणी समिति और निगरानी समिति में तीन-तीन, जिला पशुक्रूरता निवारण समिति, जिला पशु रोगी कल्याण समिति में भी दो सदस्य अशासकीय बनाए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तीन समितियों में 9 सदस्य बनाए जा सकते हैं। रोगी कल्याण समिति और जिला टीबी फोरम में दो-दो सदस्य अशासकीय हो सकते हैं। एससी-एसटी अत्याचार निवारण सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति में 8 सदस्य बन सकते हैं। वहीं जिला पुलिस शिकायत बोर्ड में जिला पंचायत के सदस्य या नगरीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि को जगह दी जा सकती है।

वर्ष 2018 में मप्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें पदों से रुखसत कर दिया गया था। कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि भाजपा नेताओं को हटाकर वह अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करे। जब तक कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौका देती, तब तक सरकार चली गई। अब चूंकि मप्र में त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं, लिहाजा सरकार चाहती है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से मौका दिया जाए। इन नियक्तियों के जरिए भाजपा संगठन और सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। पार्टी अपने मैदानी कार्यकर्ताओं के इस जोश का फायदा निकाय और पंचायत चुनावों में उठाना चाहती है। इसलिए शिवराज ने फॉर्मूला 52 बनाया है।

● **राकेश ग्रोवर**

मोदी की तर्ज पर होगा शिव मंत्रिमंडल में उलटफेर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है, जिसमें आयु एवं परफार्मेंस के आधार पर 13 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा गया है। अब मप्र में भी शिवराज मंत्रिमंडल में उलटफेर की अटकलें शुरू हो गई हैं। संभवतः निकट भविष्य में होने वाले निकाय एवं पंचायत चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल आकार ले सकता है। जिसमें कुछ मंत्रियों को आयु एवं परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कुछ के विभाग बदलेंगे। हालांकि कांग्रेस से आने वाले किसी भी मंत्री को कोई खतरा नहीं है। शिवराज मंत्रिमंडल में 30 मंत्री हैं। जिनमें से 23 कैबिनेट एवं 7 राज्यमंत्री हैं। सिंधिया समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो कैबिनेट में ज्यादातर पुराने चेहरे हैं। जो पिछली सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। सिर्फ मोहन यादव, ओमप्रकाश सकलेचा, ऊषा ठाकुर एवं अरविंद सिंह भदौरिया पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल में 4 और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि सत्ता एवं संगठन हर मंत्री की परफार्मेंस पर नजर रख रहा है। खासकर वरिष्ठ मंत्रियों पर पैनी नजर है।

चाल, चरित्र और चेहरा वाली भाजपा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बेतुके बोल इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इससे भाजपा की साख लगातार गिर रही है। हालांकि संघ से लेकर मुख्यमंत्री तक ने सभी को तौलकर बोलने की नसीहत दी है। लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है।

माननीयों के बेतुके बोल

अभी हाल ही में भोपाल में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को नसीहत दी गई थी कि वे पार्टी की गरिमा अनुसार कार्य करें और अनाप-शनाप बोलने से बचें। लेकिन पिछले एक पखवाड़े के दौरान मप्र के माननीयों के बेतुके बयानों से चर्चा में हैं। महंगाई पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि महंगाई पहली बार नहीं बढ़ रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा इससे एक कदम आगे जाकर बोले- महंगाई में आनंद है। मंदसौर से भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को बढ़ती आबादी का जिम्मेदार ठहराया है, तो मुरैना के जौरा से विधायक ने अपने बयान में बिजली चोरी की छूट दे दी।

कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए बृजेंद्र सिंह यादव शाजापुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। शाजापुर के रेस्ट हाउस में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी महंगाई बढ़ती रही है। पहले किसानों की उपज औने-पौने दामों में बिका करती थी, पर अब उन्हें भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। सरकार ने तो इससे ज्यादा बांट दिया है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है, उसके चलते ही महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा को महंगाई में आनंद नजर आता है। सकलेचा छतरपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। वह यहां दो दिन के दौरे पर आए थे। उन्होंने महंगाई पर दार्शनिक अंदाज में कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी न आए, तब तक सुख का आनंद नहीं आता। मंहगाई कम कर पाने में मोदी सरकार की नीतियों पर मीडिया के सवाल करने पर पर सकलेचा ने कहा कि यह आप जैसे लोगों की सोच हो सकती है। आप अफवाहें फैला रहे हैं।

मंदसौर से भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लेकर विवादित बयान दिया है। वे विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत बता रहे थे। इसी दौरान कह गए कि अगर हम भारत के लिहाज से देखें, तो आमिर खान जैसे लोग देश की आबादी को असंतुलित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 3 बच्चों के साथ 2 पत्नियों को छोड़ दिया। सांसद ने कहा कि उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता अपने दो बच्चों के साथ और दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ कहां भटकेंगी, उसकी चिंता नहीं? लेकिन आमिर तीसरी की खोज में जुट गए।

मुरैना के जौरा से भाजपा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने लोगों को बिजली चोरी की खुली छूट दे दी। विधायक कैलारस की चंबल कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय पर आए हुए थे। वहां उन्होंने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में स्थानीय लोगों ने कहा कि वे पानी के लिए कटिया डालकर मोटर चलाना चाहते हैं, लेकिन बिजली वाले चलाने ही नहीं देते। इस पर विधायक ने कहा कि तुम बिजली वालों की चिंता मत करो। उनको मैं देख लूंगा। तुम तो मोटर चलाओ।

एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के बयान से मचा बवाल बमुश्किल ठंडा हो पाया था कि अब मप्र सरकार के एक मंत्री ने इसे हवा दे दी है। प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे ने इस संबंध में एक विवादास्पद बयान देकर सनसनी फैला दी है। उनके बयान के बाद एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का मामला दोबारा उभर सकता है। आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे थे। मां शारदा की पूजा-अर्चना के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका को स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने साफतौर पर दावा करते हुए कहा कि मप्र में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जब कोरोना की पहली लहर में एलोपैथी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, उस वक्त आयुर्वेद ने ही लोगों के जीवन की रक्षा की थी। दूसरी लहर में भी आयुर्वेद कारगर रहा और प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ितों के लिए योग से निरोग कार्यक्रम के जरिए लोगों का मनोबल बढ़ाया। कोरोना से लड़ने का हौसला दिया। माननीयों के ऐसे बोल से भाजपा की साख पर दाग लग रहा है।

● **जितेंद्र तिवारी**

जल्द भूल गए नसीहत

अभी पिछले महीने ही मप्र भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि को नसीहत दी थी कि वे सेवा करें, दिखावा न करें। साथ ही कहा था कि आप ऐसा व्यवहार न करें, जिससे कोई आहत हो। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टी की इस नसीहत को मंत्री, सांसद और विधायक जल्द ही भूल गए। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, मंत्री मीना सिंह तो लगातार उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं। वहीं पार्टी के अन्य नेता भी ऐसे बोल बोल रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश पनप रहा है। हालांकि एक बार फिर संघ और भाजपा ने नेताओं को चुप रहने की सलाह दी है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समय-समय पर अपनी विचारधारा बदलते रहता है। संघ पूर्ण रूप से एक गैर-राजनीतिक संगठन है, तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि उसके साथ मुस्लिमों के जुड़ने से उसे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होना है। यही वजह है कि संघ राजनीति पर मुखरता के साथ अपनी बात रखता आया है। संघ प्रमुख भागवत ने राजनीति को लेकर कहा कि कुछ ऐसे काम हैं, जो राजनीति नहीं कर सकती। लोगों को जोड़ने का काम राजनीति नहीं कर सकती है। लेकिन, इसे बिगाड़ने का हथियार बन सकती है।

क्या संघ बदल रहा है...?

प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक में हुए मंथन के बाद सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के मिशन 2025 पर अपनी सहमति दे दी है। प्रभु श्रीराम की कर्मभूमि चित्रकूट में यह निर्णय संघ के स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूरे होने को देखते हुए लिया गया है जो वर्ष 2025 में होगा। इस मिशन का लक्ष्य है कि 2025 तक देश के हर गांव में संघ की पहुंच हो जाए। इसके लिए देशव्यापी जनजागरण अभियान की शुरुआत सितंबर 2021 से होगी। यह शुरुआत ढाई लाख स्थानों से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। इनका प्रशिक्षण अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा लोगों तक अपनी पैठ बनाने के लिए संघ कोरोना जागरूकता को भी माध्यम बनाएगा।

संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी राष्ट्रीय टोली के साथ चित्रकूट में संगठनात्मक मजबूती को लेकर वृहद चिंतन कर रहे हैं। इसमें देशभर के क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक भी शामिल हैं। आरोग्य धाम में चल रही इस अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का मुख्य विषय आधिकारिक तौर पर संगठनात्मक मुद्दे ही बताए जा रहे हैं, लेकिन अगले साल उप्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर संघ की **रणनीति पर चर्चा** के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पहले दो दिन की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर संघ की आगामी भूमिका क्या होगी इस पर मंथन होना तो बताया गया है। लेकिन इसके निहितार्थ पर नजर डाले तो यह संगठनात्मक विस्तार की कवायद है। कोरोनाकाल के बाद से संघ की शाखाओं में नियमितता में कमी आई है तो संपर्क भी घटा है। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए अब संघ कोरोना को ही अपना माध्यम बनाएगा। संघ के कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर जहां कोरोना से मदद को लेकर लोगों के बीच पहुंचेगे। इसके लिए देशव्यापी कार्यकर्ता प्रशिक्षण आयोजित कर ढाई लाख स्थानों पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सितंबर में संघ वृहद जनजागरण अभियान चलाने जा रहा है जिसके जरिए हर गांव, हर बस्ती तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर संघ की बैठक में वृहद मंथन किया गया। इस पर यह निर्णय लिया गया है कि हर गांव हर मंडल तक ईकाई शाखा को मजबूत किया जाए। नीचे तक संघ की पकड़ और पहुंच ज्यादा से ज्यादा होने को लेकर लंबी चौड़ी योजना तैयार किए जाने पर वृहद विमर्श किया गया है। इस मामले पर स्वयं संघ प्रमुख और राष्ट्रीय टोली गंभीरता से काम कर रही है। माना जा रहा है इस संपर्क पहुंच की शुरुआत उप्र से होगी जहां अगले साल चुनाव होने हैं। इसके बहाने संघ अपनी जमीन पकड़ बनाते हुए जमीनी हालातों से और करीब से वाकिफ हो सकेगा जो आगे की चुनावी रणनीति में सहायक होगा। यह भी कहा जा रहा है कि संघ अब

असंतोष पर संघ का मरहम

कोरोना की दूसरी लहर में उप्र सरकार के कामकाज को लेकर जमीनी स्तर पर जनमानस में असंतोष बढ़ा है। यह असंतोष उप्र चुनावों पर असर डाल सकता है। लिहाजा संघ अखिल भारतीय बैठक में इसकी काट की तैयारी कर ली है। हालांकि इस काट को संगठनात्मक चोला पहनाया गया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के आधिकारिक बयान में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए देशव्यापी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षित कार्यकर्ता लगभग ढाई लाख स्थानों पर पहुंचेंगे। उन्होंने संघ की 39 हजार शाखाओं में 27 हजार के पुनः मैदान में प्रारंभ होने की जानकारी दी। इससे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि संघ की यह कवायद उप्र सहित अन्य चुनावों को लेकर है। इसके पीछे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर अपनी रीति-नीति से न केवल अवगत कराना है बल्कि लोगों के मन में संघ के सेवा भाव से अपने प्रति जुड़ाव महसूस कराना भी है।

डिजिटलाइजेशन की दिशा में भी तेजी से बढ़ने की तैयारी में है और सोशल मीडिया के जरिए साइबर स्पेस में अपना प्रभावी दखल पर मंथन कर रहा है।

संघ की प्रांत प्रचारक बैठक में कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों की व्यापक रूप से चर्चा हुई तथा प्रांतो में हुए सेवा कार्यों की समीक्षा की गई। स्वयंसेवकों द्वारा संचालित वैक्सीन टीकाकरण के लिए सुविधा केंद्र व प्रोत्साहन के अभियानों की भी समीक्षा की गई। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रांत प्रचारकों से यह जानने की भी कोशिश की गई कि दूसरी लहर में केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया है। इसको लेकर कयास है कि संघ यह जानना चाह रहा है कि लोगों की सोच केंद्र सरकार को लेकर क्या है ताकि आगे इसे सुधारने की रणनीति तय की जा सके।

कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए पूरे देश में शासन-प्रशासन का सहयोग करने एवं संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी उचित समय पर लोगों तक पहुंचाने यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख स्थानों तक पहुंचेंगे। इस संबंध में कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना पीड़ितों तक सरकारी सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा उन्हें चिन्हित कर संघ कार्यकर्ता आवश्यक मदद पहुंचाएंगे और अपना संवाद स्थापित करेंगे।

जनजागरण अभियान में हर गांव व हर बस्ती में स्वयंसेवी लोगों और संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि इसके जरिए संघ हर घर में अपनी दस्तक देते हुए अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण में कोरोना से बचाव के लिए बच्चों व माताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक सावधानियां व उपायों को शामिल किया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना प्रकोप समाप्त होने के बाद स्थितियां सामान्य हो रही हैं। लिहाजा अब तेजी से संघ वापस मैदान में अपनी शाखाओं का संचालन प्रारंभ करे। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि देशभर में वर्तमान में कुल 39,454 शाखाएं संचालित हो रही हैं जिसमें 27,166 शाखाएं अब मैदान में लग रही हैं। संघ ने कोरोनाकाल में डिजिटल तकनीकि को बड़े पैमाने पर अपनाया है। इस संबंध में बताया गया कि देशभर में 12,288 ई-शाखाएं चल रही हैं। साप्ताहिक मिलन की संख्या 10,130 बताई गई जिसमें प्रत्यक्ष मैदानी मिलन 6510 पुनः प्रारंभ हो गए हैं। साथ ही 3620 ई-मिलन चल रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन काल में विशेष रूप से प्रारंभ हुए कुटुंब मिलन देशभर में 9637 हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी संघ ने तैयारियां की हैं। इस दौरान संघ बेहद सक्रिय दिखाई देगा। क्षेत्र प्रचारकों और प्रांत प्रचारकों से कोरोना की थर्ड वेव को लेकर प्लान मांगा गया है। उनसे यह भी पूछा गया है कि सेकंड वेव में संघ के कार्यकर्ता जमीन पर क्यों नहीं दिखे? सेवा कार्य को लेकर संघ की चर्चा क्यों नहीं हुई? सभी को हिदायत दी गई है कि थर्ड वेव में संघ की चर्चा सेवा कार्यों के लिए होनी चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। हालांकि अभी प्लान फाइनल होना बाकी है। यह जानकारी भी सामने आई है कि संघ जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ साइबर स्पेस में भी प्रभावी भूमिका में आना चाह रहा है। कई प्रांत प्रचारकों ने इस संबंध में सुझाव भी दिए हैं। जिसको लेकर अब संघ के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में भी सक्रिय करने पर विचार किया जा रहा है। लिहाजा आगामी समय में भाजपा की आईटी विंग की तरह संघ की डिजिटल टोली देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।

संघ की छवि को लेकर अभी दुविधा है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन और जनसंख्या के खिलाफ कानून बनाने के मुद्दों पर जमकर चर्चा हो रही है। कोरोना में शाखाओं पर लगी रोक के बाद अब इन्हें सामान्य माहौल में फिर से शुरू करने की प्रोसेस को लेकर भी चर्चा हो रही है। दरअसल, पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए शाखाओं की तालाबंदी नुकसानदेह साबित हो सकती है। लिहाजा, शाखाओं को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कैसे शुरू किया जाए, इसको लेकर भी एक चाक-चौबंद प्लान बनाने की दिशा में चर्चा हुई।

● **सुनील सिंह**

5 मुद्दों पर सरकार के लिए बनेगा संघ का संविधान

बताया जाता है कि बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के लिए संघ का संविधान बनेगा। बैठक में धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्रीय कानून की जरूरत को लेकर एकराय है। सूत्रों के मुताबिक, संघ मोदी सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखेगा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्रीय कानून बने। ऐसा करने वालों को गंभीर सजा हो। हालांकि अभी इस पर दुविधा है कि इस कानून को 2024 के मेनिफेस्टो में दर्ज कर उसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए या फिर लोकसभा चुनाव से पहले पारित कर इसे अपनी उपलब्धियों में गिनाया जाए? चर्चा धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून पर भी हुई है। साथ ही यह भी कि कानून के तहत सजा कैसी हो। साथ ही कार्रवाई का तरीका कितना सख्त या नर्म हो। संघ के सूत्रों का कहना है कि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका खुद ही घर वापसी चाहता है। इसके लिए किसी सख्ती की कोई जरूरत नहीं। तो एक बात तय है कि आने वाले समय में धर्म परिवर्तन की उल्टी गंगा भी बहने के मामले सामने आ सकते हैं। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी संघ के लिए चिंता का बड़ा सबब है। इस मुद्दे पर भी केंद्रीय कानून जल्द से जल्द लाने की रणनीति को लेकर भी विचार-विमर्श जारी है। सूत्रों की मानें तो उप्र का आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संघ ने प्लान लगभग तय कर लिया है। दरअसल, यह भी चर्चा है कि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हो रहे चुनाव में भी संघ का ही फॉर्मूला लगाया जा रहा है। कई विधायकों के टिकट कटने तय हैं। लिहाजा टिकट आवंटन से लेकर योगी की छवि में सुधार तक को लेकर संघ काम करेगा।

जमावट में जुटे नाथ

2018 में जीती बाजी 2020 में हारने वाले कमलनाथ अब 2023 में एक बार फिर से जीत का ताना-बाना बुन रहे हैं। इसके लिए वे जिलों से लेकर मुख्यालय तक जमावट की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जल्द ही कमलनाथ प्रदेशभर का दौरा भी करेंगे।

मप्र में भले ही विधानसभा के आम चुनाव होने में अभी दो साल का समय है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से चुनावी किला फतह करने के लिए गुपचुप रूप से तैयारी शुरू कर दी है। यानि जिस तरह की तैयारी भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है लगभग उसी पैटर्न पर कमलनाथ भी संगठन में जमावट कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने निचले स्तर के संगठन को मजबूत करने और निष्क्रिय नेताओं को हटाने की योजना बनाई है। फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान तीन विधानसभा और एक लोकसभा के उपचुनाव पर है।

इस बीच संगठन स्तर पर किए जाने वाले व्यापक फेरबदल में जिलाध्यक्षों से लेकर मंडलम और सेक्टर स्तर पर नए चेहरों को कमान देने की भी तैयारी की जा रही है। फेरबदल के पहले प्रदेश संगठन मंडलम और सेक्टर अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। इस बदलाव के लिए पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश के निचले स्तर तक दौरा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले चुके हैं। माना जा रहा है कि बदलाव में इस रिपोर्ट का अहम रोल रहने वाला है। बदलाव में इन संगठनात्मक पदों पर युवा और सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही पार्टी उन जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी कर चुकी है, जो या तो निष्क्रिय हैं या फिर लंबे समय से इन पदों पर काबिज बने हुए हैं। दरअसल पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणामों की उम्मीद लगी हुई है। इसकी वजह है बीते आम विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनावों में मिली जीत। यही वजह है कि अब निचले स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। दरअसल तीन साल पहले तत्कालीन प्रदेश प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश ने संगठन की मैदानी ताकत बढ़ाने के लिए भाजपा की तर्ज पर मंडलम और सेक्टर बनाने का फॉर्मूला तैयार कर प्रदेश में लागू कराया था।

प्रदेश में कांग्रेस के अभी लगभग 800 मंडलम और 500 से ज्यादा सेक्टर हैं। इनमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया था। उसके बाद से ही इनके पदाधिकारियों के दायित्वों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी वजह से एक ही पद पर कई-कई कार्यकर्ता बीते तीन सालों से कार्यरत हैं। करीब डेढ़ साल पहले अचानक हुए बड़े घटनाक्रम के चलते श्रीमंत और उनके समर्थकों द्वारा पार्टी छोड़ दिए जाने की वजह से खासतौर पर ग्वालियर-चंबल इलाके में जिलाध्यक्षों से लेकर मंडलम स्तर के सभी पद रिक्त हो गए थे, जिसमें से जिलों के अध्यक्ष तो बना दिए गए थे, लेकिन अन्य तमाम पद अब भी रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों को भरा जाना है। इस बीच सरकार जाने की वजह से भी बड़ी संख्या में मंडलम और सेक्टर की टीम निष्क्रिय हो चुकी है। यही वजह है कि अब संगठन में मैदानी स्तर पर मोर्चा संभालने वाली इन टीमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली गई है। इस बदलाव के लिए और पार्टी का मैदानी स्तर पर आंकलन करने के लिए ही बीते कुछ समय से प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव मैदानी टीम की परफॉर्मेंस परखने के लिए जिले स्तर तक के दौरे कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा जिलों के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर न केवल मौखिक रूप से फीडबैक लिया जा रहा है, बल्कि उनसे बीते सालों में किए गए आंदोलनों तक का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। इसके आधार पर ब्लॉक दर ब्लॉक की अलग से रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

लंबे समय से प्रदेश स्तर पर भी बदलाव का इंतजार कार्यकर्ताओं को बना हुआ है। इसमें अध्यक्ष से लेकर पूरी प्रदेश कार्यकारिणी तक शामिल है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष भले ही न बदलें, लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों में बदलाव होना तय है। यह बदलाव प्रदेश में दो साल बाद होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। फिलहाल **बीते तीन सालों से** प्रदेश की कमान कमलनाथ के हाथों में है। वे अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसके पहले जब वे मुख्यमंत्री बने थे, तब माना जा रहा था कि वे प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ के बेहद करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के संगठन में बदलाव को लेकर बयान आए हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही पीसीसी से लेकर मैदानी स्तर तक बड़ा बदलाव होना तय है।

● अरविंद नारद

युवाओं को मिलेगा मौका

प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के दौरान उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो ऊर्जावान होने के साथ ही लगातार सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि अब संगठन में प्रदेश स्तर पर होने वाले बदलावों में कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष की परंपरा को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के कई मोर्चा व प्रकोष्ठों में भी नियुक्तियां की जानी हैं। राष्ट्रीय स्तर से किए जाने वाले इन बदलावों के लिए प्रदेश के प्रभारी चारों राष्ट्रीय सचिव अपने-अपने प्रभार के संभागों के दौरे कर पूरी मैदानी जानकारी ली जा रही है। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के साथ ही उसका विस्तार करना है। यही वजह है कि पार्टी ने फैसला किया है कि जो निष्क्रिय हैं या फिर अक्षम पदाधिकारी हैं, उनकी जगह नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। पुराने कार्यकर्ताओं को भी कोई न कोई काम देकर उनका उपयोग किया जाएगा।

ओबीसी के आरक्षण की गर्माहट

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

सरकारी भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले में मप्र हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख (सालाना आय) करने पर भी विचार हुआ। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने बताया कि बैठक में पिछड़ा वर्ग के सभी विधायक, सांसद व मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसमें मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा को 14 प्रतिशत को बरकरार रखे जाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रक्रियागत तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेगी। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था, जब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार की तरफ से सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया। अब इस मामले में नियमानुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मप्र हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सहित अन्य सभी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए ओबीसी की सभी भर्तियां 14 प्रतिशत रिजर्वेशन के अनुसार करने का आदेश दिया है। 13 प्रतिशत रिजर्वेशन रिजर्व रखने का आदेश दिया है। दरअसल, रिजर्वेशन पर फैसले के इंतजार में भर्ती प्रक्रियाओं पर असर पड़ रहा था।

मप्र की राजनीति में ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। इस मुद्दे की आग तो कई सालों से सुलग रही हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर लपटें तभी उठती हैं, जब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों को कोई चुनावी फायदा नजर आता हो। इस बार भी यही हुआ है। फौरी तौर पर इसे आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के तीन उपचुनावों और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से खाली होने वाली राज्यसभा सीट के उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असलियत में यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी से जुड़ा मामला भी है। और यही कारण है कि सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर एक-दूसरे को राजनीतिक लाभ न लेने देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

दरअसल यह मुद्दा दो तीन और कारणों से भी उठा। इसमें पहला कारण यह था कि मोदी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर भाजपा ने यह प्रचारित किया कि उसने इसमें आरक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग का खास ध्यान रखा है। मप्र से आने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य और देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत को मंत्रिमंडल पुनर्गठन से 24 घंटे पहले कर्नाटक का राज्यपाल बना देने के फैसले से कई लोग चौंके थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र के ही सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को मंत्रिमंडल में लेकर और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देकर इस आरोप को हवा देने की गुंजाइश खत्म कर दी कि मप्र से एक महत्वपूर्ण विभाग छिन गया है। दूसरा एंगल राज्य सरकार द्वारा मप्र हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे से जुड़ा है। हाईकोर्ट पिछले करीब दो साल से राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले की सुनवाई कर रहा है। सरकार ने हाल ही में कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उसमें कहा गया है मप्र में ओबीसी की आबादी 50.9 प्रतिशत है। ओबीसी की आबादी के ये जिलेवार आंकड़े आधिकारिक रूप से पहली बार ऑन रिकार्ड सामने लाए गए हैं। जैसे ही इस हलफनामे की बात बाहर आई कांग्रेस को इस मामले को हवा देने का मौका मिल गया।

कांग्रेस इस मामले में क्यों कूदी इसके पीछे भी कारण है। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था। बाद में राज्य विधानसभा ने इसे सर्वानुमति से मंजूरी भी दे दी थी। वह मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही मप्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कोर्ट ने मामले पर स्टे दे दिया। तब से ही मामला न्यायालय के विचाराधीन है। हाईकोर्ट से फैसला कब आएगा और फैसला आने के बाद क्या वह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी जाएगा यह सब भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल प्रदेश के दोनों ही दलों खासकर कांग्रेस को इस मामले पर राजनीति करने का अच्छा अवसर मिल गया है और उसने इसे लपकने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं है।

मप्र में नए राज्यपाल मंगूभाई पटेल की नियुक्ति होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हाल ही में उनसे मिलने गए और मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने राज्यपाल को अवगत कराया है कि प्रदेश में आरक्षित और कमजोर वर्गों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसी के साथ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मसला जल्दी हल करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े वर्ग को उसके हक से वंचित कर रही है। कमलनाथ का बयान सामने आते ही राजनीति गरमाई और भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ यदि अपनी सरकार के समय इस मामले को ठीक से हैंडल करते और कोर्ट में पुख्ता तरीके से दलील देते तो यह नौबत नहीं आती। भाजपा के इस आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब तो वह सरकार में नहीं है, भाजपा ही कोर्ट में इस मामले पर पूरी ताकत से अपना पक्ष रख दे और ओबीसी को उसका वाजिब हक दिलाए। निश्चित रूप से ताजा हालात में इस मामले में कांग्रेस के बजाय भाजपा पर दबाव ज्यादा है।

● **बृजेश साहू**

सबसे सस्ती सोलर बिजली

सोलर से भी अब सस्ती बिजली बनेगी। रीवा के बाद आगर में प्रस्तावित 550 मेगावॉट सोलर परियोजना के लिए 12 कंपनियों में दो को चयनित किया गया है। 275-275 की दोनों यूनिटों के लिए दो कंपनियों में 2.44 और 2.45 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने का ऑफर सरकार को दिया है। ये सबसे सस्ती दर है। रीवा में सोलर से पैदा हो रही बिजली 2.97 रुपए प्रति यूनिट पड़ रही है। इस सस्ती बिजली का फिलहाल आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई राहत नहीं मिलेगी। मप्र में अभी बिजली के लिए जल विद्युत परियोजना, कोयला आधारित पावर प्लांट पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता था। पवन और सोलर एनर्जी की नाममात्र भागीदारी थी, लेकिन इसकी बिजली महंगी पड़ती थी। पावर मैनेजमेंट अभी जो बिजली खरीदता है, उसमें सबसे सस्ती बिजली जल विद्युत वाली इकाइयों से मिलती है। उसमें भी मुश्किल ये है कि बांधों को सिंचाई और पेयजल के लिए अधिक इस्तेमाल के चलते बिजली इकाइयों को अमूमन साल में तीन से चार महीने ही चला पाते हैं। सोलर के रूप में अब तीसरा बड़ा विकल्प मिला है। पावर मैनेजमेंट कंपनी का दावा है कि सोलर प्लांट से मिलने वाली सस्ती बिजली का फायदा आने वाले समय में प्रदेश के आम लोगों को भी मिलेगा।

एक तरफ प्रदेश में भले ही सोलर से सस्ती बिजली बनाने का अनुबंध हो गया हो, लेकिन आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कारण कि बिजली कंपनी हर साल बिल में कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी करती रहती हैं। अभी भी प्रदेश में बिजली उत्पादन मांग की तुलना में अधिक हो रहा है। इसके चलते कई पावर प्लांटों को बंद करना पड़ता है। सरकार ने इन बिजली कंपनियों से न्यूनतम बिजली खरीदने का अनुबंध कर रखा है। इस अनुबंध की शर्त ये है कि बिजली खरीदो या नहीं, वो न्यूनतम राशि सरकार को हर महीने इन बिजली कंपनियों को देना ही पड़ता है। अभी 20 हजार करोड़ रुपए सालाना देने पड़ रहे हैं।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मुताबिक आगर में स्थापित हो रही 275-275 की दोनों सोलर यूनिटों के लिए बीमपाव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 2.444 रुपए प्रति यूनिट और अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 2.459 रुपए प्रति यूनिट का न्यूनतम ऑफर दिया था। बोली में शामिल 12 कंपनियों में उक्त दोनों कंपनियों का रेट सबसे कम था। दोनों यूनिटों के लिए रिवर्स बिड 2.73 रुपए प्रति यूनिट के बेस टैरिफ से प्रारंभ हुई थी। मप्र के इतिहास में यह सबसे सस्ती सोलर बिजली होगी।

एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक रीवा सौर परियोजना की तीनों 250-250 यूनिटों के लिए न्यूनतम सोलर टैरिफ 2.97 रुपए प्राप्त हुआ था। यह परियोजना 3 जनवरी, 2020 से पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। इसी की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष पहले 10 जुलाई, 2020 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अब आगर में 550 मेगावॉट के सोलर बिजली बनाने के लिए कंपनियों का चयन किया गया है।

मप्र विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष एसपीएस परिहार, प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा संजय दुबे, एमडी ऊर्जा विकास निगम एवं सीईओ रम्स दीपक सक्सेना और आयोग के सचिव शैलेंद्र सक्सेना की उपस्थिति में पूरी बोली की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस परियोजना पर 1950 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसे मार्च 2023 तक पूर्ण करते हुए बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। सोलर प्लांट लगाने के दौरान जहां 5500 वहीं संचालन में 500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। आगर में स्थापित होने वाली 550 मेगावॉट सोलर प्लांट के लिए 26 जनवरी को निविदा आमंत्रित की थी। निर्धारित विभिन्न अनुमोदनों और अनुमतियों के बाद आगर सौर पार्क के लिए निविदा की अंतिम तारीख 21 जून, 2021 तक 3 अंतरराष्ट्रीय, 9 राष्ट्रीय और 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। इनमें से न्यूनतम टैरिफ के आधार पर चुनी गई 12 कंपनियों में टाटा पावर, रि-न्यू पावर, बीमपाव एनर्जी, एनटीपीसी, अयान, रिन्यूएबल पावर, टोरेंट पावर, एसजेवीएन लिमिटेड, अज्यूर पावर, अल्जोमेह एनर्जी, एक्मे सोलर, स्प्रिंग ग्रीन और अवाडा एनर्जी ने रिवर्स ऑक्शन में भाग लिया था। सीईओ रम्स दीपक सक्सेना के मुताबिक जल्द ही 450 मेगावॉट वाले शाजापुर सौर पार्क के लिए भी 19 जुलाई को रिवर्स बोली लगेगी। इसके लिए 15 कंपनियों को शार्टलिस्ट किया गया है। वहीं नीमच में स्थापित होने वाले 500 मेगावॉट के सोलर एनर्जी के लिए 15 जुलाई तक प्रस्ताव प्राप्त करने की आखिरी तारीख थी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

1500 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट की तैयारी

रम्स (रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड) का गठन जुलाई-2015 में मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में हुआ था। रम्स द्वारा स्थापित रीवा सौर परियोजना के बाद अब मप्र में आगर 550 मेगावॉट, शाजापुर 450 मेगावॉट और नीमच 500 मेगावॉट कुल 1500 मेगावॉट की सौर परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि बिजली बनाने का खर्च के अनुसार उत्पादन कंपनी प्रति यूनिट रेट निर्धारित करती है। इस बिजली को उत्पादन प्लांट से आम लोगों के घरों तक पहुंचाने का ट्रांसमिशन चार्ज जुड़ता है। राज्य सरकार प्रति यूनिट ऊर्जा टैक्स लेती है, वो जुड़ता है। प्लांट से लेकर उपभोक्ताओं के ट्रांसफर तक बिजली पहुंचने में जो तकनीकी हानि होती है, उसका चार्ज जुड़ता है। वितरण ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली पहुंचने, बिलिंग होने और बिल वसूलने के बीच के गैप की राशि भी जुड़ती है। 2013-14 में जो बिजली कंपनियों से अनुबंध के तहत हर महीने फिक्स चार्ज (20 हजार करोड़ रुपए) देने पड़ते हैं वो चार्ज जुड़ता है। बिजली कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज, एफसीए चार्ज, कोयले की ढुलाई आदि का खर्च भी जुड़ता है। बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन, रखरखाव का खर्च आदि भी जुड़ता है। ये सब खर्चे जोड़कर प्लांट से 2.50 रुपए वाली बिजली आम उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते औसत 6 रुपए के लगभग पहुंच जाती है।

नक्सलियों का अरबन नेटवर्क

मप्र के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के जंगलों के अलावा अब नक्सली अरबन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। नक्सलियों का अरबन नेटवर्क मप्र के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। इसका खुलासा गत दिनों बालाघाट में पकड़ाए नक्सलियों को हथियार पहुंचाने वाले आठ लोगों ने किया है। इन आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद तीन राज्यों की पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपितों ने चार नाम और बताए हैं, जिनकी तलाश में महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में दबिश दी जा रही है। नक्सलियों को हथियार पहुंचाने वाले आरोपितों के कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस इस मामले को लेकर बालाघाट जिले के समीपस्थ छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्य के नक्सल ऑपरेशन से जुड़े पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा कर रही है। इधर, पुलिस को अभी सप्लायर्स द्वारा बताए गए संदिग्धों की तलाश है। जानकारी के अनुसार पुलिस की दो टीमें महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ भेजी गई हैं। जानकारी के अनुसार नक्सलियों के अरबन नेटवर्क का बालाघाट जिले के अलावा राजनांदगांव, कवर्धा, मंडला, गोंदिया, गढ़चिरोली सहित अन्य जिलों में लोकल सूत्र फैले हुए हैं। इसी लोकल सूत्र (बैक चैनल) की तलाश पुलिस भी कर रही है। सप्लायर्स ने जिन लोकल सूत्र का नाम बताया है, पुलिस उन्हीं संदिग्धों की तलाश कर रही है। हालांकि, पुलिस को अभी इन संदिग्धों को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी मामले में लेकर महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले और छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बालाघाट में हुई है। इस बैठक में नक्सली मूवमेंट और उनको सहयोग करने वाले अरबन नेटवर्क को लेकर बंद कमरे में चर्चा की गई है। विदित हो कि नक्सलियों को विस्फोटक, बंदूक सहित अन्य सामग्री सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र व राजस्थान राज्य के हैं। गिरफ्तार इन आठ आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

मास्टरमाइंड संजय चित्रोढ़ा ने गढ़चिरौली से एक चेन बनाई और गोंदिया को सेंटर पॉइंट बना लिया। यहां से सीधे वह नक्सलियों को तीनों राज्यों में हथियार बेचने लगा। नक्सलियों तक हथियार-बारूद समेत अन्य सामान पहुंचाने की अच्छी कीमत भी मिल जाती थी। पुलिस अब इस संगठित गिरोह को हथियार पहुंचाने वाले कारीगरों और कारखानों का भी सुराग जुटा रही है।

विस्तार दलम बढ़ा रहा नेटवर्क

डिंडोरी का जंगल अमरकंटक से लगा हुआ है। वर्ष 2014 में कोबरा बटालियन को यहां से हटा लिया गया। इसके कुछ महीनों बाद ही फिर से सरकार ने हॉकफोर्स तैनात करने का निर्णय लिया। यह स्थापित तथ्य है कि पुलिस बल की कमी होने के कारण ही बालाघाट, मंडला, अनूपपुर और डिंडोरी में नक्सली बढ़े। कुछ वर्ष पूर्व नक्सलियों ने विस्तार दलम का गठन कर मप्र में भी अपने विस्तार का खाका खींचा था। वे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में सक्रिय होने लगे। पुलिस को जानकारी मिली कि वे क्षेत्र में पैठ बनाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राज्य की पुलिस ने इसे बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर डिंडोरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित करने का अनुरोध किया। कुछ दिनों पूर्व ही केंद्र सरकार ने इसे नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि अब राज्य पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल मिलकर नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे।

अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए मशहूर मप्र में एक बार फिर नक्सली खतरे की आहट महसूस की जाने लगी है। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद माना जाने लगा था कि शेष मप्र में नक्सली गतिविधियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन समय के साथ यह अनुमान गलत साबित हो रहा है। पिछले लगभग 20 साल के अंदर नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए योजनाएं तो अनेक चलाई गईं, लेकिन वे उतनी कारगर नहीं हो सकीं जितनी उम्मीद की गई थी। इन वर्षों में जहां कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी है, वहीं मप्र में तीन ऐसे जिलों की पहचान की गई जहां इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं।

हाल ही में राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा डिंडोरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। बीते दो दशकों में यह प्रदेश का तीसरा जिला है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। इससे पहले बालाघाट और मंडला को इस श्रेणी के जिलों में रखा गया था। इन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को आधार मिलने का मूल कारण यहां के लोगों की गरीबी और अशिक्षा है। यह दलील पूरी तरह सच नहीं है कि सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर स्थानीय लोग नक्सलियों को मान्यता देते हैं। सच यह है कि आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से त्रस्त लोगों को नक्सली सुनियोजित ढंग से अपना मोहरा बनाते हैं और उन्हें बरगलाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि सरकार ने आदिवासी इलाकों पर काफी ध्यान दिया है, लेकिन रोजगार के साधन सीमित हैं। पुलिस के खुफिया तंत्र को इन क्षेत्रों से कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए नक्सली इस क्षेत्र की गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। गरीबी से त्रस्त लोगों को उकसाकर वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलियों की आवाजाही बढ़ने के पीछे विदेशी संस्थाओं से चंदे के रूप में मिल रहा आर्थिक संबल बड़ा कारण है। इसके जरिए वे गरीबों के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। हालांकि डिंडोरी में नक्सली समस्या नई नहीं है, लेकिन इसके विस्तार की सूचना चौंकाने वाली जरूर है। लंबे समय से यह क्षेत्र भी नक्सलियों के आने-जाने का प्रमुख मार्ग रहा है।

● **नवीन रघुवंशी**

मप्र में वन्य प्राणियों के साथ ही जलीय जंतुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब उसकी सहायक नदियों में घड़ियाल पहुंचने लगे हैं। ऐसे में उनके संरक्षण की व्यवस्था जरूरी है।

चंबल के घड़ियाल अब तलाश रहे सेकंड होम

दुनिया में चंबल नदी को पहचान दिलाने वाले घड़ियाल अब दूसरा घर (सेकंड होम) तलाश रहे हैं। 1978 में बने 435 किलोमीटर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में इसी साल फरवरी में 2176 घड़ियाल गिने गए हैं। चंबल में घड़ियालों की ये आबादी सर्वाधिक है। यहां पिछले एक साल में 317 घड़ियाल बढ़े हैं। यही वजह है कि अब घड़ियाल चंबल में मिलने वाली सहायक नदियों को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। इसकी पुष्टि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट (एमसीबीटी) की ओर से किए जा रहे रिसर्च में हुई है। पिछले दो साल में चंबल से माइग्रेट कर वीरपुर के पास से कूनो नदी के अपस्ट्रीम में 60 किमी तक यात्रा कर पहुंची मादा घड़ियाल ने यहां अंडे दिए हैं। कूनो में इस मादा का परिवार सुरक्षित है। इनका रहवास बनने के कारण कूनो में 50 छोटे घड़ियाल भी छोड़े गए हैं। इसी तरह श्योपुर जिले की सीमा में चंबल में मिलने वाली पार्वती नदी में भी 20 से ज्यादा घड़ियाल देखे गए हैं।

इन घड़ियालों ने यहां स्थायी घर बना लिया है। जलीय जीवों के मूवमेंट और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञ रेडियो टेलीमेटरी ट्रांसमीटर का सहारा ले रहे हैं। चंबल नदी में 20 और कूनो में 5 घड़ियालों की पूंछ पर ये ट्रांसमीटर फिट किया गया है। ट्रांसमीटर के जरिए मिलने वाले सिग्नल को ट्रेस करने पर ही मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर जेलाब्दीन को ये पता चला कि घड़ियालों ने कूनो और पार्वती के रहवास को भी एडॉप्ट कर लिया है। बता दें कि मप्र के वन्यजीव विभाग ने पिछले 10 साल में चंबल के घड़ियालों को सीधी जिले की सोन और खजुराहो की केन नदी में बसाने की कोशिश की है, लेकिन सोन नदी में नर घड़ियाल नहीं हैं इसलिए उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है। वहीं केन में भी घड़ियालों को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया। घड़ियाल अब खुद ही अपना दूसरा घर बना रहे हैं और इसके लिए पार्वती व कूनो उपयुक्त हैं। हालांकि ये दोनों नदियां छोटी हैं और चंबल के मुकाबले में इनमें न तो इतना साफ पानी है और न ही ये 12 महीने बहती हैं, लेकिन दोनों नदियों में अवैध रेत उत्खनन और दूसरे मानवीय खतरे कम हैं इसलिए इनमें घड़ियालों की मौजूदगी आने वाले कुछ सालों में और बढ़ सकती है।

मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर जेलाब्दीन कहते हैं किचंबल सेंक्चुरी में घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसलिए वे अब दूसरे घर बना रहे हैं। हमें चंबल में मिलने वाली पार्वती नदी में 20 और कूनो नदी में घड़ियाल का एक परिवार मिला है। ये छोटी आबादी है लेकिन इससे ये साफ है कि घड़ियालों ने इन नदियों को अपने घर के लिए चुन लिया है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य तीन राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें राजस्थान, मप्र और उप्र शामिल हैं। इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यत: चंबल नदी के रूप में ये अभयारण्य 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके कोर क्षेत्र में लगभग 400 किमी लंबी चंबल नदी आती है। इसी नदी पर एक दूसरा अभयारण्य भी है जो कोटा के पास है। इसका नाम जवाहर सागर अभयारण्य है। यह भी अत्यंत खूबसूरत है और वहां जाने वाले लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। इस क्षेत्र में चंबल अपने सबसे खूबसूरत स्वरूप में बहती दिखती है। यह नदी मुख्यत: घड़ियालों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें अन्य कई प्रकार के जीव-जंतु और जलचर भी पाए जाते हैं। यहां 96 प्रजातियों के जलीय और तटीय पौधे मिलते हैं। जीव-जंतुओं में मुख्यत: घड़ियालों के अलावा गंगा नदी की डॉल्फिन (मंडरायल से धौलपुर तक), मगरमच्छ, स्मूद कोटेड ऑटर (ऊदबिलाव), कछुओं की छह प्रजातियां और पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं।

विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी भी चंबल के एवियन फाउना को बढ़ाते हैं। कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी यहां पाए जाते हैं। इनमें इंडियन स्कीमर, ब्लैक बिल्ड टर्न, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, फैरुजिनस पोचार्ड, बार-हैडेड गूज, सारस क्रेन, ग्रेट थिक नी, इंडियन कोरसर, पालास फिश इगल, पैलिड हैरियर, ग्रेटर फ्लैमिंगो, लैसर फ्लैमिंगो, डारटर्स और ब्राउन हॉक आउल आदि शामिल हैं। स्मूद कोटेड ऑटर, घड़ियाल, सॉफ्ट शैल टरटल और इंडियन टेंट टरटल तो दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों में शामिल हैं। चंबल के तटों से लगे जंगलों में भालू, तेंदुए और भेड़िए भी नजर आ जाते हैं। नदी अभयारण्य के आसपास स्थित ऊंची चट्टानें लुप्त होते जा रहे गिद्धों के प्रजनन के लिए मुफीद साबित होती हैं। यहां के पानी में कभी-कभार दुर्लभ महाशिर मछली भी दिख जाती है। यह अभयारण्य भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के तहत संरक्षित है। इसका प्रशासनिक अधिकार तीनों राज्यों के वन विभागों के अधीन है।

● श्याम सिंह सिकरवार

घड़ियालों पर आया था संकटकाल

हालाँकि बीच में इस घड़ियाल अभयारण्य पर दाग लग गया था। 2007 के अंत में चंबल के घड़ियालों पर अचानक संकटकाल आ गया था। एक रहस्यमय बीमारी के चलते दिसंबर 2007 से फरवरी 2008 के बीच 120 घड़ियाल मारे गए थे। इनके बिसरे की जांच के बाद भी घड़ियालों की मौत का राज पूरी तरह से नहीं सुलझा। हालांकि शुरुआती जांच के बाद विशेषज्ञों ने घोषित कर दिया था कि घड़ियाल लीवर सिरोसिस (लीवर में इंफेक्शन) नामक बीमारी के चलते मारे जा रहे हैं लेकिन बाद में अलग बातें सामने आने लगीं और कहा जाने लगा कि घड़ियालों की किडनी में इंफेक्शन हुआ था।

अवैध हथियारों का गढ़ बना मप्र

पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले मप्र के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। पंजाब पुलिस ने बड़वानी आकर अवैध हथियार के तस्कर बलजीत सिंह उर्फ स्वीटी सिंह को उसके गांव से पकड़ा है। उसके पास से 3 पिस्टल मिली है। स्वीटी सिंह आजाद ग्रुप मुंगेर के नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रहा था, जिस पर वह अपने अवैध हथियारों की फोटो और वीडियो शेयर करता। जब खरीदार कीमत के बारे में पूछते थे, तो वह वाट्सऐप नंबर साझा करता था। इधर, डीजीपी पंजाब का कहना है कि देश के गैंगस्टर्स और अपराधियों को टॉप क्वालिटी वाले हथियार सप्लाई करने में मप्र तेजी से उभर रहा है।

पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा, मप्र के बड़वानी जिले के गांव उमरती निवासी स्वीटी सिंह को पंजाब और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में उच्च गुणवत्ता वाले अवैध हथियारों के निर्माण और आपूर्ति में लिप्त पाया गया है। कपूरथला पुलिस ने दो दिन पहले उसे गिरफ्तार करके 32 बोर की तीन पिस्टल और तीन मैगजीन भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में स्वीटी ने खुलासा किया कि उसके गांव उमरती में लगभग 40-45 घरों में से 20 से अधिक अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री के कारोबार में शामिल थे। खासकर 30 बोर और 32 बोर पिस्तौल। पुलिस स्टेशन फत्तूधींगा कपूरथला में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

पंजाब पुलिस के अनुसार विशेष रूप से, यह पिछले 8 महीनों में मप्र में अवैध हथियार निर्माण और आपूर्ति करने वाला तीसरा ऐसा मॉड्यूल है, जिसका पर्दाफाश किया गया है। इससे पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पंजाब में गैंगस्टरों, अपराधियों और कट्टरपंथियों को हथियारों की आपूर्ति करने वाले हथियार तस्करों की गिरफ्तारी की थी। इसमें मप्र में हथियारों की अवैध फैक्टरी सहित दो मॉड्यूल का पता लगाया था। 30 जून को गिरफ्तार लुटेरों ने खुलासा किया कि वे मप्र के बड़वानी स्थित तस्कर स्वीटी सिंह से हथियारों की आपूर्ति ले रहे थे। बदमाश पेट्रोल पंपों पर लूट के साथ-साथ किसानों से भी पैसे छीन रहे थे। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि इन सूचनाओं के बाद कपूरथला पुलिस ने स्वीटी सिंह का गिरफ्तारी वारंट हासिल किया। कपूरथला से पुलिस की एक विशेष टीम मप्र पुलिस के साथ बड़वानी भेजी गई। पुलिस ने स्वीटी सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी ने महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने के लिए नर्मदा नदी पार करके गिरफ्तारी से बचने का प्रयास भी किया, जो असफल रहा।

दिल्ली पुलिस पिछले 6 महीने में अवैध हथियार तस्करों पर नकेल कसने में कामयाब रही है। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2431 अवैध हथियार तस्करों को दबोचा। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ कुल 2040 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ था। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता डॉ. ईश सिंघल ने बताया कि दिल्ली में पैर जमाने की कोशिश कर रहे अवैध हथियार तस्करों को पकड़ने में काफी सफलता मिली है। एनएस श्रीवास्तव के पुलिस आयुक्त बनने के बाद अवैध हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उनके खिलाफ अभियान शुरू किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व अपराध शाखा समेत सभी यूनिटों ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। दिल्ली पुलिस ने 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक की अवधि में 2431 अवैध हथियार तस्करों को दबोचा। इनके खिलाफ 2040 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध हथियार तस्करों के कब्जे से कुल 1702 अवैध हथियार बरामद किए गए। इनमें 1493 कट्टे, 195 रिवाल्वर-पिस्टल और 14 राइफल बरामद की गईं। इसके अलावा अवैध हथियार तस्करों के कब्जे से 3198 कारतूस भी बरामद किए गए। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस का अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान अभी जारी है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस समय दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा अवैध हथियार मप्र से आते हैं। मप्र से इस समय आ रहे अवैध हथियार की क्वालिटी अन्य जगहों से अच्छी है और सस्ते भी होते हैं। एक समय अवैध हथियार का गढ़ माना जाने वाला मुंगेर, बिहार से अब हथियार कम आ रहे हैं। यहां पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। मेरठ व अलीगढ़ समेत पश्चिमी उप्र से भी दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई होते हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

ड्रग पैडलर्स का हब भी बना प्रदेश

अवैध हथियारों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध मप्र इन दिनों ड्रग पैडलर की पसंदीदा जगह बना हुआ है। स्पेशल सेल से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मप्र के दूरदराज के इलाकों में स्थित मेक शिफ्ट फैक्ट्री में हेरोइन को प्रोसेस करने का धंधा चल रहा है, जहां कभी अवैध हथियारों का निर्माण होता था और वहां से उनकी तस्करी होती थी। स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया कि मप्र का शिवपुरी इन दिनों ड्रग पैडलर की पसंदीदा जगह बना हुआ है। यहां पर कई सारी मेकशिफ्ट फैक्ट्रियां हैं, जहां हेरोइन को प्रोसेस किया जाता है। उन्होंने कहा कि ईरान से समुद्र के रास्ते हेरोइन को मुंबई लाया जाता है और वहां से सड़क मार्ग द्वारा मप्र के शिवपुरी में लाकर मेकशिफ्ट फैक्ट्रियों में इन्हें प्रोसेस किया जाता है। हेरोइन को प्रोसेस करने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। विशेष आयुक्त ने बताया कि मप्र पहले अपने अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बदलते समय में अब मप्र नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यहां कई सारी मेक शिफ्ट फैक्ट्रियां हैं, जहां हेरोइन को प्रोसेस करने के बाद उन फैक्ट्रियों को दूसरी जगह इंस्टॉल किया जाता है ताकि किसी को शक न हो सके। अधिकारी के मुताबिक, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में उगाई जाने वाली अफीम को इम्पोर्ट किए जाने वाले जैसे टैल्क स्टोन, जिप्सम पाउडर में छिपाया जाता है। इसके बाद कंटेनरों में उसे ईरान के चाबहार बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। वहां से हेरोइन की ये खेप जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई भेज दी जाती है। यहां लाए जाने के बाद हेरोइन को बाकी समान से अलग कर उसे मप्र के शिवपुरी में प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता था, जहां से उसे प्रोसेस करने के बाद फाइन क्वालिटी में तब्दील कर आगे सप्लाई किया जाता था।

2022 में उप्र सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर से क्षेत्रीय क्षत्रपों और उनकी पार्टी की ताकत का आंकलन करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि भाजपा को इस समय कांग्रेस से नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती से डर लग रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने भाजपा को धूल चटाई है, उससे एक बात तो यह साफ हो गई है कि भारतीय राजनीति में असली सिकंदर क्षेत्रीय पार्टियां हैं।

● राजेंद्र आगाल

देश में आज भले ही दो राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द राजनीति होती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां और उनके क्षत्रपों के सहयोग के बिना इन पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों के महत्व को कमतर नहीं आंका जा सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज 13 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद क्षेत्रीय पार्टियों की धमक ने भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोच में डाल दिया है। इसका असर 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी महसूस किया जा रहा है। उप्र में सपा, बसपा तो पंजाब में आम आदमी की पार्टी ने बड़ी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बड़ी पार्टियों की कोशिश है कि वे चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों में एकता न होने दे। इसके लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के क्षत्रपों को मंत्री बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की है।

एक जमाना था जब एक भारत हुआ करता था जिसमें ऐसे नेता हुआ करते थे जो किसी नारे या अपनी किसी भव्य भंगिमा से इतिहास की धारा बदल सकते थे। वे सभी वैश्विक ब्रांड थे और उनका कद उनकी पार्टियों से भी बड़ा था। जरा उनमें से कुछ नामों को याद भर कीजिए, आधुनिकता के पैरोकार और राष्ट्र निर्माता, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की महान पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय नवीकरण का औजार बना दिया था। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने, जो लोकप्रियता के चार्ट में हमेशा सबसे ऊपर रहीं, न केवल सत्ता, व्यामोह और करिश्मे के बीच बेजोड़ संतुलन बनाया बल्कि भारत माता की भूमिका भी निभाई जिसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और यदि भारतीय राजनीति में दक्षिण पंथ की तरफ देखें तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक ऐसा नेता दिखाई पड़ेगा, जो ठेठ सियासत की सीमाओं को तोड़कर महान और साहसपूर्ण कदम उठाते थे। ये नेता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। लेकिन ये सब तो गुजरे जमाने की बात है।

क्षेत्रीय क्षत्रपों का मनोबल हाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार ने मौजूदा समय में महाराष्ट्र में सत्तासीन तीन पार्टियों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी का मनोबल बढ़ा दिया है। उधर सपा, बसपा, आप, एआईएमआईएम को भी संजीवनी मिल गई है। इन पार्टियों के साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। इससे भाजपा और कांग्रेस के माथे पर पसीना आने लगा है। वैसे देखा जाए तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का वजूद हमेशा ही रहा है। आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भी और आजादी के बाद भी **लंबे समय तक।** लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ उनसे संबंधित राज्यों तक ही सीमित रही। यह स्थिति लगभग 1980 के दशक की शुरुआत से तब तक बनी रही जब तक कि राष्ट्रीय आंदोलन की कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तमाम तरह की क्षेत्रीय आकांक्षाओं, अस्मिताओं और संवेदनाओं से अपने को जोड़े रही और उनका पर्याप्त आदर करती रही। लेकिन 1980 के दशक के मध्य तक तेलुगू देशम पार्टी और असम गण परिषद जैसे नए क्षेत्रीय दलों का धमाकेदार उदय हुआ। उसी दशक के खत्म होते-होते देश में गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हो गया और उसी के साथ शुरू हुआ राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दखल और दबदबा।

1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में वामपंथी दलों और भाजपा के बाहरी समर्थन से बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से लेकर मई 2014 तक डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई में चली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की

13 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का राज

देश में 13 राज्य ऐसे हैं जहां किसी क्षेत्रीय दल की सरकार है। इन 13 में से 7 राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं। इनमें से 5 में भाजपा सहयोगी पार्टी तो 2 जगह कांग्रेस का गठबंधन है।

	राज्य	मुख्यमंत्री (क्षेत्रीय दल)
	महाराष्ट्र	उद्धव ठाकरे (शिवेसना)
●	बिहार	नीतीश कुमार (जदयू)
●	मेघालय	कोनरॉड संगमा (एनपीपी)
●	नागालैंड	नेफ्यू रियो (एनडीपीपी)
●	सिक्किम	प्रेम सिंह तमांग (एसकेएम)
●	मिजोरम	जोरमथंगा (एमएनएफ)
●	झारखंड	हेमंत सोरेन (झामुमो)

6 ऐसे राज्य जहां अपने दम पर क्षेत्रीय दलों ने सरकार बनाई

	राज्य	मुख्यमंत्री (क्षेत्रीय दल)
●	तमिलनाडु	एमके स्टालिन (डीएमके)
●	आंध्र प्रदेश	जीएम रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस)
●	तेलंगाना	के चंद्रशेखर राव (टीआरएस)
●	ओडिशा	नवीन पटनायक (बीजद)
●	प. बंगाल	ममता बनर्जी (तृणमूल)
●	दिल्ली	अरविंद केजरीवाल (आप)

सरकार तक लगभग हर सरकार में क्षेत्रीय दलों की अहमियत बनी रही। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस तरह अपनी जीत का डंका बजाया था और फिर राज्यों के विधानसभा चुनावों में उसने अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया, उससे कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह मान लिया था कि अब देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के दिन लद गए हैं। उनकी इस धारणा को 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी और ज्यादा पुष्ट किया। लेकिन उस आम चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उस धारणा का खंडन करते हुए साबित किया कि क्षेत्रीय दलों का वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है और वे राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बनाए रखते हुए राष्ट्रीय दलों की मजबूरी बने रहेंगे।

यहां ही राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा

देश में इस समय मप्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य हैं जहां किसी भी चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होता है। हालांकि इनमें से कर्नाटक, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा में तो राष्ट्रीय दलों के साथ ही क्षेत्रीय दल भी वजूद में हैं और कई मौकों पर वे सत्ता समीकरणों को प्रभावित भी करते रहते हैं। कुल मिलाकर देश के दो तिहाई से ज्यादा राज्य ऐसे हैं, जहां क्षेत्रीय दल न सिर्फ पूरे दमखम के साथ वजूद में हैं, बल्कि कई राज्यों में तो अपने अकेले के बूते सत्ता पर काबिज हैं तो कई राज्यों में राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता में साझेदार बने हुए हैं। विधानसभा चुनावों की बात करें तो महाराष्ट्र में दो गठबंधनों के बीच मुकाबला था और दोनों गठबंधनों की अगुवाई राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस कर रहे थे। दोनों गठबंधन में एक-एक क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी। भाजपा के साथ शिवसेना और कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)। चुनाव नतीजे आए तो **दोनों क्षेत्रीय पार्टियां** राष्ट्रीय पार्टियों पर भारी पड़ी। शिवसेना ने तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा से नाता तोड़कर उसका सरकार बनाने का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। दूसरी ओर एनसीपी ने भी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर अपने पर उसकी निर्भरता को और बढ़ा दिया।

क्षत्रपों को परास्त करना होगी भाजपा की आगे की रणनीति

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश के क्षेत्रीय क्षत्रपों में एक नई उम्मीद जगाई है। राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। पिछले 7 वर्षों में देश के अंदर इस तरह का राजनीतिक माहौल पहले कभी नहीं देखा गया, जितना बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद अब देखा जा रहा है। बंगाल जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विरोध की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां काफी खुश नजर आ रही हैं। हालांकि, भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्होंने बंगाल में भाजपा को 3 से 77 सीट तक पहुंचाया है। इसके बावजूद सवाल उठना लाजिमी है कि जो भाजपा राज्य में सरकार बनाने का ही नहीं, 200 पार का दावा कर रही थी, उससे कहां चूक हुई? ऐसे में यह भी सवाल उठेंगे कि जिस भाजपा का स्ट्राइक रेट राजस्थान, मप्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में तो बढ़िया रहता है, वहीं भाजपा जब अकेले हरियाणा, बिहार, तमिलानाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में लड़ती है तो स्थितियां क्यों बदल जाती है?

हरियाणा में भी हालांकि भाजपा ने बहुमत से दूर रहने के बावजूद सरकार बना ली लेकिन इसके लिए उसे राज्य के नवजात क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को न सिर्फ सत्ता में साझेदार बनाना पड़ा बल्कि उसकी शर्तों के आगे समर्पण भी करना पड़ा। झारखंड में भी एक क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा से आगे रहा। गठबंधन में कांग्रेस को उसका नेतृत्व कबूल करना पड़ा। पिछली बार भाजपा ने भी इस राज्य में एक अन्य क्षेत्रीय दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके सहयोग से ही सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार उसने अकेले चुनाव लड़ा जिसका खामियाजा भी उसे सत्ता गंवाने के रूप में भुगतना पड़ा। उधर आजसू को पिछली बार की तुलना में इस बार एक सीट का नुकसान हुआ लेकिन वह अपना वोट प्रतिशत बढाने में कामयाब रहा।

कांग्रेस ने कई राज्यों से गंवाई सत्ता

केरल में वैसे तो राजनीति की धुरी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ही है लेकिन इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों के समर्थन की दरकार रहती है। वहां इस समय माकपा के नेतृत्व वाले वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है। दक्षिण भारत के सबसे छोटे राज्य पुदुचेरी में अब भाजपा की सरकार है लेकिन वहां तमिलनाडु की दोनों प्रमुख द्रमुक पार्टियों का भी खासा असर है और वे कई बार वहां सत्ता में आ चुकी हैं। वैसे 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही जिन 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें भी आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और सिक्किम में क्षेत्रीय दलों का ही बोलबाला रहा था। इन राज्यों में कहीं तो भाजपा और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के मुकाबले अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं पर वे क्षेत्रीय दलों के छतरी के नीचे रहकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकीं।

आंध्रप्रदेश में तो मुख्य मुकाबला ही दो क्षेत्रीय पार्टियों वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगू देशम पार्टी के बीच था, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस ने न सिर्फ तेलुगू देशम पार्टी को करारी शिकस्त देकर सत्ता से बाहर कर दिया बल्कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का सफाया कर दिया और भाजपा को तो पैर रखने तक की जगह नहीं दी। तेलंगाना में वहां की क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति दोनों राष्ट्रीय पार्टियों और तेलुगू देशम को हराकर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। तमिलनाडु में भी द्रविड आंदोलन से निकली दो क्षेत्रीय पार्टियां-द्रविड मुनैत्र कडगम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनैत्र कडगम (एआईएडीएमके) ही लंबे समय से बारी-बारी से राज कर रही हैं और राष्ट्रीय पार्टियां उनकी सहयोगी की भूमिका में रहकर अपना वजूद बनाने की कोशिश करती हैं। यह सिलसिला अभी भी कायम है। पूर्वी भारत में तटीय राज्य ओडिशा में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। हालांकि तीन बार वहां गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय दल के रूप में स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी और जनता दल की सरकार भी रही, लेकिन पिछले दो दशक से लगातार वहां बीजू जनता दल के रूप में क्षेत्रीय पार्टी शासन कर रही है।

पंजाब में भी उप्र जैसी स्थिति

पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी लंबे समय से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा हैं और इस बार भी वहां यह सिलसिला बना रहा। पिछले 25 सालों से सत्ता पर काबिज सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता से बाहर हुआ और उसकी जगह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सत्ता पर काबिज हो गया। अरुणाचल प्रदेश जरूर अपवाद रहा, जहां भाजपा पहली बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब तो रही लेकिन इस कामयाबी के लिए उसे भी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों दामन थामना पड़ा। असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा कायम है। इन सभी प्रदेशों के अलावा सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला उप्र किसी समय कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था लेकिन 1990 से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक वहां भी दो क्षेत्रीय दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ही दबदबा बना रहा। भाजपा ने तो पहले राम मंदिर आंदोलन और बाद में मोदी लहर के सहारे वहां अपने पैर जमा लिए और अब वह सत्ता पर भी काबिज है लेकिन कांग्रेस अभी भी वहां हाशिए पर ही है। विपक्ष के रूप में वहां अभी दोनों क्षेत्रीय पार्टियां ही भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में हैं। पंजाब की स्थिति भी उप्र जैसी ही है। वहां भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल के बीच ही हमेशा मुकाबला होता है और भाजपा अकाली दल की सहयोगी की भूमिका में रहती है।

बीते साल पूर्ण रूप से केंद्र शासित राज्य में तब्दील कर दिए गए जम्मू-कश्मीर में भी भाजपा और कांग्रेस की असरदार मौजूदगी के बावजूद राजनीति की धुरी वहां की क्षेत्रीय पार्टियां नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही रहती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटे छोटे से तटीय राज्य गोवा में हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहता है, लेकिन कई छोटी-

छोटी क्षेत्रीय पार्टियां दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच सत्ता समीकरण को प्रभावित करती हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र और विविधता से भरे देश में इतनी अधिक क्षेत्रीय पार्टियों का होना कोई अचरज की बात नहीं है, मगर अफसोस की बात यही है कि ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां व्यक्ति आधारित हैं और एक व्यक्ति या उसके परिवार से संचालित हो रही हैं। यह स्थिति लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है।

याद कीजिए, 1997 में कोलकाता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की शीर्ष बैठक में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, कांग्रेस अपने आप में सबसे सफल गठजोड़ है। जिस समय तक इंदिरा गांधी राजनीतिक परिदृश्य पर थीं, ऐसा था। कांग्रेस को यह महसूस करने में थोड़ा और वक्त लगा कि वह अब सत्ता सौंपी जाने के लिए स्वाभाविक पसंद नहीं है। लेकिन भाजपा को सबक सीखने में देर नहीं लगी। मई, 1996 में अपनी 13 दिन की सरकार के बाद उसने 1998 के आम चुनावों में 18 पार्टियों का गठजोड़ बनाया और 1999 में साबित कर दिया कि गठजोड़ अपरिहार्य हैं। आज, 28 में से केवल 7 राज्यों (राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मप्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली) में कांग्रेस और भाजपा के बीच आमने-सामने की चुनावी लड़ाई होती है। इन दोनों दलों के पास लोकसभा की कुल सीटों का महज छठा हिस्सा है। उप्र और बिहार में कांग्रेस सीमांत खिलाड़ी है। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो वह केरल, आंध्रप्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। चुनाव के मौसम में, राज्यों के बड़े क्षत्रप राष्ट्रीय नेताओं को उनकी महत्वहीनता की याद दिला रहे हैं। वंश या राष्ट्रीय मंच पर अनुभव के बूते अब ठोस जनाधार वाले कथित प्रांतीय नेताओं पर धौंस नहीं जमाया जा सकता।

2024 तक चलेगा मोदी मैजिक?

ऐसे में क्या 'मोदी मैजिक' क्षेत्रीय क्षत्रपों के गढ़ में ध्वस्त होता जा रहा है? मोदी और अमित शाह जैसा स्टार प्रचारक और बेहतर रणनीतिकार के बावजूद भाजपा क्यों रीजनल पार्टियों के आगे नतमस्तक होती जा रही है? हरियाणा, बिहार, उप्र, तमिलानाडु, महाराष्ट्र, पं बंगाल, ओडिशा और असम में रीजनल पार्टियां काफी मजबूत हैं। ऐसे में देश में रीजनल पार्टियां और उसके किले में भाजपा का ध्वस्त होने के मायने क्या होंगे और इसके राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर क्या दूरगामी असर पड़ेगा? भाजपा नेताओं के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि भाजपा भविष्य की राजनीति करती है। यह हाल के वर्षों में भाजपा की रणनीति देखकर भी लगता है। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति भी साल 2018 से बनाई जा रही थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसके अच्छे नतीजे भी सामने आए थे, जब भाजपा ने 18 लोकसभा सीट जीतकर सबको हैरान कर दिया था। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2019 वाला जलवा बरकरार नहीं रख सकी। हालांकि, साल 2016 में जो पार्टी 3 सीट लाई थी वह वह इस बार 77 तक जरूर पहुंच गई है।

क्या भारत के लिए महत्वहीन होती जा रही है कांग्रेस

भारतीय राजनीति में केजरीवाल, ओवैसी और जगनमोहन रेड्डी चमक गए। लेकिन कांग्रेस की गत नहीं बदली। गांधी परिवार का दरबार बन चुकी सबसे पुरानी पार्टी नए भारत में मजाक बनकर रह गई है। सफल राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिभाशाली नेताओं को मौके देती हैं। वक्त की नजाकत भांप उन्हें आगे करती हैं। भाजपा को ही लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी इसके उदाहरण हैं। राम मंदिर आंदोलन के जरिए पार्टी को उत्तर भारत में स्थापित करने वाले लालकृष्ण आडवाणी सत्ता मिलने पर भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। पार्टी ने आगे बढ़ने के लिए वाजपेयी पर भरोसा जताया। 2004 और उसके बाद दो बार आडवाणी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेशकर भाजपा जब चुनाव हारी तो बदलावों ने नरेंद्र मोदी का रास्ता खोल दिया। वहीं दिल्ली में दरबारियों से घिरी कांग्रेस अपने ही मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को निपटाने में व्यस्त रही। याद कीजिए वह दौर जब, पश्चिम बंगाल के दिग्गज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर रे कहते रहे कि वह मरने से पहले पश्चिम बंगाल में वामपंथी राज को ढहते हुए देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी इस लड़ाई के लिए तैयार भी थीं। लेकिन ममता का कद बड़ा न हो जाए, इसीलिए दिल्ली से लगाम लगा दी गई। झल्लाहट में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाई और आखिरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता से वामदलों को बेदखल कर दिया। कांग्रेस को इंदिरा गांधी के दौर से ही परिवार भक्त नेता पसंद हैं। ऐसे नेता जो गांधी परिवार की हां में हां मिलाते रहे। हालांकि इंदिरा गांधी खुद भी एक बड़ी नेता थीं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध और जनता के बीच जाकर राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया।

क्षेत्रीय दलों से कैसे पार पाएगी भाजपा

जानकार बताते हैं कि भाजपा का इतिहास रहा है कि जहां मुख्य मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से होता है (उप्र को छोड़ दें) वहां कमजोर साबित होती है। हालांकि, कई राज्यों में भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर कांग्रेस या दूसरी रीजनल पार्टियों को हराती भी रही है। महाराष्ट्र, बिहार, असम, हरियाणा, नार्थ-ईस्ट के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन कर जीत दर्ज करती आ रही है। एक उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां पर भाजपा और शिवसेना साथ-साथ चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना ने भाजपा को झटका देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया।

ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उप्र विधानसभा चुनाव में बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम का असर कमोबेश दिखेगा। ऐसे में भाजपा के पास क्या विकल्प होंगे? साल 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अगले ही साल लालू-नीतीश की जोड़ी ने बिहार में भाजपा को धूल चटा दी थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी के नवीन पटनायक ने भी यही कारनामा किया था।

क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण

भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय और विभिन्न धर्मों का देश है। भारत जैसे विशाल एवं विभिन्नताओं से भरे देश में क्षेत्रीय दलों के उदय के अनेक कारण हैं। पहला प्रमुख कारण जातीय, सांस्कृतिक एव भाषायी विभिन्नताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं जिन पर राष्ट्रीय दलों या केंद्रीय नेताओं का ध्यान नहीं जाता परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। दूसरा केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से करता रहा है। केंद्र की शक्तियों के केंद्रीयकरण की इसी प्रवृत्ति के कारण अनेक क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है। तीसरा, उत्तरी भारत की प्रधानता को लेकर आशंकाएं भी क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण रहा है। क्षेत्रीय दलों के उदय का चौथा प्रमुख कारण कांग्रेस दल की संगठनात्मक दोष भी है। केंद्र में कांग्रेस की स्थिति तो मजबूत थी परंतु राज्यों में कांग्रेस संगठन बिखरता जा रहा था। परिणामस्वरूप कांग्रेस में संगठन संबंधी फूट और कमजोरियां आ गईं और राज्य स्तर के अनेक नेताओं ने क्षेत्रीय दलों के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। पांचवा, क्षेत्रीय दलों उदय का कारण जातीय असंतोष भी रहा है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की मांग के लिए भी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है।

तीसरे ध्रुव की कवायद

चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन के लिए जगह भांपने या बनाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई चुनाव नजदीक नहीं होने के बावजूद अगर इस दिशा में कोई गतिविधि होती दिखती है तो वह लोगों का ध्यान खींचती है। इस लिहाज से देखें तो पिछले कुछ समय से चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जा रहे प्रशांत किशोर के कई दलों के नेताओं से मिलने को विपक्ष का नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिशों के तहत देखा जा रहा है। हालांकि देशभर में महामारी के संकट और उसके बीच सीमाओं में चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों में यह कवायद कितना रंग ला पाएगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक पखवाड़े के भीतर प्रशांत किशोर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार से तीन बार मुलाकात के संकेतों को समझने की कोशिश स्वाभाविक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद इस बात की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का विकल्प खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जिस दायरे में इस विकल्प पर चर्चा हो रही है, उसमें यह देखने की बात होगी कि इसमें शामिल पार्टियां क्या तीसरा मोर्चा खड़ा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाती हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व में राजग के सामने विकल्प के तौर पर कोई मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो वह सीमित शक्ति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं खड़ा कर पाती है। इसके बावजूद राष्ट्रीय परिदृश्य में वह खुद को मुख्य विपक्ष मानकर चलती है।

ऐसी स्थिति में फिलहाल कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के तालमेल से अगर कोई मोर्चा बनता भी है तो उसमें यह निश्चित नहीं है कि कौन कितने दिन तक टिका रहेगा। यूं तो तीसरे मोर्चे के लिए अब तक हुई ज्यादातर पहल का हासिल कमोबेश यही रहा है। इस बार भी जैसी कोशिशें दिख रही हैं और उसमें जिन पार्टियों को शामिल माना जा रहा है, उनके सामने विपक्ष के मुख्य ध्रुव को चुनना एक बड़ी समस्या रही है। मसलन, समाजवादी पार्टी अगर तीसरे मोर्चे जैसे किसी गठबंधन में शामिल होने के बारे में सोचती है तो उसके सामने कांग्रेस के साथ सहयोग करने या नहीं करने का ऊहापोह कायम रहेगा।

इसी तरह वामपंथी पार्टियों के सामने भी यह दुविधा बनी रहेगी कि भाजपा के विरोध के मोर्चे में वह कांग्रेस से कितनी दूरी बना सकेगी। पश्चिम बंगाल के हाल के विधानसभा चुनावों में भी वामपंथी पार्टियों का कांग्रेस के साथ तालमेल था। अब ताजा सुगबुगाहट में वामपंथी दलों के कुछ नेताओं के जिस तरह सक्रिय होने की खबरें हैं, उसमें कांग्रेस के साथ सहयोग का स्वरूप क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है।

बिहार में राष्ट्रीय पार्टियों को होना पड़ता है बेबस

बिहार में 1990 के आसपास कांग्रेस के शासन खत्म होने के बाद से यहां की सियासी कुंजी क्षेत्रीय दलों के ही पास रही है। सत्तापक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही जगह यहां के क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो चाहकर भी राष्ट्रीय दल बिहार में अपनी पैठ नहीं बना सकते। उन्हें चुनाव में हर हाल में किसी क्षेत्रीय दल के साथ ही जाना पड़ता है। बिहार में 1990 से पहले लगातार शासन में रहने वाली कांग्रेस पिछले कई सालों से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के सहारे ही बिहार में चुनाव लड़ती आ रही है। वहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी भाजपा भी नीतीश कुमार के सहारे ही बिहार में 15 सालों से सत्ता में साक्षीदार है। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्रीय नेतृत्व में आने के बाद भाजपा ने बिहार में खुद को मजबूत किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा ने बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। 2014 में भाजपा बिहार में 23 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि, तब भी उसे रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे क्षेत्रीय नेताओं की जरूरत पड़ी थी। लेकिन ठीक एक साल बाद ही विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। भाजपा रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तथा जीतनराम मांझी को एकजुट कर नीतीश और लालू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी पर कामयाबी नहीं मिल पाई। खुद भाजपा जदयू और आरजेडी की तुलना में कम सीटें जीत पाई। यही कारण है कि भाजपा को ना चाहकर भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है और चिराग पासवान जैसे क्षेत्रीय दलों के अध्यक्षों के दबाव में आना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अगर बिहार में भाजपा अपने दम पर चुनाव में जाती है तो उसके ऊपर सवर्णों की पार्टी होने का तबका लग जाता है।

यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि स्वच्छता अभियान में अपनी स्वच्छता का डंका बजा रहे मप्र में आज भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वह भी तब जब प्रदेश के सभी जिले 100 फीसदी ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। दरअसल, प्रदेशभर में 7 वर्षों में 96,60,574 शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन लाखों शौचालय ऐसे हैं, जो उपयोग लायक नहीं हैं।

भ्रष्टाचार में बेइज्जत 'इज्जत घर'

मप्र खुले में शौच मुक्त प्रदेश है। यानी 100 फीसदी ओडीएफ। प्रदेश को ओडीएफ बनाने के लिए सरकार ने 97,60,574 घरों में इज्जत घर (शौचालय) बनवाए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये इज्जत घर बेइज्जत होकर रह गए हैं। इस कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में लाखों लोग आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। दरअसल, प्रदेशभर में जो शौचालय बनाए गए हैं या तो वे कागजों पर बने हैं या फिर गुणवत्ताहीन हैं। सरकार ने कई स्तरों पर इसकी जांच-पड़ताल की। लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर बाकी भ्रष्टाचारी इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसके लिए घर-घर शौचालय के जरिए स्वच्छता की योजना परवान चढ़नी थी, मगर भ्रष्टाचार की गंदगी ने इसे भी गंदा कर डाला। भ्रष्टाचारियों ने गांव में इज्जत घर निर्माण की योजना को बेइज्जत कर दिया। इस कारण लोग अब खुले में शौच करने को मजबूर हैं। खुले में शौच मुक्त अभियान (ओडीएफ) की सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। सरपंचों और ग्राम सचिवों ने इज्जत घरों में जमकर खेल किया है।

मप्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 7 वर्षों में 96,60,574 शौचालय बनाए गए हैं। इनमें से स्वच्छाग्रहियों की मदद से 62 लाख 78 हजार 514 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। ये ऐसे घर थे, जिनमें रहने वाले सदस्य शौच के लिए खुले में जाते थे। वजह थी घर में शौचालय का नहीं होना। ऐसे 55 लाख 78 हजार 514 घरों में सरकार की मदद से शौचालय बनाए गए हैं। वहीं 7 लाख घरों में रहने वाले लोगों ने स्वेच्छा से शौचालय बनवाए हैं। लेकिन, हकीकत यह है कि आज लाखों शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। राजधानी भोपाल की झुग्गी-बस्ती क्षेत्रों में आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि प्रदेशभर में लाखों शौचालयों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग खुले में शौच करने को मजबूर हो रहे हैं।

दरअसल, प्रदेशभर में शौचालय निर्माण में जमकर घोटाले हुए हैं। न गड्ढ़ा बनाया, न ही सीट लगाई, केवल दीवार खड़ी कर राशि आहरित कर ली गई है। राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन, सतना, सीधी, बैतूल, सिंगरौली, खंडवा, बुरहानपुर सहित डेढ़ दर्जन जिलों की स्थिति का आंकलन करने के बाद यह पाया गया कि शौचालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में शौचालयों का निर्माण ही नहीं हुआ, जहां कहीं इसकी शुरूआत भी हुई तो महज कागजी खानापूरी तक ही सीमित रहा। लेकिन योजना मद की पूरी धनराशि जरूर निकाल ली गई। बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों में घर-घर शौचालय निर्माण का अभियान शुरू किया गया। खूब प्रचार-प्रसार हुआ। कहा गया कि अब कोई खुले में शौच करने नहीं जाएगा। बैनर-पोस्टर लगाए गए। वॉल राइटिंग हुई। कईयों पर जुर्माना भी लगा। लेकिन हकीकत में कहीं कागजों पर तो कहीं आधा-अधूरा शौचालय बनाकर राशि निकाल ली गई।

कोरोना संक्रमणकाल में जब लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लगा था, उस दौरान भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर थे। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने खुले में थूकने के लिए प्रतिबंध लगाया है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की खुले में शौंच के लिए जाना मजबूरी बनी हुई है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खुले में शौच के लिए जाते समय कई बार पुलिस द्वारा गश्त के दौरान डंडे भी बरसाए गए। लेकिन हमारे शौंचालय उपयोग लायक ही नहीं बनाए गए हैं, जिससे खुले में शौच के लिए जाना हमारी मजबूरी है।

● **कुमार विनोद**

कागज पर बने 4.5 लाख शौचालय

बैतूल में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। तस्वीरों और पेपर पर तो 4.5 लाख शौचालय दिख रहे हैं। लेकिन स्पॉट पर जाने पर एक भी नहीं दिखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वह वहां से पलायन कर गए या फिर कोई बड़ा घोटाला हुआ है। इसे बनाने में 540 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन सभी के जीपीएस टैग फोटो भी थे, मगर मौके पर कहीं दिखा नहीं। जांच में यह बात सामने आई है कि जिन जगहों पर टॉयलेट निर्माण की बात कहीं जा रही है, वहां एक भी टॉयलेट नहीं मिले हैं। हालांकि प्रशासन के पास सभी टॉयलेट्स की जीपीएस-टैग की गई तस्वीरें हैं। पूरे खुलासे के बाद सरकार उन पर खर्च किए गए पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है। दरअसल, यह घोटाला 2017 गुना में हुए शौचालय के दरवाजे के घोटाले की याद दिला रहा है। जहां 42,000 शौचालयों में दस किलो से भी कम वजन का दरवाजा लगवाया गया था। जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ था। प्रदेश के कई जिलों में बने शौचालयों की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है।

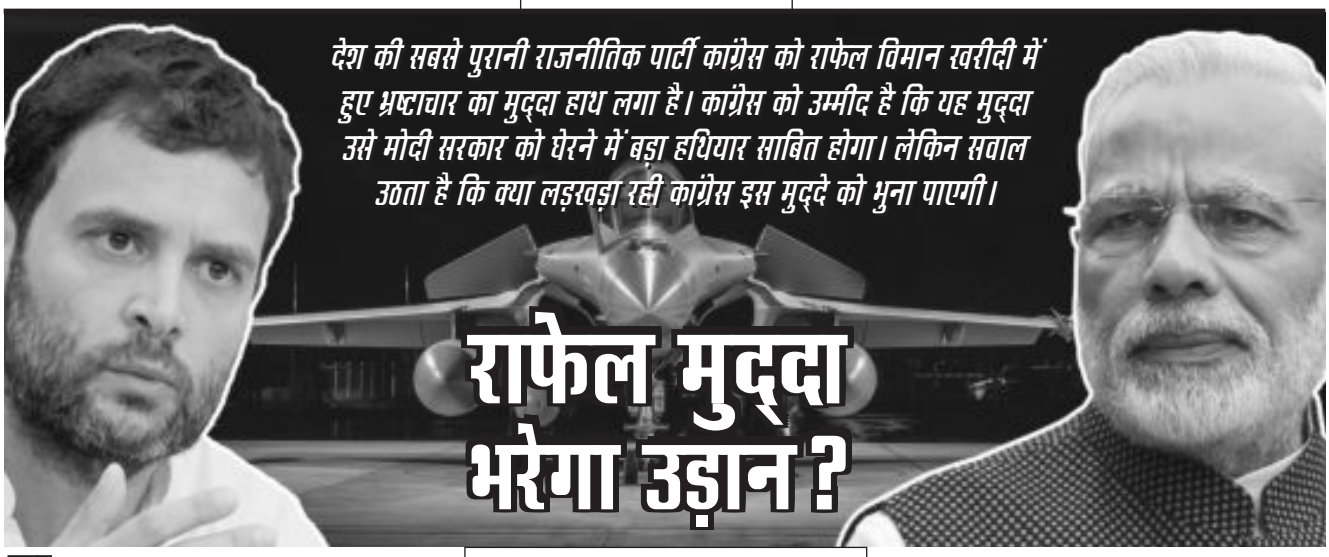

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को राफेल विमान खरीदी में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा हाथ लगा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यह मुद्दा उसे मोदी सरकार को घेरने में बड़ा हथियार साबित होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या लड़खड़ा रही कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी।

राफेल मुद्दा भरेगा उड़ान?

राफेल डील की आग बुझी तो नहीं थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी के मुद्दा बनाने के बावजूद कांग्रेस की हार के साथ ही उसकी लपटें धीमी जरूर पड़ गई थीं। अब एक बार फिर धुआं उठने जरूर लगा है और ये फ्रांस में दिखाई पड़ा है, लेकिन देश की राजनीति में भी कोई असर पड़ेगा क्या? धुआं कहीं भी दिखे, जिसके मतलब का होता है वो आग के लेवल के चक्कर में नहीं पड़ता, मौका मिलते ही अपने विरोधी पर धावा बोल ही देता है और राहुल गांधी बिलकुल ऐसा ही फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू कर चुके हैं।

राफेल डील की जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। राफेल डील की जांच के लिए फ्रांस के ही एक एनजीओ ने 2018 में ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब वहां की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने जांच की डिमांड खारिज कर दी थी, लेकिन अब वो भारत के साथ हुई इस डील में भ्रष्टाचार के साथ-साथ इस बात की जांच के लिए भी तैयार हो गई है कि कहीं कोई पक्षपात भी हुआ है क्या? मतलब, किसी का फेवर लिया गया है क्या?

फ्रांस और भारत के बीच जब ये डील हुई थी तो मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रोन तब की फ्रांस्वा ओलांद सरकार में वित्त मंत्री रहे। खबर है कि इमैनुएल माक्रोन और फ्रांस्वा ओलांद के साथ साथ फ्रांस के मौजूदा विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियान से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सौदा पक्का होते वक्त वो फ्रांस सरकार में रक्षा मंत्री हुआ करते थे। राफेल डील की जांच की खबर ऐसे वक्त आई है जब कुछ ही महीनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी महीने संसद का मानसून सत्र बुलाया जाना है। संसद में विपक्ष का हंगामा तो तय है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों पर भी राफेल डील जांच का कोई असर हो सकता है क्या?

2022 के विधानसभा चुनावों पर असर

आम चुनाव में तो राहुल गांधी का 'चौकीदार...' स्लोगन सुपर फ्लॉप रहा। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं हारे होते तो भी लगता कि चलो ज्यादा न सही कुछ तो असर हुआ है, लेकिन पूरी कांग्रेस भी 52 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। दो सीटें तो रायबरेली से सोनिया गांधी और केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने ही जीती थी। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की हार से मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हौसला बढ़ा है और कांग्रेस को अलग रखते हुए ज्यादातर विपक्षी नेता एक्टिव भी हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों पर राफेल डील का मुद्दा उछालने से कोई फर्क पड़ेगा भी, ऐसे कम ही चांस हैं। राफेल डील का मामला केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार से जुड़ा है, ऐसे में विधानसभा चुनावों में कोई मतलब नहीं रह जाता और वो भी तब जब राफेल डील के आरोपों को काउंटर क्या न्यूट्रलाइज करते हुए भाजपा सत्ता में पहले से ज्यादा सीटों के साथ वापसी कर चुकी हो। रही बात उप्र की तो भला राफेल डील का योगी आदित्यनाथ की सरकार से क्या लेना देना?

2019 के आम चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी जगह-जगह लोगों से 'चौकीदार चोर है' के नारे भी लगवाते रहे। राहुल गांधी ने इस नारे की शुरुआत तो 2018 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों में ही कर दी थी। जब तीन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली तो उत्साह बढ़ा और फिर आम चुनाव के लिए ये स्लोगन पक्का कर लिया गया।

राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा को भारी पड़ने लगे थे। फिर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट चली गईं और राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की। आम चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी को राफेल डील पर बयानबाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी तक मांगनी पड़ी थी, लेकिन चुनावी हार के बाद जब राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर सार्वजनिक किया तब भी यही दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपने आरोप से वो पीछे नहीं हटे हैं, 'चौकीदार चोर है।' प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी के अटैक को काउंटर करने के लिए खुद मोर्चा संभालना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बदला और नाम के पहले 'चौकीदार' शब्द जोड़ दिया। प्रधानमंत्री को फॉलो करते हुए भाजपा नेताओं और समर्थकों ने भी नाम के पहले चौकीदार जोड़ लिया, तब जाकर हमले की धार कम की जा सकी। 2017 में गुजरात में कांग्रेस के कैंपेन 'विकास पागल हो गया है' के बाद ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री ने अपनी लोकप्रियता के बूते कांग्रेस के किसी मुहिम की धार कमजोर किए थे।

राहुल गांधी तब से लेकर अब तक कांग्रेस की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। इसके लिए कई बार पार्टी की तरफ से तारीखें भी बताई गईं, लेकिन मामला टलता रहा है। यहां तक कि कांग्रेस में एक स्थायी अध्यक्ष की मांग को लेकर जी-23 ग्रुप भी एक्टिव हो गया है, जिसे कांग्रेस में बागियों के तौर पर देखा जाता है और उसी ग्रुप के एक सदस्य जितिन प्रसाद अब कांग्रेस छोड़ कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं।

अब जबकि फ्रांस में राफेल डील की जांच कराने की खबर आई है, राहुल गांधी नए सिरे से एक्टिव नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर नई टिप्पणी पेश की है, लेकिन मुहावरे को अधूरा रखा है, और लॉकडाउन के बाद बढ़ी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी चर्चित रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से भी जोड़ने की

कोशिश की है।

सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट की है, एक इलस्ट्रेशन तैयार किया गया है जिसमें आधा चेहरा नजर आता है और लंबी दाढ़ी में नीचे राफेल विमान की तस्वीर जोड़ दी गई है। ट्विटर की ही तरह राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर भी वही जुमला लिखा है चोर की दाढ़ी... और हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या अगले साल 2022 में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस राफेल डील को नए सिरे से मुद्दा बना पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो क्या असर भी होगा, खासकर उप्र में?

कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। कम से कम चार प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा ही हो रहा है। जैसे नाव में छेद होने पर एक जगह से पानी रोको तो दूसरी जगह से आने लगता है, वैसा ही हाल कांग्रेस का हो रहा है। अचानक जैसे सब क्षत्रपों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। सबको पता चल गया है कि कांग्रेस हाईकमान में अब न तो कुछ हाई रहा है और न ही कमान। तीन लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी चलाने का उपक्रम कर रहे हैं, पर पार्टी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है। वैसे कांग्रेस की यह हालत कोई अचानक नहीं हुई है। चुनाव दर चुनाव हार से पार्टी अशक्त हो गई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उम्मीद नहीं रह गई है और सबसे बुरा होता है उम्मीद का मर जाना। जो और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं, वे एक-एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जो रुके हुए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्यों रुके हुए हैं? यदि भाजपा बंगाल जीत जाती तो अब तक कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मच गई होती, पर अब भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।

लंबे इंतजार के बाद गत दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई। इससे पहले सिद्धू की राहुल गांधी और प्रियंका से लंबी बातचीत हो चुकी थी। कांग्रेस में चल क्या रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद कैप्टन पर सिद्धू के हमले रुकने के बजाय और बढ़ गए। सारा देश जानता है कि पंजाब में समस्या सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई है, पर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन बाहर आए तो सिद्धू के बारे में पूछने पर कहा कि उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वह तो कांग्रेस अध्यक्ष से सरकार और राजनीतिक स्थिति पर बात करने आए थे। वह जो तय करेंगी, मानेंगे। मतलब यह कि गेंद अब सोनिया गांधी के पाले में है। समस्या यही है कि पूरा गांधी परिवार मिलकर कुछ तय नहीं कर पा रहा है। पिछले दो महीने में कांग्रेस के नेताओं ने

सबसे पुरानी पार्टी की दुर्दशा

देश की सबसे पुरानी पार्टी की दुर्दशा का वर्णन करना कठिन है। अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जो रिटायरमेंट से लौटकर आने को मजबूर हुईं। सिर्फ इसलिए कि बेटे के लिए पद को बचाए रख सकें। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जिनकी राजनीतिक उपलब्धि यह है कि महामंत्री के नाते उप्र का प्रभार मिला तो पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी परिवार का कोई सदस्य (राहुल गांधी) अमेठी से चुनाव हार गया। उनकी रहनुमाई में उप्र में कांग्रेस को 80 में से 1 सीट मिली। इसके पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत बचाना मुश्किल हो गया। पंचायत चुनाव में पार्टी का हाल खोजते रह जाओगे वाला है, पर वे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का भविष्य तय करती हैं। फिल्म 'अमर प्रेम' में आनंद बख्शी का लिखा गीत है- चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए। तो कांग्रेस में सावन ही आग लगा रहा है।

कैप्टन सरकार की जितनी कमियां गिनाई हैं, उतनी तो समूचा विपक्ष भी नहीं गिना पाया। चार साल बाद पार्टी हाईकमान की नींद खुली और कैप्टन को कुछ दिन पहले तीन सदस्यीय कमेटी के मार्फत आदेश दिया गया कि चुनाव घोषणा पत्र के 18 मुद्दों पर सरकार काम करके बताए। अब जो काम सवा चार साल में नहीं हुआ, वह कुछ दिनों में हो जाएगा, ऐसे चमत्कार की उम्मीद कांग्रेसी ही कर सकते हैं। जबसे मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनी है, ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सरकार नहीं चला रहे, बल्कि कोई मुकदमा लड़ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार में बदलने पर आमादा है।

पंजाब की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा खोल दिया। यहां सरकार नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष ही सही। प्रदेश अध्यक्ष सैलजा को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। वह गांधी परिवार की पसंद हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर पार्टी हाईकमान का नहीं हुड्डा का हुकुम चलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव जिताकर वही लाए थे और वही फिर जिताने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए विधायक कह रहे हैं कि चुनाव जीतना है तो पार्टी की कमान हुड्डा को देनी पड़ेगी। हाईकमान की क्षमता नहीं है कि वह हुड्डा को रोक सके। रोकना चाहे भी तो हुड्डा रुकने वाले नहीं हैं।

राजस्थान में तो अशोक गहलोत का जादू का खेल चल रहा है। हाईकमान से मिलने की बात हो, उनके हरकारों से या असंतुष्टों से, मुख्यमंत्री को डॉक्टर घर में रहकर आराम करने की सलाह दे देते हैं, पर राज्यपाल के पुस्तक विमोचन समारोह में जाने के लिए वह बिल्कुल चंगे हैं। सचिन पायलट को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह किसके पास जाएं? वैसे टेलीफोन टैपिंग की तलवार गहलोत के सिर पर अभी तक लटकी ही हुई है। साथ में बहुजन समाज पार्टी के जिन छह विधायकों का कांग्रेस में विलय कराया था, उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना है। वहां से झटका लगा तो जादूगर का जादू भी काम नहीं आएगा, पर एक बात तो है कि अशोक गहलोत को कैप्टन की तरह हाईकमान की कोई चिंता नहीं है।

● इन्द्र कुमार

मोदी का मेगा मैनेजमेंट

अगले साल फरवरी-मार्च में 5 राज्यों उप्र, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। कैबिनेट विस्तार में इनमें से उप्र पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। विस्तार में शामिल 36 नए चेहरों में से 7 अकेले उप्र से हैं। इसके साथ ही यहां से आने वाले कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मोदी कैबिनेट में उप्र के मंत्रियों की ये सबसे बड़ी संख्या है।

प्रधानमंत्री मोदी का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार जिस आलोचना का सबब बना है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। सिर्फ और सिर्फ आगामी उप्र चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट का विस्तार यह बता गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सत्ता के लिए कितनी बड़ी सत्ता पिपासु है। सिर्फ अपनी छवि और कुर्सी के बचाव के कारण कैबिनेट का कुछ इस तरह विस्तार किया गया कि आने वाले समय में उप्र और गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी पुनः सत्तासीन हो सके।

नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में हुई फेरबदल के बारे में सबसे बेहतरीन कटूक्ति गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने की। उन्होंने ट्वीट किया- 'खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं।' बात तो सचमुच बड़े मार्के की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल हो तो खबर बननी ही है। फेरबदल अगर बड़े विस्तार से किया गया हो तो समाचारों में उसकी सुर्खियां प्रमुखता से लगेंगी। ऐसे फेरबदल की व्याख्याएं होंगी, आलोचना होगी और हां, उम्मीद भी बांधी जाएगी। लेकिन ये सारा कुछ इस **यकीन के तले होगा** कि मंत्रिमंडल में कुछ को बुलाया और कुछ को हटाया गया है तो फिर इस नई बुनावट से कुछ बेहतर सधेगा, प्रशासन बेहतर होगा और मंत्री सचमुच ही अपने महकमे के काम को मति-गति देंगे, उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में ऐसा यकीन पाल कर चलने की कोई वजह नहीं।

मोदी सरकार का मंत्रिमंडल पीएमओ की हांक से चलने वाला मंत्रिमंडल है। कह लें कि आजाद भारत में पीएमओ की हांक पर चलने वाला जैसा मंत्रिमंडल मोदी सरकार ने बनाया है वैसा अब से पहले कभी नहीं बना, उस वक्त भी नहीं जब देश में इमरजेंसी लगी थी और मंत्रिमंडल में पत्ते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे से हिला करते थे। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में चीजें कुछ यूं होती हैं कि प्रधानमंत्री चीजों की एक दिशा तय कर देते हैं, उस दिशा की लकीर पर प्रधानमंत्री का कार्यालय अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नीतियां बना लेता है। इस काम में कोई बड़ा फैसला करना हो तो वह प्रधानमंत्री खुद करेंगे या फिर ऐसे फैसले का ऊंच-नीच और झोल तौलना हो तो ये काम भी खुद प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रियों को बस हुक्म बजाना होता है और वह भी एकदम समय की पाबंदी के साथ।

सच कहें तो, मंत्री नहीं बल्कि मंत्रालय के सचिव के रूप में काम कर रहा कोई आईएएस इस काम के लिए काफी है। इस मंत्रिमंडल में मंत्रियों का काम तो बस इतना भर रह जाता है कि वे हुक्म बजाते रहें, नजर रखें ताकि लोगों में ये धारणा जमी रहे कि मंत्रालय अपने काम पर मुस्तैद है, कि मंत्रीजी काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, कि वे ठीक समय से चीजों को होता हुआ दिखा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और धुआंधार प्रचारबाजी के काम पर डटे हुए हैं।

दरअसल, विकास की जो बातें देशवासियों को आए दिन लोगों को लुभावने लच्छेदार भाषणों मीठी चुपड़ी बातों का सच अब सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी की एक धरोहर थी आप याद करिए- 'गुजरात मॉडल' का एक भ्रम जाल फैला करके 2014 के चुनाव में भाजपा ने मोदी को आगे रख करके अपनी चुनावी नैया पार लगाई थी और जैसे-जैसे समय बीतता चला गया अब गुजरात मॉडल पीछे रह गया है। वह सारी बातें अब कोई नहीं करता जिनके आधार पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना था। अब जब लगभग 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और मोदी ने बहुप्रतिक्षित कैबिनेट विस्तार किया तो एक बार पुनः यह सच सामने आ गया कि किस तरह 56 इंच के सीने का दावा करने वाला प्रधानमंत्री ताश के पत्तों की तरह मंत्रियों को फेंट देता है। अपने पुराने दिन के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनाकाल के समय में हुई अपनी

मंत्रियों को हटाए जाने के मायने

नजर इस बात पर दौड़ाने की जरूरत है कि मंत्रिमंडल में कौन-कौन से नए चेहरे बुलाए गए, निगाह इस बात पर टिकायी जाए कि मंत्रिमंडल से किन चेहरों को हटाया गया। वजह ये कि जिन्हें बुलाया गया है उनमें से बहुतों के बारे में हमें नहीं पता कि मंत्री के रूप में उनका ट्रैक रिकार्ड क्या रहा है। सो, बेहतर यही है कि हम मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के मायने तलाशने के लिए इस बात पर सोचें कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और ऐसे कौन-कौन हैं जो यूं तो आ सकते थे फिर भी फेरबदल के खेल में मंत्रिमंडल में आने से रह गए। मंत्रिमंडल में रखने और हटाने का फैसला बड़ा अहम होता है और उससे पता चलेगा कि हालिया फेरबदल से प्रधानमंत्री के मन में क्या मकसद साधने की बात रही होगी। मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में गवर्नेंस के मोर्चे पर जहां-जहां बुरी तरह नाकाम हुई है उसकी बिना किसी राग-विराग के एक सूची बनाएं तो वो यूं होगी। कोरोनाकाल के लॉकडाउन के ऐन पहले, बाद में और लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन, लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़, कश्मीर-घाटी से बात-विचार करने के जो भी संवाद-सूत्र बचे रह गए थे उनको तिलांजलि, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के मसले पर अल्पसंख्यकों में भारी घबराहट पैदा करना, तीन कृषि कानूनों को हड़बोंग मचाने की शैली में सामने लाना और नतीजों में किसानों का जो प्रतिरोध उभरा उसके मसले ना सुलझाना और हां, इसी सूची में ये भी दर्ज होगा कि महामारी की दूसरी लहर ने जब जोर मारा तो बड़े हैरतंगेज ढंग से अपनी सारी जिम्मेवारियों से कन्नी काट ली गई।

गलतियों को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर थोप दिया है।

ऐसा प्रतीत होता है मानो नरेंद्र मोदी पद किसी अज्ञात भय का साया है और यह भय उनके लंबे-चौड़े कैबिनेट निर्माण में बारंबार झलक रहा है। चाहे उप्र की बात हो या फिर बिहार की, गुजरात की हो या फिर पश्चिम बंगाल की हर कहीं अपनी खामियों को छुपाने-ढंकने के लिए मोहरों को शपथ दिलाई गई है और अपेक्षा की जा रही है कि अब वह कुछ ऐसा करें कि मोदी सरकार की लाज बच सके। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना के समय सरकार की जो किरकिरी हुई है उसे इस नवीन मंत्रिमंडल की आभा मंडल के द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया है।

यह सारा देश जानता है कि जिस तरह 2020 के मार्च महीने में लॉकडाउन लगाने के पश्चात मोदी सक्रिय थे वैसा 2021 में दूसरी लहर के समय में नहीं थे। दूसरी लहर की मारक क्षमता के सामने मोदी सरकार विवश दिखाई दे रही थी। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ तथा श्मशान घाट में लोगों की लाशें और केंद्र सरकार का मौन!

ऐसे समय में देश की उच्चतम न्यायालय ने मानो बागडोर संभाल ली और अभी भी हाल ही में देश की उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना से मृत लोगों को मुआवजा देना होगा यह आदेश, यह जता रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह कमजोर हुई है। और इन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कैबिनेट को उलटफेर करके पुराने दिग्गजों को सेट करके और नए लोगों को जोड़कर यह दिखाने का प्रयास किया है कि वे एक सक्षम और कुशल नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री हैं।

लाख टके का सवाल यही है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश क्या है। नवीनतम वृहदकायय मंत्रिमंडल निर्माण के पीछे उनकी मंशा क्या है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि देश किस दिशा में जा रहा है, यह इस कदम से समझ में आ सकता है। भाजपा जिस तरीके से हिंदुत्व का राग अलापती है और सत्ता के अपने चरम समय में आज आदिवासी, हरिजन और ओबीसी कार्ड खेल रही है तो यह सच्चाई सामने आ जाती है कि मोदी अब वैसे सक्षम नहीं रहे जैसे कि 2014 में थे।

मोदी को आज के समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे कांग्रेसियों और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जैसों की आवश्यकता है जो उन्हें या तो आगामी चुनाव में उबारकर ले जाएंगे या फिर डुबा भी सकते हैं। कैबिनेट का यह विस्तार एक तरह से संघ परिवार भाजपा और नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है।

नई कैबिनेट की औसत उम्र 58.2 साल है। ये मोदी सरकार की अब तक की सबसे युवा कैबिनेट है। कैबिनेट में शामिल 12 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है। 2019 में कैबिनेट में शामिल 11 मंत्री ऐसे थे जिनकी उम्र 50 साल से कम थी। वहीं, 2014 में शपथ लेने वाली कैबिनेट में 33 यानी करीब 72 प्रतिशत मंत्री 50 साल या उससे कम उम्र के थे। हालांकि, 2014 की मोदी कैबिनेट की औसत उम्र 59.6 साल थी।

40 साल से कम उम्र के मंत्रियों की बात करें तो 2014 में स्मृति ईरानी इकलौती मंत्री थीं। 2019 की कैबिनेट में एक भी मंत्री 40 से कम उम्र का नहीं था। नई कैबिनेट में निशीथ प्रमाणिक (35 साल), शांतनु ठाकुर (38 साल) और अनुप्रिया पटेल (40 साल) ऐसे हैं जो 40 या उससे कम उम्र के हैं। 72 साल के सोम प्रकाश सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। उनके अलावा 70 पार मंत्रियों में 71 साल के राव इंद्रजीत और 70 साल के नरेंद्र मोदी शामिल हैं।

संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा मंत्री उप्र से बनाए गए हैं, लेकिन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से गुजरात की भागीदारी सबसे ज्यादा है। राज्य में 26 लोकसभा सीटें हैं। यहां से 6 मंत्री बनाए गए हैं। यानी, लोकसभा सीटों के करीब 23 प्रतिशत मंत्री। इस लिहाज से 80 लोकसभा सीटों वाला उप्र 20 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र 19 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर है।

78 में 6 मंत्री ऐसे हैं जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं। इनमें एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, सोम प्रकाश, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव और आरसीपी सिंह शामिल हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में दो ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजीव चंद्रशेखर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो मोदी कैबिनेट में इस बार सबसे कम करोड़पति हैं। मौजूदा कैबिनेट में 89.5 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं। 2019 में 91 प्रतिशत मंत्री करोड़पति थे। वहीं, 2014 में 91.3 प्रतिशत करोड़पति मंत्री थे। जो बाद में बढ़कर 92 प्रतिशत हो गए थे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया नई कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। उनके पास 379 करोड़ की संपत्ति है। सिंधिया के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति पीयूष गोयल के पास है। गोयल 95 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। गोयल की तरह ही महाराष्ट्र से आने वाले नारायण राणे तीसरे नंबर पर हैं उनके पास 87.77 करोड़ की संपत्ति है।

● **रजनीकांत पारे**

योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता

कैबिनेट के विस्तार में कुछ पुराने मंत्रियों की पदोन्नति यह बताती है कि उन्हें उनके बेहतर काम का पुरस्कार मिला। यह मिलना भी चाहिए था क्योंकि इससे सभी को यह संदेश जाता है कि बेहतर प्रदर्शन मायने रखता है न कि मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर मौजूदगी। आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की प्रतीक्षा पूरी हुई। इस पहले बड़े विस्तार और साथ ही फेरबदल से यही स्पष्ट हुआ कि नए मंत्रियों के चयन में योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता देने के साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा गया। लोकतंत्र में ऐसा करना आवश्यक होता है। कैबिनेट विस्तार के साथ प्रधानमंत्री की टीम कहीं ज्यादा व्यापक आधार वाली और पहले से अधिक सक्षम दिखने लगी है। चूंकि कैबिनेट में सहयोगी दलों की भागीदारी के साथ ही युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है इसलिए उसकी औसत आयु पहले से कम दिखने लगी है। खास बात यह भी है कि कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके साथ ही वंचित एवं पिछड़े तबकों की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री सोशल इंजीनियरिंग पर न केवल काम कर रहे हैं, बल्कि उसे बल भी प्रदान कर रहे हैं।

राजद्रोही आईपीएस!

अवार्ड के लिए ग्रामीणों को बना दिया था नक्सली

जीपी सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। विवाद उनके एसपी बनने के साथ ही जुड़ना शुरू हो गए थे। बस्तर एसपी रहते गैलेंट्री अवार्ड के लालच में आदिवासी ग्रामीणों को नक्सली बनाना हो या फिर आईजी बनने के बाद बिलासपुर के एसपी रहे 37 साल के एसपी राहुल शर्मा की खुदकुशी का। राहुल शर्मा ने खुद को गोली मार ली थी। उसमें भी जीपी सिंह का नाम सामने आया था। बस्तर एसपी रहने के दौरान जीपी सिंह करीब 100 ग्रामीणों को रायपुर लेकर आए थे। बताया जाता है कि गैलेंट्री अवार्ड पाने के लालच में यह सब किया गया। जब उन्हें रायपुर लेकर पहुंचे तो पता चला कि नक्सली नहीं बल्कि वह सामान्य आदिवासी हैं। इसकी बाद काफी फजीहत भी हुई थी। वहीं अपने ही वरिष्ठ और मातहत अधिकारियों के साथ उनके झगड़े भी चर्चा में हमेशा रहे। एक आईजी के घर से लूट की रकम बरामद करने की साजिश में भी इनका नाम आया था।

एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंसे छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह पर राजद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उनके सरकारी बंगले से कुछ चिट्ठियां, फटे हुए पन्ने और पेन ड्राइव मिली थीं, जिसकी जांच में सरकार विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई थी। इसके बाद सिटी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। वहीं, जीपी सिंह आखिरी बार बिलासपुर में देखे गए थे। वे वहां से पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। हालांकि, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। गौरतलब है कि एसीबी के पूर्व चीफ जीपी सिंह के सरकारी बंगले समेत 15 ठिकानों पर 1 जुलाई को छापे में बेहिसाब अवैध संपत्ति, बड़े लेन-देन और शेल कंपनियों में निवेश के सबूत मिले हैं। जांच अफसरों ने बताया कि सिंह की करोड़ों की प्रॉपर्टी की पुष्टि हुई है।

जांच टीम के अफसरों को कुछ डायरियां और डायरियों के फटे पन्ने मिले हैं। इस डायरी में जादू-टोने से जुड़ी बातें लिखी हुई हैं। कुछ ऐसा अजीबो-गरीब सामान भी सिंह के यहां से मिला है जो अमूमन तंत्र-मंत्र के काम आता है। एक डायरी में कोड वर्ड में कुछ अफसरों के बारे में अजीब बातें लिखी हैं। जादू-टोने की बातें ये पुलिस महकमे के ही बड़े अधिकारियों के बारे में हैं। डायरी में लिखा है- वह थाईलैंड से 20 पैर वाला कछुआ मंगवा चुका है। उसकी बलि देने के बाद कुछ भी कर सकेगा। इनमें से एक अफसर का नाम **छोटा टकला** लिखा गया है। लिखा है कि छोटा टकला ने एक अफसर का बाल काट लिया है, इसलिए सब कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि छोटा टकला प्रदेश के ही एक सीनियर अफसर का कोड वर्ड है। ये फिलहाल कई मामलों में फंसे हुए हैं और इनके खिलाफ जांच जारी है। दो और अफसरों के लिए अनोपचंद-तिलोकचंद लिखा हुआ है। कुछ आईएएस अधिकारियों, सचिव स्तर के अफसरों, कांग्रेस-भाजपा के नेताओं का नाम भी कोड वर्ड में लिखा है। इन सभी दस्तावेज को बारीकी से देखा जा रहा है। जांच टीम को जीपी सिंह के विदेशी बैंकों में कई खातों की जानकारी मिली है। उन खातों की लिस्टिंग, पैसा कहां से आया किसने दिया, इन पहलुओं की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही है। कनाडा, ब्रिटेन और कुछ देशों में बसे रिश्तेदारों के जरिए निवेश की जानकारी की भी जांच हो रही है। गत दिनों ओडिशा में संपत्ति, कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले आधा दर्जन वाहन, कई बैंक अकाउंट्स, 75 से अधिक बीमा पॉलिसी के सबूत मिले थे। ये सब जीपी सिंह, उनकी धर्म पत्नी और उनके पुत्र के नाम पर हैं।

उधर आय से अधिक संपत्ति मामले और राजद्रोह के आरोपों से घिरे सीनियर आईपीएस जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस रिट पिटिशन में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सिंह ने कहा कि उन्हें सरकार के कुछ अधिकारियों ने फंसाया है। इसके अलावा सिंह ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है। उधर सिंह की इस याचिका के बाद शाम को राज्य शासन ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोई भी फैसला, संरक्षण देने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। दरअसल, एसीबी के पूर्व चीफ जीपी सिंह के सरकारी बंगले समेत 15 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी में बेहिसाब आय से अधिक संपत्ति और कुछ दस्तावेज मिले थे जिसमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी गई थीं। याचिका में प्रमुखता से जो बात रखी गई उसमें कहा गया कि सरकार में दखल रखने वाले कुछ नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर जीपी सिंह को इस पूरे ट्रैप में फंसाया। याचिका में हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग करते हुए सिंह ने कहा है कि यह पूरी कार्रवाई इसलिए हुई है कि उन्होंने कुछ अवैध कामों को करने से मना किया। उनके असहयोग करने के कारण कुछ अधिकारियों ने पहले उन्हें धमकी दी और बाद में आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए एसीबी, ईओडब्ल्यू का छापा पड़वाया। इसमें भी बात नहीं बनी तो उनके खिलाफ राजद्रोह का अपराध गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया। उन्हें पूरा यकीन है कि यदि उनकी जांच राज्य शासन की पुलिस या कोई एजेंसी करती है तो उनके साथ न्याय नहीं होगा इसलिए सभी मामलों की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए जो राज्य शासन के अधीन ना हो।

इस याचिका में जीपी सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज मामले रद्द करने और एफआईआर रद्द करने जैसी कोई मांग नहीं की है। अमूमन ऐसी याचिकाओं का मुख्य बिंदु यही होता है कि एफआईआर गलत है या मामला झूठा है। जीपी सिंह इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं, जिससे सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने याचिका के माध्यम से एफआईआर का आधार, सबूत किसी दूसरी जांच एजेंसी को दिखाने की भी बात कही है। एक ओर जीपी सिंह हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे रायपुर की अदालत में अपनी अग्रिम याचिका की अर्जी भी लगा रहे हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जो धाराएं लगी हैं उनमें तो गिरफ्तारी का खतरा कम है, लेकिन राजद्रोह की धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि जो धाराएं अभी तक लगाई गई हैं, उसमें एक भी धारा ऐसी नहीं है जिसकी सजा 7 साल से ऊपर की हो। अमूमन ऐसे मामलों में पुलिस गिरफ्तारी की हड़बड़ी नहीं दिखाती, लेकिन जीपी सिंह का मामला अलग है। सिंह को गिरफ्तारी का डर है, लिहाजा वे पहले ही अदालत पहुंच गए हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

गठबंधन में कांग्रेस का पेंच

शरद पवार विपक्षी खेमे में मोदी सरकार के खिलाफ चल रही मोर्चेबंदी की धुरी बने हुए हैं। शरद पवार या प्रशांत किशोर के विपक्षी एकजुटता की कवायद से कांग्रेस को अलग रखने की वजह सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं लगते। महाराष्ट्र में उनके करीबी, भरोसेमंद और उनकी नजर में सबसे काबिल नेता नाना पटोले भी हो सकते हैं। नाना पटोले को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। भाजपा में रहते हुए नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देकर बगावत की थी और राहुल गांधी को इसीलिए नाना पटोले सबसे ज्यादा पसंद हैं।

नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले विधानसभा में स्पीकर थे। अब जिस तरह के हाव-भाव नजर आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाने का इंतजार किए बगैर ही, पहले खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं। हाल ही में नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस गठबंधन में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि भाजपा को सरकार बनाने से रोकना था। नाना पटोले ने ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस गठबंधन में हमेशा के लिए शामिल नहीं हुई है। नाना पटोले के बयान को कांग्रेस के अपने दम पर सरकार बनाने की मंशा के तौर पर देखा गया और एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुस्से में बहुत बुरी तरह रिएक्ट भी किया था।

कांग्रेस के अपने बूते महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा था- 'कुछ लोग अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कोरोनाकाल में हृदयविदारक हाल हो रखा है... लोगों का रोजगार गया, रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है... ऐसे में अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा, तो लोग चप्पल से मारेंगे। हम सबको।' उद्धव ठाकरे के बयान पर नाना पटोले कहते हैं- 'ये तो जनता तय करेगी कि चप्पल की मार किसे पड़ेगी।' नाना पटोले के बयान को लेकर उठे सवाल पर एनसीपी नेता शरद पवार ने पहले तो साफ साफ बोल दिया- 'कांग्रेस अगर चाहे तो अकेले चुनाव लड़ सकती है' लेकिन फिर नाना पटोले के बयान को कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने वाला बताया, कहा- 'हर राजनीतिक दल को अपना विस्तार करने का अधिकार है... हम भी अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं।'

देखा जाए तो कांग्रेस के महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की अहमियत पर शरद पवार ने करीब-करीब एक ही तरीके से रिएक्ट किया है। बिलकुल वैसा ही बयान दिया है, जिसे मौजूदा समीकरणों में भी पॉलिटिकली करेक्ट कहा जाएगा, लेकिन क्या हकीकत भी वही हो सकती है जो शरद पवार बोल रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल यही है। कांग्रेस की जो अहमियत महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाते वक्त रही, केंद्र में विपक्षी गठबंधन की मजबूती में भी उतनी ही महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। शरद पवार की मुश्किल ये है कि महाराष्ट्र में तो जैसे-तैसे स्थिति संभाल भी ले रहे हैं क्योंकि नाना पटोले गांधी परिवार के करीबी तो हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह गांधी परिवार से तो नहीं आते।

विपक्ष की मोर्चेबंदी फिर से फेल हो जाएगी, ऐसा समझना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक आशंका तो सबके मन में बनी हुई होगी ही। शरद पवार के मन में भी और प्रशांत किशोर के भी। मुलाकातों और दिल्ली में विपक्षी नेताओं की मीटिंग के बीच कमलनाथ का जाकर शरद पवार से मिलना भी तो यही संकेत दे रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व को भी ये नहीं सुहा रहा है। राहुल गांधी को भले ही बहुत फर्क न पड़ता हो, लेकिन सोनिया गांधी तो परेशान होंगी ही कि भला कैसे विपक्ष के ये सारे नेता आपस में मिल रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व को बुलाने की जगह बता रहे हैं कि उन नेताओं को बुलाया गया था जो सही तरीके से पार्टी को रिप्रजेंट भी नहीं करते। कहने का मतलब कि अगर कहीं भेजना हो तो कांग्रेस नेतृत्व उन नेताओं को प्रतिनिधि बनाकर भेजता है जिन पर भरोसा होता है, जैसे पी चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कमलनाथ। कमलनाथ का शरद पवार से मिलना कांग्रेस नेतृत्व की चिंता की तरफ इशारा करता है। हालांकि, कमलनाथ की मुलाकात को लेकर सफाई दी गई थी कि वो एनसीपी नेता का हालचाल पूछने गए थे। कुछ दिन पहले शरद पवार की एक सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से काफी दिनों तक वो राजनीतिक तौर पर खामोश भी देखे गए। अब तक तो यही समझाइश रही है कि प्रशांत किशोर बंगाल विजय के बाद ममता बनर्जी को दो पैरों से दिल्ली जिताने के मिशन पर निकल पड़े हैं, लेकिन ये भी है कि सबके मन में ये बात तो होगी ही कि कांग्रेस नेतृत्व को कैसे राजी किया जाए कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावा न भी छोड़े तो कम से कम इस बात के लिए तो तैयार हो कि प्रधानमंत्री पद का फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद आम सहमति से होगा।

● **बिन्दु माथुर**

कांग्रेस के सामने और मुश्किलें

जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर ने शरद पवार को आगे कर विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की है, कांग्रेस के लिए आगे और भी मुश्किलें होने वाली हैं। और तो और कमलनाथ के शरद पवार के पास जाकर हालचाल पूछने के वाकये के बाद लगता है कि कांग्रेस भी कहीं नहीं बातचीत से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। जरूरी नहीं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को विपक्षी नेता वास्तव में अलग-थलग रखने की हिम्मत जुटा भी पाएं। ये भी हो सकता है कि जब विपक्ष के सक्रिय दलों के बीच आम सहमति बन जाए तो कांग्रेस को उसका शेयर ऑफर किया जाए। जैसे एक बार आम चुनाव के वक्त सुनने में आया था, ममता बनर्जी की ही तरफ से ही कि कांग्रेस भी विपक्ष के साथ गठबंधन में शामिल हो जाए।

नाक की लड़ाई

कांग्रेस नेता सचिन पायलट के मित्र भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट में शामिल होने से पहले मीटिंग कर रहे थे तब राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंहगाई के खिलाफ जयपुर शहीद स्मारक पर 40 डिग्री तापमान में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे थे। ठीक उसी वक्त जयपुर के मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान के भेजे गए दो प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ राजस्थान के सियासी संकट को खत्म करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। यह तीनों तस्वीरें अलग-अलग हैं, मगर तीनों का रिश्ता कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के भूत और भविष्य से जुड़ी हुई कहानी से है। सचिन पायलट के भीतर क्या चल रहा है इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट खुद के अंदर के द्वंद से जूझ रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पायलट उलझन में हैं। पहली तस्वीर पर चर्चा करें तो यह बात सच है कि भाजपा सचिन पायलट को अपने पास चाहती थी और चाहती है। आज के दिन का सच तो यही है कि पायलट भाजपा के पास होकर दूर निकल गए हैं।

सिंधिया की तस्वीर के साथ देर रात तक सोशल मीडिया पर बहस चलती रही कि क्या सचिन पायलट भी राष्ट्रपति भवन में भाजपा के मंत्री के रूप में शपथ लेंगे? कहा जाता है कि भाजपा ने आखिरी वक्त तक सचिन पायलट का इंतजार किया। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी यही चाह रहे थे कि सचिन पायलट भाजपा के पाले में आ जाएं। गांधी परिवार के बाहर सचिन पायलट अकेले ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक की भूमिका पूरे देश में निभाते हैं। चाहने वालों की जबरदस्त टीम राजस्थान में है और इसके अलावा जातीय आधार उप्र, हरियाणा से लेकर जम्मू-कश्मीर तक है। मगर कहा जाता है कि सचिन पायलट के इच्छा तारे पाने की नहीं बल्कि चांद पाने की है। वह केंद्र में मंत्री बनने के बाजार राजस्थान में संघर्ष कर मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सपना था मगर जिस तरह के हालात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके चल रहे हैं अब सचिन पायलट की जिद है।

दूसरी तस्वीर जयपुर के शहीद स्मारक पर नजर आयी जब महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस के धरने में सचिन पायलट पहुंचे हुए थे और महंगाई से ज्यादा 'सचिन पायलट तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं' के नारे गूंज रहे थे। यह नारा लगते हुए सचिन पायलट चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर बरसे।

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका प्रहार दो धारी था। पहला कि वह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ राजस्थान में अकेला संघर्ष कर रहे हैं और दूसरा कांग्रेस आलाकमान को दिखाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस के लिए पसीना बहा रहे हैं। सालभर पहले सचिन पायलट के सामने कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की फौज सर झुकाए रहती थी वह सचिन पायलट भीषण गर्मी में जयपुर के पार्षद मनोज मुदगल और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के साथ भाजपा पर हमला बोल रहे थे।

सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता के लिए यह आसान काम नहीं है, मगर सचिन पायलट यह दिखाना चाहते हैं कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट के आने की खबर सुनकर कोई भी मंत्री और कांग्रेस का पदाधिकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से घोषित भाजपा के विरोध कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष और सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे प्रताप सिंह खाचारियावास और प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस प्रदर्शन से दूर रहे।

आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। मगर वो उनके संघर्ष और जिद्दीपन की इंतेहा है कि अपने ईगो को किनारे रखकर वह कांग्रेस को लीड करते हुए राजस्थान में दिखना चाहते हैं। इससे पहले फिर से बिल को लेकर भी सचिन पायलट राजस्थान में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सड़क पर उतरे मगर कांग्रेस में उसे तवज्जो नहीं दी गई। इसलिए कहा जा सकता है कि पायलट के लिए यह राह आसान नहीं है क्योंकि ये तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री निवास से अलग आ रही थी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

इंतजार की इंतेहा

सचिन पायलट के लिए सब्र का समंदर बनने का यह भी इम्तिहान और इंतहा ही है। खबर आई कि कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है और कहा है कि जुलाई में गहलोत-पायलट विवाद को खत्म किया जाए। मगर कांग्रेस आलाकमान इतना मजबूत नहीं है कि अशोक गहलोत को निर्देश दे सके। लिहाजा अजय माकन से बात बनी नहीं और अब कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह एक बार फिर से सोनिया गांधी से चर्चा करने के बाद अजय माकन दोबारा आएंगे। मसला यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुरे वक्त में साथ दिया है उनको हम छोड़कर कांग्रेस की राजनीति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और अशोक गहलोत को संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वह कमजोर पड़ गए हैं बल्कि यह बताना चाहते हैं कि सचिन पायलट को हमने हाशिए पर धकेल दिया है। कांग्रेस के अंदर यह लड़ाई अब गहलोत और पायलट की नाक की लड़ाई बन गई है जिसमें कांग्रेस की नाक काटी जा रही है। सचिन पायलट वापस राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं या फिर कांग्रेस का महासचिव बनकर पार्टी की सेवा करना चाहते हैं यह भी साफ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के पसंद के विधायकों को उनके कोटे से मंत्री बनाएंगे और बनाएंगे तो कितना बनाएंगे यह भी विवाद का विषय है। अशोक गहलोत की राजनीति को तो आप जानते हैं कि उनकी राजनीति में न इंकार है ना इकरार है बस इंतजार है। सचिन पायलट के लिए यह नर्व वार बन चुका है।

लड़ाई भाजपा बनाम सपा ही!

उप्र में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखकर साफ लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच ही होने वाली है।

2022 में होने वाले उप्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। भाजपा और संघ के बीच कई दिनों से चल रही मैराथन बैठकों का निचोड़ सामने आ चुका है। उप्र का सियासी किला बचाने के लिए भाजपा और संघ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई जा चुकी है। हालांकि, इसके साथ ही जातिगत समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के गैर-यादव ओबीसी फॉर्मूले को साधने की कवायद भी तेज कर दी गई है।

वहीं, सियासी हलकों में इस चर्चा ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि अगले साल का उप्र विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी होना तय है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई को देखते हुए कांग्रेस और वाम दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरेंडर कर दिया था। उप्र के आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति कांग्रेस और बसपा के सामने भी आ सकती है। जिसकी वजह से इन राजनीतिक दलों को मजबूरन समाजवादी पार्टी के नाम पर चुप्पी साधनी पड़ सकती है। उप्र के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा के सामने भी सपा का मौन समर्थन करने की स्थिति बन सकती है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2017 और 2019 में गठबंधन का सारा गणित पढ़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनका ध्यान उप्र की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले छोटे राजनीतिक दलों की ओर ही होगा। इन दलों में से कुछ बीते चुनाव में भाजपा की योगी सरकार के साथ थे। सपा गठबंधन में बड़े दलों को जगह नहीं देगी। इतना ही नहीं अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ भी संबंधों को सुधारने की कवायद में लगे हैं। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह की जसवंतनगर विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार नहीं उतारेगी और प्रसपा के साथ गठबंधन करेंगे।

अगर उप्र में विपक्षी दल एक होते हैं, तो भाजपा को लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने का एक और मौका मिल सकता है। भाजपा ये कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगी कि सत्ता पाने की लालसा में ये सभी दल एक हुए हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य का उदाहरण भी दिया जाएगा। जहां सत्ता के लिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाली विचारधाराओं का गठबंधन बनाकर सरकार चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 लोकसभा चुनाव वाली भाषा में कहें, तो 'महामिलावटी गठबंधन' हुआ है। वैसे, बीते दोनों चुनावों में क्रमशः कांग्रेस और बसपा से मिले कटु अनुभवों के साथ ही राजनीतिक नुकसान झेलने के बाद शायद ही अखिलेश यादव ऐसे किसी गठबंधन के बारे में सोचेंगे भी।

गठबंधन से इतर बात करें, तो उप्र में चुनाव लड़ने के लिहाज से फिलहाल एक्टिव संगठन सपा के ही पास नजर आता है। कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन के दौरान सपा ने इन पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ताओं में बड़ी सेंध लगाई थी। कहना गलत नहीं होगा कि बसपा और कांग्रेस से बाहर होने वाले ज्यादातर नेताओं की शरणस्थली के तौर पर सपा सबसे आगे है। वहीं, 1989 के बाद से उप्र की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस के पास न संगठन है, न कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिल्ली और ट्विटर के जरिए ही उप्र संभालती नजर आती हैं। कोरोना महामारी की वजह से प्रियंका गांधी के भी उप्र दौरों पर लगाम लगी है। उप्र में कांग्रेस के पास दो ही विकल्प दिखाई देते हैं, या तो वे गठबंधन करें या चुप रहकर सपा की मदद करें। ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का सहयोग किया था। आखिर दुश्मन नंबर वन तो यहां भी भाजपा ही है। वहीं, इस संदर्भ में बसपा की बात करना भी बेमानी सा लगता है। सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उप्र को छोड़कर पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत करने की जुगत भिड़ा रही हैं। चुनाव से पहले ही कांशीराम के करीबी रहे रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया है। उप्र में मायावती की सक्रियता केवल ट्विटर और औपचारिक बयानों तक ही सीमित है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

सपा को मिल सकता है भरपूर फायदा

अगर उप्र में सपा प्रमुख तौर पर चैलेंजर बनकर सामने आती है, तो पश्चिम बंगाल की तरह ही यहां भी मुस्लिमों का एकमुश्त वोट अखिलेश यादव के पाले में आ सकता है। मुस्लिम वोटर्स का वोट काफी हद तक भाजपा के विरोध में ही जाता है। अगर सूबे में विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल की तरह कांग्रेस और बसपा चुप रहते हैं, तो मुस्लिमों के लिए विकल्प चुनना आसान होगा। वहीं, उप्र में जोर-आजमाइश की कोशिश करने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शायद इस बार कोई चुनावी शरारत करना नहीं चाहेंगे। अगर वो बंगाल की तरह यहां भी कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने के लगने वाले आरोपों को भी बल मिलने का अंदेशा रहेगा। भाजपा के रणनीतिकारों को पूरा भरोसा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जिसके चलते मुस्लिम वोट बंटेगा और उसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। लेकिन, ऐन वक्त पर कांग्रेस और वामदल ममता बनर्जी को मूक समर्थन देते हुए पर्दे के पीछे चले गए। वहीं, उप्र के मतदाताओं के सामने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों का ये खेल नया नहीं रह गया है। भाजपा भी इससे सबक ले चुकी है। मुस्लिम वोटों का एकतरफा होना तो तय है। धर्म और जाति के समीकरणों को तमाम चीजों से ऊपर रखने वाले मतदाताओं के बीच अब सवाल यही है कि क्या उप्र में हिंदू वोट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा?

विरासत पर घमासान

चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच छिड़ी विरासत की जंग से बिहार का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग और पशुपति ने अपने-अपने तरीके से इस विरासत पर पकड़ बनाने की कोशिश की। वैसे, 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती से इतर राष्ट्रीय जनता दल का 25वें स्थापना दिवस यानी आरजेडी की रजत जयंती भी थी। रजत जयंती कार्यक्रम में करीब साढ़े तीन साल बाद लालू प्रसाद यादव आरजेडी नेताओं से वर्चुअल रूप से मुखातिब हुए। इस पूरे कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव चर्चा का केंद्र रहे। लेकिन, सुर्खियां बटोर ले गए लालू के बड़े लाल।

दरअसल, लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेजप्रताप यादव ने मंच पर पहुंचते ही जमकर भड़ास निकाली। तेजप्रताप यादव ने अपने भाषण के दौरान मंच पर बैठे छोटे भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तंज कसे। पार्टी में अपनी उपेक्षा को लेकर एक बार फिर से तेजप्रताप का दर्द छलककर लोगों के सामने आ गया। इस तमाम घटनाक्रम के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी में भी विरासत की जंग छिड़ सकती है। इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या लालू अपने बेटों को एक रख पाएंगे? या आरजेडी में भी विरासत पर घमासान होगा।

चर्चा से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजप्रताप यादव ने ऐसा क्या कह दिया, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल, रजत जयंती के मौके पर तेजप्रताप यादव ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने आरजेडी के नेताओं को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। छोटे भाई तेजस्वी यादव भी तेजप्रताप के लपेटे में आ ही गए। उनसे पहले आए सभी नेताओं ने आरजेडी का गुणगान किया। लेकिन, तेजप्रताप यादव ने पार्टी की पोल खोलना शुरू कर दिया। भाषण के दौरान तेजप्रताप यादव ने पिता के साथ अपनी करीबी भी जताई। उन्होंने कहा कि पिताजी ने हमको फोन कर कहा- अभी तक यहीं हो, जाओ जल्दी। मुझे पूजा-पाठ में देर हो गई। यहां आए, तो देखा कि तेजस्वी यादव बाजी मार गए और मंच पर पहले ही आकर बैठ गए हैं।

वैसे, तेजप्रताप खुद को तेजस्वी से बेहतर मानते हों या नहीं। लेकिन, इतना जरूर मानते हैं कि वो तेजस्वी को हर मुश्किल मौके पर अपना सहयोग देकर बचाते रहे हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे देखकर विरोधी भी कहते हैं कि ये दूसरा लालू यादव है। जब-जब विरोधियों ने अर्जुन पर वार किया, तो श्रीकृष्ण ने बचाव किया। ऐसे ही जब भी तेजस्वी यादव पर हमला होगा, तो कृष्ण के तौर पर मैं उनका बचाव करूंगा। कहा जा सकता है कि तेजप्रताप यादव अपने छोटे भाई की छाया के तले रहकर पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। वो पार्टी में रहना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के समकक्ष जगह चाहते हैं।

वहीं, भाषण की शुरूआत से ही तेजप्रताप यादव ने खुद को लालू यादव के जैसा जताने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। खुद को पिता के नक्शेकदम पर चलने वाला बताने के लिए तेजप्रताप ने बीएन कॉलेज में दाखिले और लालू यादव की क्लासरूम बेंच पर बैठने की बात कही। तेजप्रताप ने कहा कि मैं पिता लालू यादव की तरह हूं। लोग उनसे डरते हैं और हमसे भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब बोलते हैं, तो कुछ लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लालू यादव भी जब बोलते थे, तो विरोधी हंसते थे। पिता मंच पर आते थे, तो लोगों का मनोरंजन भी होता था और काम भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगठन समुद्र है, इसमें बहुत सारे लोग आते और जाते हैं। कुछ लोग रूठते हैं, जिन्हें मनाना भी पड़ता है। इन तमाम बातों से एक चीज स्पष्ट है कि तेजप्रताप यादव आरजेडी में अपनी उपेक्षा को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कई नेताओं पर भी भरपूर निशाना साधा। तेजप्रताप यादव ने आरजेडी विधायकों की विधानसभा में पिटाई के मामले पर कहा कि कुछ लोग हमें पीछे खींचते हैं। वो चाहते हैं कि हम हीरो न बन जाएं। लाठीचार्ज के दौरान मैं आगे जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया। तेजप्रताप ने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लाठीचार्ज के बाद कुछ नेता हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो गए। ये लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं और पार्टी कार्यालय में बैठे रहते हैं।

आरजेडी की रजत जयंती पर तेजप्रताप यादव का भाषण शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद तकनीकी कारणों से माइक गड़बड़ा गया था। जिसके बाद तेजप्रताप ने कहा कि जब भी सच बोलने लगता हूं, ये सब होने लगता है। लोग सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। लेकिन, सच की जीत होती है। इशारों में मैंने बहुत बातें कह दी, जिन्हें समझना था, वो समझ गए होंगे। तेजप्रताप का इशारा किस तरफ था, ये सभी को पता है। तेजप्रताप यादव अपने पूरे भाषण के दौरान पिता लालू यादव की विरासत पर सीधा हक जमाते हुए नजर आए। उन्होंने तेजस्वी का नाम लिए बिना ही नसीहत दे डाली कि संगठन में सबको साथ लेकर चलना होगा।

● **विनोद बक्सरी**

विरासत के ऐलान के समय ही छलका था दर्द

2017 में लालू यादव ने जब तेजस्वी को पार्टी की विरासत सौंपने का ऐलान किया था। उसके कुछ ही दिनों बाद तेजप्रताप का दर्द ट्वीट के जरिए बाहर आ गया था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें दुख होता है कि आरजेडी में उनकी अनदेखी की जा रही है। तेजप्रताप ने उस ट्वीट में साजिश की आशंका भी जताई थी। हालांकि ट्वीट के बाद उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी से किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हुए उन्हें कलेजे का टुकड़ा बताया था। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को लेकर भी तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच तनातनी हो चुकी है। दरअसल, दलितों के सम्मान को लेकर तेजप्रताप यादव ने रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन, तेजस्वी ने पूर्वे को अभिभावकतुल्य बताते हुए तेजप्रताप के आरोपों को खारिज कर दिया था। इस मामले के कुछ ही समय बाद रामचंद्र पूर्वे की प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई हो गई थी। ऐसे ही कई मौकों पर तेजप्रताप के फैसलों पर तेजस्वी के सवाल उठाने से दोनों भाईयों के बीच पार्टी में प्रभुत्व को लेकर गरमा-गरमी बनी रहती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरजेडी में पार्टी के चेहरे और उत्तराधिकार की जंग लंबे समय से चल रही है।

संकट से घिरा नेपाल

नेपाल एक बार फिर राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक के साथ-साथ विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुछ हालिया फैसलों ने न केवल नेपाल को उपहास का पात्र बनाया, बल्कि नेपाली लोकतंत्र की बुनियाद भी हिला दी है। नेपाल में लोकतंत्र की पहली बयार 1951 में चली, जब 104 वर्ष की राणाशाही का अंत हुआ और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। राणावंश से पूर्व शाहवंश का शासन था। वर्ष 1955 में महाराजा त्रिभुवन की मृत्यु के बाद महाराजा महेंद्र का राजतिलक हुआ। फिर 1959 में संविधान लागू किया गया और आम चुनाव हुए। चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन राजवंश को नई लोकतांत्रिक व्यवस्था रास नहीं आ रही थी। लिहाजा राजा महेंद्र ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। संसद एवं संविधान भी भंग कर दिए गए और दल विहीन पंचायत प्रणाली शुरू की गई। लंबे समय तक ऐसी राजनीतिक उठापटक से जूझते हुए अप्रैल 2008 में आखिर राजशाही की आधिकारिक तौर पर समाप्ति हुई। संवैधानिक सभा के लिए चुनाव हुए। जुलाई 2008 में माओवादी नेता प्रचंड के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। नेपाली कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। एक प्रशासनिक भूल के कारण प्रचंड को तब इस्तीफा देना पड़ा, जब मई 2009 में उन्होंने सेनाध्यक्ष रूकमांगद कटवाल को पद से बर्खास्त कर दिया था।

यह भी एक तथ्य है कि नेपाली कम्युनिस्ट उस चीनी वामपंथी विचार को गलत साबित कर चुके हैं कि सत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है। जब प्रचंड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'एमाले' ने मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) का गठन किया तो लगा था कि उनके नेतृत्व में स्थायी सरकार बनेगी। चुनाव नतीजों ने जनता को भी उत्साहित किया, क्योंकि पांच दशकों के बाद पहली बार किसी ऐसी सरकार का गठन हुआ, जो बिना किसी बाधा के अपना कार्यकाल पूरा करती दिख रही थी। एनसीपी ने दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। बड़ा दल होने के नाते केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी की कमान प्रचंड को सौंपी गई। हालांकि नेपाल में संवैधानिक समस्याओं, मर्यादा, आचार संहिता और मूल्यों का इतना ह्रास कभी देखने को नहीं मिला, जितना संयुक्त कम्युनिस्ट नेताओं के कार्यकाल में दिखा। ओली को पहले 'भारत समर्थक' नेता माना जाता था, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने सीमा और जल विवाद जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। उनके रवैये के कारण कई बार सीमा पर तनातनी जैसी स्थिति बनी।

नेपाल में नई सरकार

नेपाल में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने हैं। शेर बहादुर देउबा नेपाल में अब तक विपक्ष में रही पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस गठबंधन में नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (माओवादी), सीपीएन-यूएमएल माधव कुमार नेपाल-झालानाथ खनाल गुट, जनता समाजवादी पार्टी का उपेंद्र यादव गुट और राष्ट्रीय जनमोर्चा शामिल हैं। नेपाल में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके देउबा को भारत समर्थक माना जाता है। 2017 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। देउबा भारत के साथ आर्थिक रिश्तों से लेकर मधेशियों के मामले में नरम रवैया दिखाते रहे हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद भंग कर दी थी। नेपाली संसद पिछले 5 महीने में दूसरी बार भंग की गई थी। उन्होंने 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 से ज्यादा पिटीशन लगाई गई थीं।

मई 2020 में जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धारचूला के बीच सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल सरकार द्वारा देश का नया नक्शा जारी कर एक अजीब संकट पैदा कर दिया गया। मार्च 1816 की सुगौली संधि का हवाला देकर ओली ने कथित तौर पर अपनी जमीन वापस मांगी। यह वह दौर था जब नेपाल के तराई इलाकों के नागरिकों को भयंकर यातना एवं अभावों से जूझना पड़ा था। मधेशियों के समर्थक दलों को ओली सरकार के विरुद्ध कई महीने संघर्ष करना पड़ा।

यह तब है जब ओली ने ही राजनीतिक अवसरवाद के चलते पहले मधेशियों की पार्टी समाजवादी जनता पक्ष में विभाजन कराया और उपप्रधानमंत्री समेत दर्जनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर उन्हें असंवैधानिक करार दिया। उसका कहना था कि संसद भंग होने के बाद कैबिनेट विस्तार अवैध है। चूंकि कोई भी कार्यवाहक सरकार चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के पक्ष में बताया जा रहा है, लेकिन यह कहना कठिन है कि भविष्य का घटनाक्रम नेपाल में लोकतंत्र को मजबूती देगा। इससे पहले एनसीपी में मतभेद और दूरी के पीछे भी ओली का अलोकतांत्रिक और मनमाना रवैया ही जिम्मेदार माना गया। उन्होंने अपने विरोधियों से निपटने और अपने हितों की पूर्ति में ही पूरी ऊर्जा लगा दी है। इसके लिए उन्होंने चीन का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया। फिर भी वह प्रतिनिधि सभा यानी संसद का विश्वास नहीं हासिल कर सके। परिणामस्वरूप अब अल्पमत सरकार चला रहे ओली ने नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा की है। अब देखना यही होगा कि चुनाव नतीजे क्या कहते हैं? संसद में बहुमत खोने के बावजूद ओली अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से ओली पर लगाम लगनी तय मानी जा रही है। वहीं इसे भारत की जीत मानी जा रही है।

● **राजेश बोरकर**

बड़ी चुनौती बनता चीन

चीन पर राज करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने थ्येनआनमन चौक से अपना जो भाषण दिया, उससे न केवल चीन की विस्तारवादी सोच झलकती है, बल्कि उसके दंभ के कारण विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों की भी झलक मिलती है। माओत्से तुंग ने जब सोवियत संघ से प्रेरित होकर 1 जुलाई 1921 को सीसीपी की नींव रखी थी, तब उनका मकसद चीन को गरीबी से बाहर निकालकर देश को उस मुकाम पर पहुंचाना था, जहां वह तीन-चार सौ वर्ष पहले था। एक समय भारत और चीन, विश्व व्यापार में अपना आधिपत्य रखते थे, लेकिन समय के साथ दोनों पिछड़ गए और उनकी गिनती गरीब देशों में होने लगी। कभी विश्व व्यापार में चीन की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो 1941 में आधा प्रतिशत पर आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे रहे कि चीनी नेताओं को अमीर देशों के सामने अपमानित होना पड़ा। इस अपमान से विचलित हुए बगैर चीनी नेता अपने देश को आगे ले जाने की रूपरेखा बनाने में जुटे रहे।

चीन ने पिछले तीन-चार दशकों में अपनी आर्थिक तरक्की के बल पर करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के पूरे व्यापार पर करीब 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी कायम कर ली। ऐसी उपलब्धि की मिसाल मिलना कठिन है। 50 वर्षों में दो प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस चमत्कार के पीछे चीनी नेताओं की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता रही। चीन का यकीन इस पर नहीं कि जनता की भागीदारी से विकास होता है। अभी भी वह एक पार्टी वाली शासन व्यवस्था को आदर्श मान रहा है। लोकतंत्र और साम्यवाद के तौर-तरीके बिलकुल अलग होते हैं। जहां लोकतंत्र में जनता के वोट से सरकारें बनती हैं वहीं साम्यवाद में एक ही पार्टी का एकछत्र राज चलता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर कानूनों का निर्माण इस सोच के साथ किया जाता है कि सबको समान अधिकार मिले और किसी का दमन न हो। ऐसे देशों के औसत नागरिकों की सोच में अधिकार सर्वोच्च हो जाते हैं और कर्तव्य पीछे। चीनी नागरिकों के पास कोई खास अधिकार नहीं है और चीनी सत्ता को इसकी परवाह भी नहीं कि अपने नागरिकों के दमन पर विश्व उसके बारे में क्या सोचेगा? चीन ने जैसे थ्येनआनमन चौक पर लोगों का दमन किया, वैसे ही उइगर मुसलमानों का कर रहा है। चीन के अधिकांश नागरिक यह मानते हैं कि देश के सामने उनके अधिकार गौण हैं।

1970 के आसपास चीन ने अपने कारखानों को सरकारी मदद से खड़ा किया। आज भी उसके अधिकांश कारखाने सरकारी मदद से ही चलते हैं। वैसे तो यह भारत की तरह के सार्वजनिक उपक्रम हैं, पर उत्पादकता के मामले में चीन के कारखानों का कोई सानी नहीं। भारत में चाहे सरकारी मदद से चलते कारखाने हों या प्राइवेट सेक्टर के, वे उत्पादकता के मामले में चीन के सामने ठहरते ही नहीं। इसी कारण जिस समय विकसित देश अपने उद्योगों की आउटसोर्सिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने चीन को पसंद किया और भारत हाथ मलता रह गया। चीन की तरक्की का कारण यह भी है कि उसे अपनी योजनाओं को अमल में लाने में किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले के नेताओं ने चीन के विकास का जो सपना देखा था, उसे ही उनके उत्तराधिकारियों ने देखा और उसे साकार करने में जुटे रहे। इसके विपरीत भारत के नेताओं ने देश के विकास का कोई साझा सपना नहीं देखा। यहां हर सरकार अपनी तरह से देश का विकास करना चाहती है।

इसमें दो राय नहीं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र है। वह मानवाधिकारों को कोई महत्व नहीं देता और पड़ोसी राष्ट्रों को धमकाता रहता है, लेकिन इस सबके बाद भी उसने अपने लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। निसंदेह चीन की इस बात के लिए आलोचना होती है कि वह गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और खुद से असहमत अपने लोगों का दमन करता है, लेकिन वह अपने आर्थिक विकास को सर्वोच्च महत्व देता है और हर हाल में उस पर ध्यान केंद्रित किए रहता है। चूंकि वह अपनी आर्थिक ताकत के नशे में चूर है इसलिए आगे भी विश्व समुदाय की निंदा-आलोचना की परवाह नहीं करने वाला। वह महाशक्ति बनने और अमेरिका का स्थान लेने को तैयार है। आज अमेरिका के सामने उसकी वही स्थिति है, जो एक समय सोवियत संघ की थी। चीन के अड़ियलपन और अहंकारी रवैये की कितनी भी आलोचना की जाए, उसने आर्थिक विकास के मामले में जो कुछ हासिल किया है, उसकी अनदेखी कम से कम भारत को नहीं करनी चाहिए।

● **ऋतेंद्र माथुर**

अपनी जरूरत का हर सामान खुद बनाता है चीन

जहां भारत अपनी तमाम जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, वहीं चीन अपनी जरूरत का हर सामान खुद बनाता है। इतना ही नहीं, वह दुनिया का कारखाना बना हुआ है। डिजिटल तकनीक के मामले में तो वह अमेरिका से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। एक समय चीनी वस्तुओं की गुणवत्ता घटिया होती थी, लेकिन धीरे-धीरे वह गुणवत्ता प्रधान वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम हो रहा है। उसके विश्वविद्यालय भी विश्वस्तरीय बन रहे हैं और शोध-तकनीक के संस्थान भी। वह कई मामलों में अमेरिका के समकक्ष खड़ा नजर आता है। उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की धाक बढ़ती जा रही है। विश्व में शायद ही कोई देश हो, जो व्यापार में चीन का प्रमुख सहयोगी न हो। चीनी सत्ता अभी भी यह नहीं मानती कि चीन शिखर पर है। उसकी सोच चीन को सिरमौर बनाने की है। चीन के इरादों से भारत समेत दुनिया के लोकतांत्रिक देशों का सशंकित होना स्वाभाविक है। भारत को कहीं अधिक चिंतित होना चाहिए, क्योंकि चीन न केवल पड़ोसी देश है, बल्कि हमारी तरक्की की राह को रोकना चाहता है। ऐसे में हमारे नेताओं को यह सोचना होगा कि चीन का मुकाबला कैसे किया जाए? राजनीतिक नेतृत्व के साथ आम जनता को भी अपनी व्यवस्था की खामियों के बारे में सोचना होगा। यदि इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा गया तो चीन का मुकाबला करना और कठिन होता जाएगा।

बेटियों का दुख

कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो कई दिनों तक हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। जिसे देखकर ही पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि क्या इस जमाने में भी ऐसा हो सकता है। किसी बेटी के मायके आने की ऐसी सजा कौन देता है...

पिछले कुछ दिनों के दौरान मप्र में दो दिल दहलाने वाले मामले सामने आए हैं। पहली घटना अलीराजपुर जिले के बोरी थाने के बड़े फुटतालाब गांव की है, जहां एक आदिवासी लड़की को परिवार वालों ने बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो इतना भयावह है कि जिसने भी देखा, उसकी रूप कांप गई। लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को तरस नहीं आई। हैरानी की बात यह है कि लड़की पर यह जुल्म गैरों ने नहीं, अपनों ने ही किया। आरोपियों में लड़की के पिता और चचेरे भाई शामिल हैं। पीड़िता का कसूर सिर्फ इतना था कि वह बिना बताए रिश्तेदार के यहां चली गई थी।

यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि धार जिले के टांडा थाना के तहत ग्राम पीपलवा के परिवारजनों की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना में दो युवतियों को परिवार वाले लाठी-डंडों से पीटते और उनके साथ जानवरों सा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। लड़कियां चिल्लाती रहीं, लेकिन इंसानों से हैवान बने लोगों का दिल रत्तीभर नहीं पसीजा। रोती-बिलखती लड़कियां उनसे रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन वहां रहम नहीं लाठी-डंडों से पिटाई मिली। लड़कियों का कसूर बस इतना था कि दोनों अपने मामा के लड़कों से बात करती थीं।

हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां मौजूद लोग लड़कियों को बचाने की बजाय इस घटना का वीडियो बना रहे थे। इन दोनों ही घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद पुलिस हरकत में आई और आनन-फानन में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। जरूरी है कि ऐसी घटनाओं में शामिल तमाम आरोपियों पर कठोर कारवाई और सजा दी जाए। साथ ही समाज के लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं का वीडियो बनाने की बजाय पीड़ितों की मदद करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। आखिर सवाल तो यही उठता हैं कि कब रुकेंगे बेटियों पर अत्याचार! कोई समाज कब तक इस तरह के अंधेरे में डूबा रहेगा, जिसमें स्त्रियों को गुलामी में अपना जीवन काटना पड़ता है? स्त्रियों पर जुल्म ढाने वाले मानवीयता से वंचित ऐसे लोगों को कब सभ्य होने का मौका मिलेगा?

दरअसल, मप्र के अलीराजपुर की 20 साल की इस महिला का कसूर केवल इतना था कि शादी के बाद जब इसका पति गुजरात काम करने चला गया तो यह अपने मामा के घर चली आई। इस घटना की दो वीडियो वायरल हुई है। पहली वीडियो में उसके ही घर के पुरूष उसे दौड़ा-दौड़ाकर महिला को पीट रहे हैं। कभी लात तो कभी घूसे से। वहां मौजूद लोग तामाशा देख रहे हैं। दूसरी वीडियो में उसे रस्सी से बाधकर पेड़ से लटका दिया गया है। उसे झूले की तरह तीन पुरूष एक-दूसरे के पास धक्का दे रहे हैं बारी-बारी से सभी उस पर डंडे बरसा रहे हैं। वह चिल्ला-चिल्ला कर रो रही है, लेकिन सभी तमाशाबीन बनकर दर्शक बने हुए हैं किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी है।

इस महिला के साथ ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ही भाई और पिता हैं। अब अगर पुलिस उनको सजा दे भी दे तो क्या उस लड़की को उसका सम्मान दिला पाएगी। हमारे समाज में तो ही होता है ना गलती करने वाला शर्मिंदा नहीं होता बल्कि पीड़िता ही लोक-लाज में जीती है। मानो जैसे गलती उसकी हो। इस महिला की गलती यह थी कि शादी के बाद पति गुजरात काम करने चला गया तो यह अपने परिजनों को बिना बताए अपने मामा के घर चली गई थी। नाराज मायके वाले महिला को लेकर आए फिर गुस्से में उसे बुरी तरह पीटा। अब जिस लड़की के भाई और पिता ऐसे हों उसे किसी और अपराधी की जरूरत क्या है। हमारे देश में महिलाएं अपने घरों मे हिंसा की शिकार हो जाती हैं। हर मामले में उन्हें दबाया जाता है, वे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी भी नहीं सकती। ऐसा लगता है महिलाओं को इंसान समझा जाना अभी बाकी है। हम किस युग में जी रहे हैं। क्या हमारी दुनिया बस उन्हीं लोगों तक सीमित हैं जो शहरों में दो घरों के कमरे में रहते हैं। जिनके पास खाने का भोजन है, शनिवार को अच्छी तरह तैयार होकर बाहर डिनर और रविवार की सुबह देर तक सोना है। दिन में फिर वेब सीरीज देखनी है और शाम को कहीं घूम आना है। बड़े शहरों में या छोटे शहरों में काम करती महिलाओं को देखकर तो लोग यही सोचते हैं कि इस जमाने में वो महिलाएं कौन सी हैं जो अपने हक की बात करती हैं, सब तो हैं इनके पास पता नहीं इन्हें अब क्या चाहिए।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

हाशिये पर खड़ी स्त्री से जुड़े सवालों को तो मत छोड़िए

आप सिलबट्टे पर क्रांति करिए लेकिन स्त्री विमर्श के बुनियादी मुद्दों और हाशिये पर खड़ी स्त्री से जुड़े सवालों को तो मत छोड़िए। यह सवाल हमारे शहरी, वर्गवादी विमर्श से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चटनी खाइए या मत खाइए, मिक्सर में पीसिए या सिलबट्टे पर लेकिन जो जरूरी बहस है उसे अनदेखा मत कीजिए। जिस मायके में शादी के बाद लड़की के जाने पर उसका स्वागत होता है उसी घर में क्या हुआ यह आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले स्त्री को मनुष्य समझ लिया जाए उसके बाद बाकी बातों की बारी आती है। सिलबट्टा और चटनी तो इसके सामने एक छोटी सी चर्चा भर है, हालात तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। जो सोशल मीडिया की लड़ाई तो चलती रहती है लेकिन हकीकत आज भी संकुचित सोच रखने वाले घरों में दिख जाती है।

योगः कर्मसु कौशलम

श्रीमद्भगवत गीता योगशास्त्र है। प्राचीन काल से ही योग का अस्तित्व देखा जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमद्भगवत गीता है, जो सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर तक श्रीकृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवतगीता में पहली बार योग शब्द श्रीकृष्ण (जिनको योगेश्वर श्रीकृष्ण भी कहते हैं) ने अर्जुन को अपने जीवन में असमर्थता पर काबू पाने के लिए प्रदान किया था। गीता में वर्णित 18 अध्याय हमको श्रीकृष्ण द्वारा उल्लेखित योग के बारे में बताते हैं। अठारह अध्यायों में से प्रत्येक को एक अलग नामों में नामित किया गया है क्योंकि प्रत्येक अध्याय, शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित करता है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विशाद योग है। चितकों को लगा कि कहीं विशाद भी योग बन सकता है। विशाद को आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि गीता गोविंद की वाणी है। गीता को हमें जीवन में धारण कर उसे व्यवहार में लाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जब मेरे जीवन में समस्या आई, या मैं कभी निराशा में गिरा, तो गीता की शरण लेता था। धर्म केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है कि सत्य बोलो, धर्म को आचरण में लाओ। इस दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालुओं को झूमते देखा गया।

कर्मों में कुशलता का नाम योग है। भारत की प्राचीन धरोहरों में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान आध्यात्मिकता से युक्त हैं। कर्म को पूजा भाव से करने की परम्परा भारतीय समाज का अंग रहा है। भगवान श्रीकृष्ण ने समाज को कर्म की प्रेरणा गीता में दी है। श्रीकृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। कर्म की कुशलता ही योग है।

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है, 'योगः कर्मसु कौशलम' अर्थात् योग से कर्म में कुशलता आती है। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, 'सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते' यानी अंत:करण की शुद्धि से ज्ञान मिले, न मिले-दोनों ही दशाओं में सम रहें, यही योग है।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।।

कर्मों में कुशलता का नाम योग है। भारत की प्राचीन धरोहरों में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान आध्यात्मिकता से युक्त हैं। कर्म को पूजा भाव से करने की परम्परा भारतीय समाज का अंग रहा है। भगवान श्रीकृष्ण ने समाज को कर्म की प्रेरणा गीता में दी है। श्रीकृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। कर्म की कुशलता ही योग है। कर्म करने का साधन शरीर है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय भी कर्म का ही एक अंग है। भारतीय ऋषि परम्परा में आत्मा के साथ शरीर को भी स्वस्थ और निर्मल पर बल दिया गया है। क्योंकि कर्म को सम्यक प्रकार से करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है सभी प्रकार के कर्मों का माध्यम शरीर ही है। योग की सिद्धियों का माध्यम भी शरीर ही है।

भारतीय ऋषियों ने योग की अनेक सिद्धियां अर्जित की थीं। एक समय था भारत का योग विज्ञान चरम पर था इसका प्रत्यक्षीकरण रामायण और महाभारत में होता है। योग का अर्थ है जोड़ना। अपने को प्राणिमात्र में देखना तथा प्राणिमात्र को आत्मवत् देखना अर्थात् भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना ही योग है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो आत्मा और परमात्मा के सम्मिलन की अद्वैत अनुभूति योग कहलाती है।

हमारे ऋषियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के आठ प्रकार के साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टाङ्ग योग कहा जाता है। ये साधन हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके निरंतर अभ्यास से ही योग की दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो सकती है।

शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योग ही सवेत्तिम पद्धति है। विश्व में ऐसी कोई भी अन्य पद्धति नहीं है। भारत की इस प्राचीन धरोहर ने ही समाज में 'वसुधैव कुटुम्बकम' का भाव निर्माण किया था। सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया:' का वैश्विक स्वरूप भी इसी की देन है। इसके अभाव के कारण ही समाज में स्वार्थ एवं मानवीय मूल्यों का संकुचन हुआ है।

जिस डर से सब जग डरे, मेरे मन आनंद।
कब भारिहों कब पाइहों पूरन परमानंद॥

मन को वश में करने की मुक्ति ही योग है। महर्षि पातंजलि ने कहा भी है-योगश्चित्त वृत्ति निरोध:। चित्तवृत्ति के निरोध से ही योग की उत्पत्ति होती है और इसी को प्राप्ति ही योग का लक्ष्य है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने योग की महत्ता बतलाते हुए कहा है कि यद्यपि मन चंचल है फिर भी योगाभ्यास तथा उसके द्वारा उत्पन्न वैराग्य द्वारा उसे वश में किया जा सकता है।

व्यावहारिक रूप से योग का तात्पर्य होता है जोड़ना या बांधना। जिस प्रकार घोड़े को एक स्थान पर बांधकर उसकी चपलता को नष्ट कर दिया जाता है उसी प्रकार योग द्वारा मन को सीमित किया जा सकता है। विस्तार पाकर मन आत्मा को अच्छादित न करले इसलिए योग की सहायता आवश्यक भी हो जाती है। भक्तियोग और राजयोग से ऊपर उठाकर त्रिकालयोग के दर्शन होते हैं और यही सर्वश्रेष्ठ योग है।

● **ओम**

गिरगिट

नव्या की जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा था। सरकारी नौकरी के लिए कई परीक्षाएं दीं। कुछ में असफल रही। कुछ के परिणाम अभी तक नहीं आए थे। इसी बीच उसकी शादी की बात चली। सांवले रंग की भरपाई के लिए गाड़ी की मांग हुई। वह उसके पिता की क्षमताओं के बाहर था। बात खत्म हो गई।

इस समय वह बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि कोई प्राइवेट नौकरी कर ले। वह अखबार में नौकरी के इश्तिहार देखने लगी। कुछ को मार्क किया। एक जगह फोन मिलाने जा रही थी कि उसकी सहेली का फोन आया। फोन उठाते ही उसने मुबारकबाद दी। नव्या हैरान थी कि मुबारकबाद किस बात की।

सहेली ने बताया कि रुके हुए परिणामों में से एक परीक्षा का नतीजा आ गया है। वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। नव्या बहुत खुश हुई। उसने खुद भी इंटरनेट पर परिणाम देखा। वह इंटरव्यू की तैयारी करने लगी।

इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरव्यू में भी पास हो गई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई।

नौकरी लगने के एक महीने बाद ही जिन लोगों ने रिश्ता तोड़ा था वह पुनः उसके घर आए। लड़के की मां ने कहा, मेरा बेटा बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि गुण देखे जाने चाहिए। रूप रंग नहीं। लड़की ने अपनी काबिलियत से सरकारी नौकरी पाई है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। हमें गाड़ी भी नहीं चाहिए।

नव्या के पिता ने उसकी तरफ देखा। नव्या ने बहुत ही शालीनता से कहा...आंटी जी आपके बेटे के विचारों में परिवर्तन आया यह बहुत खुशी की बात है। किंतु मेरे गुण सरकारी नौकरी से नहीं आंके जा सकते। पहले गाड़ी थी अब मेरी नौकरी। यह तो मौका परस्ती है।

नव्या और उसके पिता ने हाथ जोड़कर उन्हें चले जाने को कहा।

– **अनाम**

साथ भले ही, आए न कोई

साथ भले ही, आए न कोई,
हम बढ़ते ही जाएंगे।
पथिक हैं हम, पथ ही साथी,
पथ का साथ निभाएंगे।।
अविचल होकर पथिक को बढ़ना।
बाधा कितनी भी, सघन, न डरना।
साथ भले ही मोहक प्यारे!
राह में तुझको, नहीं ठहरना।
सुख-सुविधाओं के आकांक्षी,
क्यूं कर साथ निभाएंगे।
साथ भले ही, आए न कोई,
हम बढ़ते ही जाएंगे।।
चलना ही बस मूलमंत्र है।
नहीं है, साधन, नहीं यंत्र है।
साथी ने भी, पथ है छोड़ा,
साथ हमारे, नहीं तंत्र है।
सुविधाओं में कैद हुए तुम,
हम तो अलख जगाएंगे।
साथ भले ही, आए न कोई,
हम बढ़ते ही जाएंगे।।
धन की हमको चाह नहीं थी।
पद की भी परवाह नहीं थी।
विश्वास का संबंध था चाहा,
अपयश पर भी आह! नहीं थी।
किसी से कोई, मांग नहीं है,
सबको प्रेम लुटाएंगे।
साथ भले ही, आए न कोई,
हम बढ़ते ही जाएंगे।।

– **डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी**

आबाद रहे तू

गलवान घाटी में भारतीय सेना शांति से अपने खेमे में थी और अपनी सीमा में लहराते अपने तिरंगे को देख खुश हो रही थी। जश्न का माहौल था कोई अपनी थाली को ढपली की तरह बजा रहा था, कोई गा रहा था और कोई मस्त होकर के आजादी के गीतों पर नाच रहा था। अचानक कैप्टन! चीनी अपनी हद पार कर तिरंगे की तरफ आ रहे हैं क्या? क्या कह रहे हो! सब दौड़ पड़ते हैं...थाली कहीं गिरती है चम्मच कहीं गिरता है। ठहरो! दुस्साहस मत करना।

चीनी और भारतीयों के बीच झड़प होने लगती है।

बात बढ़ती ही जा रही थी। चीनी फायरिंग पर उतर आए थे। तभी एक दहाड़ गूंजती है, मां भारती की तरफ उठने वाले हर हाथ को काट दो। झड़प हाथापाई में बदल जाती है अपने देश की रक्षा करते हुए भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे पर दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी।

बिहार, पंजाब रेजीमेंट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना के साथ आज पूरा भारत शोक में डूब गया था पर मस्तक पर विजय गर्व की आभा दमक रही थी तिरंगा ऊपर लहरा रहा था और धरा पर वीर सपूतों को अपने आंचल के नीचे समेटे गर्वित हो रहा था।

गूंज रही थी बस यही धुन 'ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू।
मैं रहूं या ना रहूं आबाद रहे तू।'

– **मंजूषा श्रीवास्तव मृदुल**

गावस्कर बनने के लिए चाहिए संयम-साहस

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर...कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा तो आपने जरूर सुना होगा। कुछ लोग छोटे कद के लोगों को हीन भावना से देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कद काबिलियत, समझदारी और बौद्धिकता मापने का पैमाना नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि काम में भी छोटे हैं। सुनील गावस्कर इसकी जीती जागती मिसाल हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10 हजार रन और 34 शतक बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 51.12 की रही है। उनके शतकों का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था।

कहा जाता है कि धन हिम्मत, योग्यता, विद्वता और दृढ़ता से बढ़ता है, चतुराई से फलता-फूलता है, लेकिन 'संयम' से सुरक्षित रहता है। संयम के बिना व्यक्ति अपने मन का गुलाम हो जाता है। इसलिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। सुनील गावस्कर से संयम की सीख लेने लायक है। क्रिकेट की पिच पर टिक कर खेलने में माहिर रहे गावस्कर के संयम की कायल पूरी दुनिया रही है। यही वजह है कि खेल के मैदान में उन्होंने जैसा सोचा लगभग वैसा ही प्रदर्शन किया। एक बार तो पिच पर ऐसे डटे कि आउट ही नहीं हुए। विरोधी टीम के गेंदबाजों ने हर रणनीति अपना ली, लेकिन उनको पवेलियन नहीं भेज पाई।

साल 1975 में वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 60 ओवर में 174 बॉल का सामना करते हुए महज 34 रन ही बनाए थे, लेकिन आउट नहीं हुए। गावस्कर ने संयमित होकर ऐसा खेल खेला कि कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उनके नाम अपनी डेब्यू सीरीज में सबसे **ज्यादा रन बनाने** का रिकॉर्ड है। साल 1970-71 के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उन्होंने 774 रन बनाए थे। उनके नाम सबसे ज्यादा 34 शतकों का रिकॉर्ड भी था, जिसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने साल 2005 में तोड़ा था। टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी गावस्कर ही थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ यह रिकॉर्ड बना था।

महज 5 फिट 5 इंच लंबे सुनील गावस्कर के अंदर समंदर जितना साहस है। एक जमाना था जब वेस्टइंडीज के लंबे-लंबे तेजतर्रार सुपरफास्ट बॉलर्स के आगे लोग हेलमेट पहनकर भी खेलने से घबराते थे, उन्हें सुनील गावस्कर ने बिना हेलमेट के खेलकर लोगों को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 27 टेस्ट खेलते हुए 13 शतक बनाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आज भी कायम है। उनको मानसिक रूप से बहुत मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। पद्मश्री से सम्मानित मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी ने एक किस्सा बताया था, 'साल 1983 में गयाना टेस्ट मैच में मार्शल की एक गेंद सीधे गावस्कर के माथे पर लगी और टकराकर काफी दूर मिड ऑफ पर चली गई। यह संकेत था कि चोट काफी घातक थी। उस वक्त वो 49 रनों पर खेल रहे थे। उनके साथी खिलाड़ी किरण मोरे सकपकाते हुए उनके पास आए। उनसे पूछा कि खैरियत तो है? पानी वगैरह चाहिए क्या? लेकिन गावस्कर ने उन्हें तुरंत भगाते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि बगैर हेलमेट के इतनी भयंकर गेंद को झेलने वाला खिलाड़ी केवल शरीर से ही नहीं, जज्बे से भी कितना हिम्मती है। इसके बाद वो न केवल मैदान में डटे रहे, बल्कि बगैर आउट हुए 147 रन भी बनाए। इसीलिए उन्हें आज भी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाता है।'

जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। किताबों से मिला ज्ञान जीवन में आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन को बेहतर बनाता है। एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। सुनील गावस्कर को क्रिकेट खेलने के बाद किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो खासकर क्रिकेट और इतिहास से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। आपने क्रिकेट कमेंट्री करते हुए अक्सर उनसे क्रिकेट से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र सुना होगा, ये उनके स्वध्ययन की वजह से ही संभव है। उनकी पसंदीदा किताब दिलीप दोशी की स्पिन पंच और क्रिस रयान का गोल्डन बॉय है, जो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान किम ह्यूजेस के बारे में है।

लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के 50 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने साल 1987 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। उसके बाद से आज भी अलग-अलग भूमिकाओं में क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। गावस्कर आज भी उतने ही जोशीले और ऊर्जावान हैं जितने उस समय थे। वे क्रिकेट के अपने अनुभवों और ज्ञान से विश्व क्रिकेट का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनको नजदीक से समझने वालों का कहना रहा है कि वो हमेशा से ही एक बेहतरीन टीम मेंबर रहे हैं। अपने साथियों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। उनके बुरे दौर में भी उनके साथ रहते हैं। उनका उत्साहवर्धन करते हैं। आज भी समय-समय पर वो टीम और प्लेयर्स को अपने कीमती सुझाव देते रहते हैं।

● **आशीष नेमा**

सफलता के बावजूद डाउन टू अर्थ

अक्सर देखा गया है कि सफलता के साथ लोगों का दिमाग भी आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि चढ़ते हुए सूरज को एक न एक दिन ढलना पड़ता है। सुनील गावस्कर इस बात को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि देश के महान बल्लेबाज होने के बावजूद उनके अंदर कभी घमंड नहीं आया। वो बेहद विनम्र स्वभाव के हैं। ऐसे दौर में जब हर खिलाड़ी की बायोपिक फिल्म बन रही हो, उस वक्त में उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ रोचक नहीं, जिसके आधार पर बायोपिक बनाई जा सके। उन्होंने कहा था, मैं सच में अपने ऊपर बायोपिक के पक्ष में नहीं हूं। मेरा जीवन काफी नियमित है। इसमें कुछ रोचक नहीं। एक दर्शक के तौर पर मैं इसे पर्दे पर देखना भी पसंद नहीं करूंगा। तो फिर लोग क्यों पसंद करेंगे? कई बार लोगों ने मुझसे बायोपिक के संबंध में बात की लेकिन मैं मानता हूं कि मेरा जीवन बायोपिक के लिए रोचक नहीं है। गावस्कर का यही व्यावहारिक ज्ञान आज की पीढ़ी के कई क्रिकेटरों को सीखने की जरूरत है।

अलविदा ट्रैजेडी किंग

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब ने आज भले ही दुनिया को अलविदा कह दिया हो लेकिन उनके ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्हें बॉलीवुड फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे।

पिता नहीं चाहते थे कि फिल्मों में काम करे बेटा, पिटाई के डर से दिलीप साहब ने बदल लिया नाम

दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर, 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। दिलीप साहब के पिता लाला गुलाम सरवर खान और माता आयशा बेगम ने अपने बेटे का नाम यूसुफ खान रखा था। ऐसे में यह जेहन में आता है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार कैसे बने। यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने के पीछे का किस्सा उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत से जुड़ा है। 1944 में फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए इंडियन सिनेमा की पहली स्टार एक्ट्रेस देविका रानी ने यूसुफ खान को दिलीप कुमार के नाम से पेश किया।

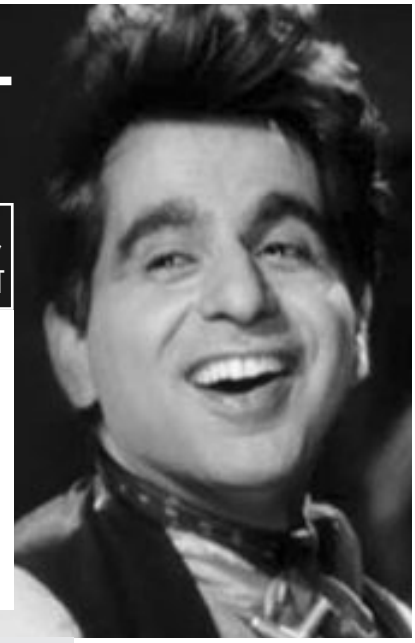

ऑटोबायोग्राफी में दर्ज है नाम बदलने का किस्सा

दिलीप कुमार ने नाम बदलने का किस्सा अपनी ऑटोबायोग्राफी 'दिलीप कुमार: द सबस्टांस एंड द शेडो' में लिखा है। दिलीप साहब ने लिखा– देविका ने मुझसे कहा– यूसुफ, मैं तुम्हें एक अभिनेता के तौर पर लॉन्च करने के बारे में सोच रही हूं और मुझे लगता है कि अगर तुम अपना स्क्रीन नेम बदल लो तो यह कोई बेकार आइडिया नहीं है। एक ऐसा नाम जिससे आप जाने जाएंगे। एक ऐसा नाम जो कि स्क्रीन पर दिखने वाली आपकी रोमांटिक छवि के हिसाब से होगा। मुझे लगता है कि दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। यह मेरे दिमाग में तब आया जब मैं आपके लिए नाम के बारे में सोच रही थी। यह नाम आपको कैसा लगता है? दिलीप कुमार को यह नाम पसंद आया। उन्होंने दिलीप कुमार नाम से फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने का फैसला किया और अपनी बेमिसाल अदाकारी की बदौलत देखते ही देखते दुनिया भर में मशहूर हो गए।

देविका रानी ने दिया था पहला ब्रेक

दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की देन हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। यहीं वे यूसुफ सरवर खान से दिलीप कुमार बने और यहीं उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं। पहली फिल्म ज्वार भाटा (1944) के लिए उन्हें 1250 रुपए मिले थे। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। 1947 में उन्होंने जुगनू में काम किया। इस फिल्म की कामयाबी ने दिलीप साहब को चर्चित कर दिया। इसके बाद उन्होंने शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमति, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, आन, आजाद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

अपने अभिनय से वो स्वतंत्र भारत के पहले दो दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। उन्होंने अभिनय के माध्यम से कई मुद्दों को ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत किया। दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग के साथ ऑलराउंडर एक्टर भी कहे जाते थे। 25 साल की उम्र में वे देश के नंबर वन एक्टर के रूप में स्थापित हो गए थे।

खाली समय में क्रिकेट खेलते थे दिलीप साहब

दिलीप साहब को शूटिंग के दौरान जब भी वक्त मिलता था, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। सोशल मीडिया के जरिए अपनी पुरानी यादों का ताजा करना भी उनका आदतों में से एक था। अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की फिल्मों में लेकर दिलीप कुमार के कैरियर को सही दिशा में आगे बढ़ाया। फिर नौशाद, महबूब, बिमल राय, के आसिफ और दक्षिण के एसएस वासन ने दिलीप के साथ काम कर कई चर्चित फिल्में बनाईं। 44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से शादी करने तक दिलीप कुमार ऐसी कई फिल्में कर चुके थे, जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दिलीप साहब ने अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को पैसा कमाने के लिए कभी नहीं भुनाया।

यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने का एक और दिलचस्प किस्सा

यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। यह किस्सा दिलीप कुमार के डर से जुड़ा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार को पिटाई के डर से नाम बदलना पड़ा था। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने खुद ही यह किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा– मेरे वालिद फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम लाला बंसी नाथ था। इनके बटे फिल्मों में एक्टिंग करते थे। मेरे वालिद अक्सर उनसे शिकायत करते थे कि ये तुमने क्या कर रखा है। तुम्हारा नौजवान और इतना सेहतमंद लड़का देखो क्या काम करता है। दिलीप कुमार ने बताया– मैं जब फिल्मों में आया तो मुझे बहुत खौफ हुआ कि जब उन्हें मालूम होगा, तो वह बहुत नाराज होंगे। मेरी पिटाई भी कर सकते हैं। उस समय मेरे सामने तीन नाम रखे गए। युसूफ खान, दिलीप कुमार और बासुदेव। मैंने कहा कि युसूफ खान मत रखिए, बाकी जो आपके दिल में आए वो नाम रख दीजिए। इसके दो–तीन महीने बाद जब एक अखबार में मैंने इश्तिहार देखा, तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार रखा गया है।

मानव, पहले मानव है?

मानव को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित होकर उसे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। अपने को उच्च और अन्य को हेय मानकर उसे निम्न सिद्ध करने में बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और न जाने कितने मानव विभंजक रूप हैं, जो नहीं चाहते कि दुनिया में शांति रहे। उसे लड़ने-लड़ाने में जो आनंद आता है, वह कहीं भी नहीं मिलता। लड़ाने वाले लड़ाकर आनंद मनाते हैं।

कहा जाता है कि 'मानव पहले पशु है, बाद में मनुष्य।' किंतु हमें इसके ठीक विपरीत ही प्रतीत होता है। अर्थात् 'मानव पहले मनुष्य है, बाद में पशु है।' हो सकता है बहुत पहले जब मानव - सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, अथवा वह अपने शैशव काल में रही होगी, तब मनुष्य, मनुष्य कम; पशु ही अधिक रहा हो। क्योंकि उसका रहन-सहन, आसन, असन, वसन, व्यसन, आहार, निद्रा, देह-संबंध आदि सभी क्रिया-कर्म पशुओं जैसे ही रहे हों, लेकिन शनैः-शनैः विकसित सभ्यता ने उसे पशु से उठाकर मनुष्य की पंगत में बिठा दिया हो। कौवे से हंस, गधे से गाय, बिच्छू से मधुमक्खी, नाली के कीट से फलों की गिड़ार, उल्लू से गरुण, मेंढ़क से घड़ियाल बना दिया हो।

आज मनुष्य पशुओं से बहुत आगे निकल चुका है। अब वह गुफाओं, बिलों और पेड़ों पर अपने घर-घोंसले बनाने के बजाय ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं और बहु मंजिला भवनों में निवास करता है। पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े बेचारे वहीं के वहीं रह गए और वह पशु से मनुष्य बन गया। बंदर आज भी बंदर है, गधा आज भी गधा है, गाय-भैंस आज भी गाय-भैंस ही बने हुए हैं। नाली का कीड़ा आज भी नाली में और सुअर आज भी नाले में किलोलें करते हुए देखे जा सकते हैं। पर वाह रे! मानव, तारीफ है तेरी की तू कहां से कहां पहुंच गया! तू कभी गीदड़ की तरह गुफावासी था, अब महलवासी हो गया। बनैले हिंसक शेर, चीते,भालू आदि से जान बचाने के लिए भय वश तू पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहता था, अब एअर-कंडीशंड कमरों में विलास करता है। अब तू पशु नहीं है, न पक्षी और न ही कोई कीड़ा मकोड़ा। (यह अलग बात है कि कुछ मानव देहधारी प्राणी आज कीड़े-मकोड़ों, कुत्ते, बिल्लियों की जिंदगी से भी बदतर जीवन जी रहे हैं।) आमतौर से मानव तिर्यक और इन यौनियों से बहुत ऊपर जा चुका है।

अब आज का मानव एकता में नहीं, विभाजन में विश्वास करता है। इसलिए उसने वर्ण-भेद, जाति-भेद, भाषा-भेद, क्षेत्र-भेद, प्रदेश-भेद, जनपद-भेद, नगर-ग्राम-भेद और न जाने कितने भेद में विभाजित होकर खंड-खंड होकर जीने को ही सुखी जीवन की आधार शिला माना है। मुंह से एकता, अखंडता, संगठन के गीत गाने वाला मानव इन सब को केवल आदर्श की किताबों, उपदेशों, कविताओं और गीतों में लिखकर रखता है, लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। उसे प्रेम के बजाय लड़ना अधिक पसंद है। तभी तो महाभारत और दो-दो विश्व युद्ध हुए। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में बारूद के ढेर पर बैठकर परमाणु बम बनाकर उस 'शुभ पल' की प्रतीक्षा में उतावली से बैठा हुआ है। खून-खराबा देखने में आनंद लेना, मनुष्य की हॉबी है। तभी तो मरते हुए आदमी को बचाने के बजाय उसके वीडियो बनाना, फोटो खींचना उसे ज्यादा पसंद है। उसे किसी के मरण को अपना प्रिय उत्सव बनाना उसका बहुत ही रोचक कर्म है। कहीं आग लगे, दुर्घटना हो, किसी के प्राण निकलने वाले हों, तो वह सबसे पहले अपना मोबाइल निकालकर पत्रकार की भूमिका में आकर उसे प्रसारित करना अपना धर्म समझता है। उसका यह कृत्य उसे पशुओं से भी बहुत ऊपर उठा देता है।

मानव को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित होकर उसे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। अपने को उच्च और अन्य को हेय मानकर उसे निम्न सिद्ध करने में बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और न जाने कितने मानव विभंजक रूप हैं, जो नहीं चाहते कि दुनिया में शांति रहे। उसे लड़ने-लड़ाने में जो आनंद आता है, वह कहीं भी नहीं मिलता। लड़ाने वाले लड़ाकर आनंद मनाते हैं। 'अति बलशाली 'लड़कर अपनी मनः शांति मनाते हैं, अपने अहंकार में मिट जाना सहर्ष स्वीकार है मानव को, किंतु शांति प्रियता उसे कायरता का पर्याय प्रतीत होती है।

युद्धप्रियता मानव का प्रिय 'खेला' है। यही उसकी प्रियता का मेला है। आखिर मानव भी तो लाल रंग का चेला है। अब वह चाहे साड़ी में हो या मांग में, चूड़ी में हो या दिमाग में, रक्त में हो या अनुरक्ति में (प्रेम में, मनुष्य प्रेम का रंग भी लाल मानता आया है, वही रंग श्रृंगार का भी है।) इसीलिए किसी युग के राजा लोग युद्ध में लाल खून की नदी बहाकर दूसरे राजा की पुत्री या रानी को छीनकर लाल लाल जोड़े में लाल श्रृंगार की लाल-लाल सेज पर सुहाग रात मनाते थे।

'विनाश काले विपरीत बुद्धि' के सिद्धांत का उद्घोषक और मान्यता देने वाला मानव इसके विपरीत चलना ही उचित मानता है। आप तो जानते ही हैं कि इनके सिद्धांत केवल उपदेश, ग्रंथों की शोभा बढ़ाने और दूसरों को बताने, (स्वयं करने के लिए नहीं), अपने धर्म की शेखी बघारने, अपनी अभिजात्यता का डंका पीटने-पिटवाने और प्रदर्शन के लिए ही तो हैं। अब पशु-पक्षी बेचारे क्या जानें ये आदर्शों की 'ऊंची-ऊंची बातें!'

आइए हम सब आपस में लड़ें, कटें, मिटें और पशु-पक्षियों के ऊपर अपने मानव-साम्राज्य की आवाज बुलंद करें। अंततः मानव पहले मानव है, बाद में पशु भी हो सकता है। जब मानव होने पर उसका ये हाल है, तो पशु होने पर क्या हाल होगा, कल्पनातीत है। भले ही वह कोयल के कलरव, मोरों की मेहो! मेहो!! गौरैया की चूं-चूं, कौवों की कांव-कांव, शहर-शहर या गांव-गांव में कोई भी उसे सुनने मानने वाला न हो।

इसीलिए तो हमने कहा कि 'मानव पहले मानव है, बाद में पशु।'

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

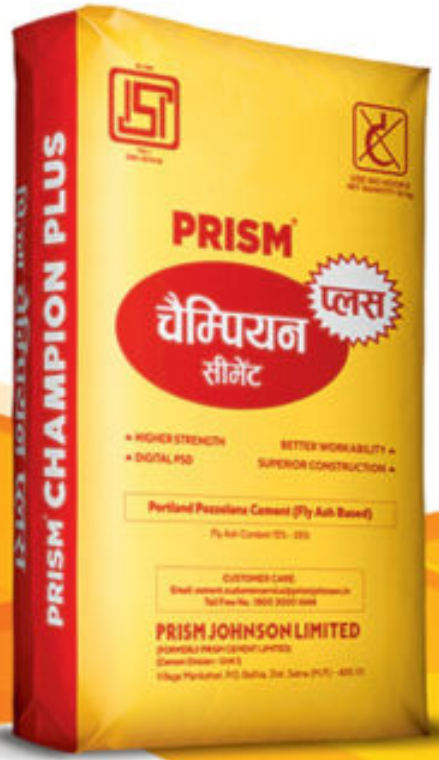

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

BC-20s

Auto Hematology Analyzer

Minimum Size,
Maximum Capability

mindray
healthcare within reach

Science House Medicals Pvt. Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687